

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 24 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 2-00 बजे हुई। अध्यक्ष (रघुबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सवाल जवाब होंगे।

separate division/sub division for Meham constituency

960 sh. Anand singh Dangi : Will the Irrigation Minister be Pleased to state:-

(a) Whether it is a fact that the area of Meham constituency falls in three divisions i.e. Rohtak, jind and Bhiwani due to which the farmers under consideration of the Government to form a separate division or sub Division for whole of the area of the Meham Constituency; and

(b) if so, the time by which such a proposal is likely to be materialized?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला)

(क) मदीना जल सेवाएं उपमंडल रोहतक का मुख्यालय महम में स्थानान्तरित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन

है। तदानुसार, बोन्द जल सेवाएं मंडल, भिवानी तथा जल सेवाएं मंडल, भिवानी के कुछ क्षेत्र जोकि महम निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है, को भी प्रस्तावित महम उपमंडल के साथ संयोजन करने को भी प्रस्तावना है।

(ख) महम में उपमंडल जून, 2008 में खोले जाने की संभावना है।

श्री आनंद सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मदीना जल सेवाएं उपमंडल रोहतक का मुख्यालय महम में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव लगभग मान लिया है। अध्यक्ष महोदय, महम हल्के के किसानों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि महम हल्का तीन डिवीजनों में बंटा हुआ है। महम हल्के का कुछ एरिया भिवानी में, कुछ एरिया जींद में और कुछ एरिया रोहतक में पड़ता है जिससे किसानों को अपने काम-का- के लिए आने जाने में बहुत असुविधा होती है। इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि महम निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी माईनर्स हैं, वे जितने भी डिवीजनों और सब-डिवीजनों में पड़ते हैं उनको एक डिवीजन में जल्दी से जल्दी कर दिया जाये ताकि वहां के किसानों को समस्या न हो। मंत्री जी ने अपने जबाव में जहां संभावना भाब्द का इस्तेमाल किया है इसकी जगह वे आभासन दें कि महम हल्के के सभी माईनर्स को एक डिवीजन में कर दिया जाएगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि नहर विभाग निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर डिविजनों का गठन नहीं करता। लेकिन एक स्पेसिफिक केस में माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि नहर विभाग की पोलिसी यह है कि एक सब-डिवीजन या डिवीजन का कंट्रोल हैट से लेकर टेल तक एक ही डिवीजन या सब डिवीजन के पास रहे। यह सरकार की मूलभूत नीति है। लेकिन मेरे माननीय साथी के क्षेत्र के अंदर जो इलाका पड़ता है उसमें कई माईनर्स हैं जिनकी टेल इनके यहां आकर खत्म हो जाती है और उनका कंट्रोल भी भिन्न-भिन्न डिविजनों में होने की वजह से दिक्कत आ रही है। इसलिए निर्णय लिया है कि महम हल्के के लिए अलग से डिविजन बनाया जाएगा जिसके बारे में मैंने अपने जबाव में भी चर्चा की है। जहां तक माननीय साथी ने संभावना भाब्द की बात की है इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इसको यथार्थ में बदला जाएगा।

श्री आनंद सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, माननीय बिजली मंत्री जी ने जो बताया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि महम हल्के में केवल दो माईनर्स ऐसे हैं जिनका हैड किसी दूसरे हल्के में पड़ता है जिनका सब डिवीजन जुलाना है। दो माईनर्स के अलावा जितने माईनर्स हैं उनके हैड और टेल महम हल्के में ही पड़ते हैं इसलिए जल्दी से जल्दी वहां अलग से डिवीजन बनाया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जैसा की मैंने अपने जवाब में बताया है कि हम आलरैंडी डिवीजन बनवा रहे हैं और जो सीमित समय दिया है उस समय सीमा तक काम पूरा कर दिया जाएगा।

श्री भिव भांकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महम के लिए डिवीजन बनाने पर बोन्ट जल सेवाएं भिवानी तथा जल सेवाएं मंडल, भिवानी का हैडक्वार्टर भिवानी में ही रहेगा या भिष्ट कर दिया जायेगा। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि बोन्द जल सेवाएं, भिवानी तथा जल सेवाएं मंडल, भिवानी का हैडक्वार्टर भिवानी में ही रहे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी की चिंता वाजिब है लेकिन हमने पहले से ही सुनिश्चित किया है। मेरे माननीय साथी प्रभन के जवाब को पढ़े उसमें लिखा है कि उसके कुछ क्षेत्र निकाले जायेंगे मगर हैडक्वार्टर नहीं बदल जायेगा। मैंने अपने जबाब में कहा है कि तदानुसार, बोन्द जल सेवाएं मंडल , भिवानी, तथा जल सेवाएं मंडल भिवानी के कुछ क्षेत्र जोकि महम निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है उनको अलग करेंगे। हम माननीय साथी का इलाका नहीं बदल रहे हैं और न ही हैडक्वार्टर बदल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें इनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आयेगी। यह एक कोपरेभानल बात है जो सरकार की समझ में आई है इसलिए इसको कियान्वयन किया जा रहा है।

श्री रणबीर सिंह महेंद्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पहले बोंद डिस्ट्रीक्टूटरी और भिवानी सब-डिवीजन है वे वहीं रहेंगे या बदल दिये जाएंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य श्री भारद्वाज के जबाव में भी बताया है। मैं माननीय सदस्य चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा जी को भी आभवस्त करना चाहूंगा कि जो एगजिस्टिंग सब-डिवीजनस और डिवीजनस हैं उनमें हम केवल इतना ही परिवर्तन कर रहे हैं कि जहां पर टैल्स और हैडस हैं वे महम के क्षेत्र में पड़ते थे और इनके साथ जोड़ने से ऑपरेभान प्राब्लमज थी इसलिए केवल उस इलाके को ही हम निकाल रहे हैं। इसके अलावा न तो हम डिवीजनस खत्म कर रहे हैं और न ही बदल रहे हैं।

Inspection of Jails

*860 Dr. Sita Ram: Will the Chief Minister be pleased to state the total number of jails in the state togetherwith the total number of inspecitions/raids conducted by concerned authorities of state and the unlawful activites noticed or material seized in such inspection/raids since april 2007 till date?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): दिनांक 1-4-2007 से 29-2-2008 की अवधि के दौरान राज्य की विभिन्न जेलों पर भिन्न-भिन्न अथॉरिटी द्वारा 464 निरीक्षण जेल विजिट

की गई। इन निरीक्षणों के दौरान कई अनियमितताएं नोटिस में आईं और जहां आवश्यकता हुई वहां कानूनी व अनुभासनिक कार्यवाही की गई। इस अवधि के दौरान राज्य की विभिन्न जेलों पर निरीक्षणों के दौरान 39 मोबाईल फोन बरामद हुए। अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे पास 19 जेल हैं जिनमें 2 सैन्ट्रल जेल भी शामिल है। यह 19 जेलों का जिक्र जो हमने जो जबाव दिया है उसमें होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसके लिए मैं आपके माध्यम से समद से और आपसे क्षमा याचना करता हूँ।

डा. सीता राम: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सरकार के नोटिस में है कि जेलों के अन्दर से अपराधियों ने अपराधिक गतिविधियां चलाई हुई हैं और लोगों से फिरौतियां भी मांगी जा रही है। इसके अलावा क्या हरियाणा प्रदेश को सभी जेलों के अन्दर सेलफोन आपरेट न हो सके इसके लिए सेलफोन जैमर्ज लगाये जा रहे हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं अपने काबिल दोस्त की तारीफ करूंगा कि कम से कम उन्हें प्रदेश की कानून व्यवस्था की चिंता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था हो इसके लिए प्रदेश के हर काबिल नागरिक को इसकी चिंता करनी चाहिए ताकि प्रदेश के अन्दर और जेल के अन्दर या बाहर से कोई भी अपराध न हो। न प्रदेश के मुखिया, न प्रदेश के मुखिया के बेटे का, न ही प्रदेश के किसी और व्यक्ति का संरक्षण

हो। अध्यक्ष महोदय, रोहतक की जेल का उदाहरण आपके सामने है क्योंकि रोहतक आपका पुराना जिला रहा है। एक समय में ऐसा हुआ करता था और यह सर्वविदित भी है कि कृष्ण पहलवान से जेल के अन्दर मिलने कौन जाया करता था और जेल के अन्दर से किस प्रकार से फिरौती मांगी जाती थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के आदेशानुसार हमने राज्य के कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, भिवानी, कैथल और गुड़गांव में स्थित जेलों में मोबाईल फोन जैमर्ज लगाये हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिए हैं कि जिन जेलों में अभी तक मोबाईल फोन जैमर्ज नहीं लगाये गये हैं उनमें भी जल्दी से जल्दी मोबाईल फोन जैमर्ज लगाये जायें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक मोबाईल फोन जैमर्ज लगाने पर 45 से 50 लाख रुपये की राशि खर्च होती है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि चाहे ये मोबाईल फोन जैमर्ज कंपनियों के माध्यम से लगवाये जायें चाहे सरकार अपने खातों में से यह पैसा दे और जिन जेलों में मोबाईल फोन जैमर्ज नहीं लगे हैं उनमें भी मोबाईल फोन जैमर्ज लगाये जायें। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही माननीय सदस्य की चिंता से अपने आप को जोड़ते हुए मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कई ऐसे कुख्यात अपराधी भी थे जब उन्हें कई बार पेनी पर ले जाया जाता था तो कई वारदातें हुआ करती थीं। कई बार ऐसा हुआ कि बंगलोर से कुख्यात अपराधियों को जो किसी अगुवाई के काण्ड के अन्दर

संलिप्त थे डबवाली के अन्दर मुकद्दमें दर्ज करके लाये गये और अगले दिन फरार हो गये और फिर वर्षों तक वे एक पूर्व मुख्यमंत्री के फार्म पर रहे। इसकी बाकायदा वीडियो रिकार्डिंग भी है। इसलिए यह भी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सुनिश्चित किया और उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट चलाया जिसकी कुल लागत होगी 1375 लाख रुपये और इसके तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिन जेलों में बहुत डेंजरस प्रिजनर्स हैं जिनसे पूरी सोसायटी को खतरा है और ट्रांजिट से कहीं वे भाग न सके और कोर्ट के अन्दर भी कोई वारदात न हो तो उसके लिए सरकार ने यह किया है कि उनकी गवाही भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वहीं पर हो सके और इसके लिए हमने टैण्डर्ज भी फाईनालाईज कर लिए हैं और इसके लिए हम 25 स्टूडियोज मुखतलिफ जेलों में बनायेंगे और 30 वीडियो स्टूडियोज हरियाणा की अदालतों के अन्दर बनायेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर अनुमानतः 1375 लाख रुपये की लागत आयेगी। इस सारी प्रक्रिया को भी इस वर्ष के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा। इस बात को लेकर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार बहुत चिंतित है। सवाल के जवाब में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 464 इंसपैक्टान्स किये गये। ये 464 इंसपैक्टान्स इस बात को दर्शाते हैं कि सरकार इस मामले में कितनी गम्भीर है। जहाँ-जहाँ लोग दोषी पाये गये, चाहे वे सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वे कैदी थे, जहाँ-जहाँ कानून का उल्लंघन हुआ है वहीं पर हमने कड़ी कार्यवाही की है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि जैमर्स लगाये गये हैं लेकिन जैमर्स लगे होने के बावजूद भी अभी तक जेलों में सैलफोन ऑपरेट हो रहे हैं। वे किस की मिलीभगत से हो रहे हैं? क्या जेल अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे हैं? क्या सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह स्वाभाविक है कि जहाँ-जहाँ जैमर्स लगे हुए हैं, वहाँ जैमर्स लगने के बाद सैलफोन पर किसी प्रकार का कोई सिगनल नहीं आना चाहिए। जैमर्स लगाये ही इसलिए जाते हैं कि किसी प्रकार का कोई सैलफोन सिगनल न आये। जहाँ तक कार्यवाही का प्र न है, अध्यक्ष महोदय, सोनीपत में हमने इस बारे में एफ०आई०आर० दर्ज करवाई है। एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और दो अधिकारियों को वहाँ से ट्रांसफर कर दिया है। इसी प्रकार से एक और वाकया कुरुक्षेत्र में हुआ था। वहाँ पर भी हमने धारा 221, 120 of Section 54 of Prisons Act के तहत एफ०आई०आर० दर्ज करवाई है। गुड़गांव में भी एफ०आई०आर० नं. 511, दिनांक 29.12.2007 को दर्ज करवाई गई है। ऐसी सब जगह जहाँ हमने एफ०आई०आर०

दर्ज करवाई हैं वहाँ जो भी दोषी पाया जायेगा चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कैदी हो, उन सबसे सख्ती से निपटा जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आ वस्त

करना चाहूंगा कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार इस बात को लेकर बहुत चिंतित और गम्भीर है कि एक भी दोषी व्यक्ति जो समाज और प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए खतरा है उसके लिए हरियाणा में ढिलाई की कोई जगह नहीं होगी। इसी वजह से 1999 से 2005 के बीच में जो लोग सरकार के संरक्षण के अन्दर सैलफोन ऑपरेट करते थे, आज वे लोग हरियाणा को छोड़ कर भाग चुके हैं या जेलों की सलाखों के पीछे हैं और उनकी जगह भी वहीं पर है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पुराने समय की बात की है लेकिन मैं मो इस समय की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र की जेल के बारे में आई०जी० प्रिजन का स्टेटमेंट आया था कि कुरुक्षेत्र जेल से 2007 में ही फिरौती मांगी गई थी। मेरा दूसरा यह है कि जो जैमर्ज लगाये गये हैं क्या वे सभी कम्पनियों के सैलफोन को जाम कर सकेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, दो पृथक प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछे हैं। कुरुक्षेत्र की जेल के मामले को लेकर हमने पुलिस स्टेशन थानेसर में ऐरिंग ऑफिशियल्स के खिलाफ एफ०आई०आर० नं० 22, दिनांक 17.1.08 को अंडर सैव इन 221,120 बी० ऑफ सैव इन 54 ऑफ द प्रिजन एक्ट, 1894 के तहत दर्ज करवाई हैं। इन सबके खिलाफ एक्शन लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक जैमर्ज का प्रश्न है, जैमर जेल

में सिगनल को जैम करता है न कि कम्पनियों के सैलफोन को जैम करता है। जो भी जैमर्ज लगायें गये हैं और जिन जगहों पर लगाये जाने हैं वहाँ पर भी हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर प्रकार के सैलफोन का सिगनल जैम हो। अगर फिर भी माननीय सदस्य को किसी विशेष कम्पनी का सिगनल पकड़े जाने की शिकायत मिली हो तो वे माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखकर भिजवा दें, हम यह सुनिश्चित कर लेंगे और जैमर्ज को रिचैक भी करवा लेंगे।

श्री नरेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि जेलों के अन्दर से फिरौती की बात होती थी उसके बारे में मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह काम ज्यादातर वर्ष 2000 से 2005 के भूख तक होता रहा है। उस पीरियड की स्थिति क्या है, कितने लोगों को ऐरैस्ट किया गया, कितने लोग विदेशों में हैं और कितने लोग देश में हैं, क्या मंत्री जी इसका ब्यौरा देंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छी बात कही है। इस बात को पूरा प्रान्त जानता है और यह बात सर्वविदित भी है कि एक समय ऐसा था जेल के अन्दर जो अपराधी थे वे सैलफोन ऑपरेट करते थे और सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त था। कृष्ण पहलवान की मैंने चर्चा भी की। अध्यक्ष महोदय, यह आपका पुराना जिला भी रहा है इसलिए यह आप भी जानते हैं कि उस समय के मुख्यमंत्री और उसके बेटे

रोहतक की जेल में कृ ण पहलवान से मिलते जाते थे। इसी प्रकार से डिम्पी, जिसकी बाद में चण्डीगढ़ में हत्या कर दी गई थी उनको एक केस में प्रोडक् ान वारन्ट लेकर डबवाली लाया गया था और फिर वहां से उसको भगा दिया गया था। वह पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पर भी रहा। इसके पक्के सबूत भी हैं। अब तो उसकी हत्या कर दी गई है। इसी प्रकार से और बहुत सारे अपराधी थे। स्पीकर सर, जिस दिन चौधरी भूपेन्द्र सिंह की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में अपना कार्यभार सम्भाला उसके 24 घण्टे के भीतर ही वे सभी अपराधी तड़ीपार हो गये थे और हरियाणा की सीमा से बाहर चले गये थे। या तो वे जेलों की सलाखों के पीछे हैं या फिर उनसे हरियाणा छुड़वा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था वे कुख्यात अपराधी 40 के करीब थे जो पुलिस के साथ एनकाउंटर के अन्दर मारे गए हैं जिन्होंने कई काण्ड किये थे और पुलिस पर हमला कर गुण्डागर्दी की को ि ा की। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार की नीति पुर्णतया स्पष्ट है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटों के बारे में माननीय मन्त्री महोदय बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। जो प्र ान मैंने पूछा है वह वर्ष 2007 के बारे में है। Jail is becoming safe and heaven for criminals. हमारी सरकार के समय की बात नहीं है बल्कि वर्तमान सरकार के समय की बात है।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें पूछे गये सवाल का पूरा जवाब नहीं आया है। सवाल यह था कि कितने कुख्यात अपराधी जेलों से टेलीफोन किया करते थे, फिरौतियां मांगते थे? अध्यक्ष महोदय, सुरजेवाला साहब ने केवल दो आदमियों के नाम लिये हैं, कृ ण पहलवान और डिम्पी। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे और लोग भी हैं? उनके नोटिस में कितने ऐसे अपराधी थे और वे अपराधी किस-किस के साथ जुड़े हुए थे ? यह सारी बात क्लीयर हो जाए कि कौन-कौन आदमी थे ओर किस-किस से जुड़े हुए थे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े स्पष्ट तौर पर जवाब दिया है। जहां तक माननीय सदस्य का प्र न हैं, मैंने पूरी जानकारी और वस्तुस्थिति से सदन को अवगत करवा दिया है कि वे किस के बेड़े के अन्दर बैठते थे। मैं माननीय सदस्य को बता देता हूं कि वे चौटाला साहब के बेड़े में बैठते थे और उनके फार्म हाउस के अन्दर बैठते थे यह बात सब लोग जानते हैं। उनकी वीडियो सी०डी० और फोटो भी है जिसमें डॉ० सीता राम जी भी बैठे हुए हैं। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैंने इन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है इसलिए यह उसको व्यक्तिगत तौर पर न ले (विधन) अध्यक्ष महोदय, डॉ०सीता राम जी के बारे में यह कोई टिप्पणी नहीं थी और न ही उनके बारे में इल्जाम है कि इनके किसी अपराधी से सम्बन्ध हैं इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा

कि वे व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही अच्छे और सज्जन आदमी हैं इनके आगे जो बैठते हैं वे उनके साथ बैठे हुए थे वे गलती से उस फंक्शन में गए हुए थे। (विधन)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पब्लिक प्लेस को व्यक्तिगत तौर पर न लें। अपराधी किस्म के लोगो से हमारा कोई नाता नहीं है। पब्लिक मीटिंग में कोई भी किसी भी किस्म का व्यक्ति बैठा हुआ हो सकता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, उनके इनकी पार्टी के लोगो के साथ सम्बन्ध थे। माननीय सदस्य बहुत ही अच्छे और सही आदमी हैं इनके आगे जो बैठे हैं ये उनको पहचान सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठने से पहल आगे—पीछे देखना पड़ता है।

श्री राधे याम भार्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय बड़े अथॉरिटी से कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटों का संरक्षण उनको प्राप्त था। क्या उनके खिलाफ माननीय मन्त्री जी कार्यवाही करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के गठन के फौरन बाद ही चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की

सरकार आने के बाद एक कॉप्रहेंसिव चार्ज गिट बनाई गई है जिसमें जिन लोगों का अपराधियों से लिंक हैं उसका एक पूरा चैप्टर उसके अन्दर है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने वह चार्ज गिट केन्द्रीय जांच ब्यूरो के हवाले कर दी है जिस पर इस समय जांच चल रही है।

डॉ० सु गील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जेल के बारे में इन्होंने कहा कि 464 जेलों का निरीक्षण हुआ और जेलों के निरीक्षण के दौरान इन्होंने स्पष्ट रूप से माना है कि अनियमितताएं हुईं। सरकार की तरफ से भी इस बात को माना गया है कि अनियमितताएं हुई हैं। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अगर अनियमितताएं हुई हैं और वर्तमान सरकार ने अपनी इस असफलता को माना है तो क्या वर्तमान मन्त्री और मुख्यमंत्री जी उन उच्च अधिकारियों जिनकी अनियमितताओं में सलिप्तता पाई गई है, उनके खिलाफ भी इन्कवायरी कावांगें ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया है कि स्पैसिफिकली प्र न यह था कि क्या कोई सैलफोन का यूज जेलों में मिला है, मैंने इसके जवाब में कहा है कि 'हां'। 3-4 जेलों के अन्दर जहां-जहां सैलफोन का यूज मिला है और जिस-जिस से मोबाईल रिकवर हुए हैं, उसके बारे में हमने जवाब में लिख दिया है कि उन सबके ऊपर एफ०आई०आर० दर्ज करवाई

गई है जो ऑफिशियल दोषी पाए गए हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है और यदि उन्होंने कोई कोताही की है तो उनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करवाई गई और डिसीप्लिनरी एक्शन भी लिया गया है। जो इस सरकार के आने से पहले अनियमितताएं हुई हैं उस बारे में सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टीगेशन एजेंसी इन्कवायरी कर रही है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि सदन में चर्चा हो रही है इस बारे में सबको मालूम है कि उस समय ऐसे अपराधियों को छोड़ा गया था जो कि कातिल थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के द्वारा उन अपराधियों को दोबारा से जेलों में ठोका गया। जब हमारी सरकार बनी और बनते ही मैंने जो पहली प्रेस कांफ्रेंस की थी, उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जो भी अपराधी किस्म के तत्व हैं वे या तो मुख्य धारा में आ जाएं या भारत छोड़ कर चले जाएं।

श्री अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया उस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के वक्त में जिन्होंने अपराध किए थे उनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की जाती थी। उस वक्त की सरकार में जो बदमाश थे वे लोगों के ट्रैक्टर, मोटर साइकल और ट्रक आदि की चोरी कर लेते थे और जब लोग थानों में उनके खिलाफ अपनर एफ०आई०आर० दर्ज करवाने जाते थे तो उनकी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की जाती थी। जब अधिकारियों से इस

बारे में कहा जाता था तो वे कहते थे कि हमें ऊपर से आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त की सरकार की मं ता थी कि अगर एफ०आई०आर० दर्ज नहीं होगी तो उनके वक्त में क्राईम का ग्राफ बहुत नीचे आ जाएगा। लेकिन उनके इस अलिखित आर्डर की वजह से हमारे लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जिल लोगों की जो मोटर साईकल, ट्रक और ट्रैक्टर चोरी हुए हैं उनको आज भी डर है कि कहीं वे बदमा ता लोग चरस, अफीम आदि की तस्करी न करते हों या वे अपराधी लोग किसी को उनकी गाड़ियों के नीचे कुचल कर मार न दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बात कहते हुए जो चिन्ता जाहिर की है वह बहुत ही वाजिब है। पिछली सरकार के पांच वर्षों के राज में यह अलिखित हिदायतें थी कि कोई भी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं करी जाए ताकि क्राईम की फीगर को फर्जी करके दिखाया जा सके। जब मौजूदा कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तब हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यह स्पष्ट तौर पर सभी को कह दिया था कि किसी पर कोई दबाव नहीं है और अगर कोई कॉग्नीजेबल अफैस है तो उसकी एफ०आई०आर० जरूर दर्ज करे। यह हमारी सरकार की डिक्लेयरड नीति है कि जहां कहीं भी कॉग्नीजेबल अफैस होगा वहां पर हम पर्चा दर्ज करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह कहना चाहूंगा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई ि ताकायत या दरखवास्त लेकर आएगा हम

उसको एग्जामिन करवा लेंगे। अगर इनके क्षेत्र के लोगों की तरफ से लिखित में उस बारे में कोई शिकायत हमारे विधायक साथी के पास है तो ये हमें दे दें, उस बारे में हम एफ०आई०आर० भी दर्ज करवा देंगे।

श्री अर्जन सिंह : धन्यवाद जी।

To Develop a House Board Colony

***942. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a Housing Board Colony at Circular Road, Bhiwani near Dadri gate?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Yes sir.

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, भिवानी सर्कुलर रोड के पास हाऊसिंग बोर्ड कालोनी बनने जा रही है। लेकिन उस कालोनी के साथ ही बाल्मिकि बस्ती है। वह बस्ती वहां पर बहुत सालों से बनी हुई है और वहां पर बहुत सालों से गरीब लोग रह रहे हैं। अगर यह हाऊसिंग बोर्ड की कालोनी उस बस्ती से सट कर बनती है तो वहां से जो रास्ता निकलता है वह अवरूद्ध हो जाएगा। इसकी वजह से वहां पर न तो पानी की ओर न ही सीवरेज की लाइन डाली जा सकेगी और वे लोग वहां पर अपनी वह ईंटों का ट्रक भी नहीं ले जा सकेगा। इस हाऊसिंग बोर्ड की कालोनी बनने की वजह से लोगों के लिए वहां पर कोई

भी रास्ता नहीं रहेगा जिससे उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या सरकार उन बाल्मिकि बस्ती वालों के लिए 20 या 25 फुट चौड़ा रास्ता वहां पर छोड़ेगी ताकि उन लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े ? इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में दूसरा प्रश्न लाना चाहूंगा कि भिवानी में नई और पुरानी जो हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनिज हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए वहां के लोगों का मत है कि अगर यहां पर भी यह कॉलोनी बन कंजै तो ठीक है। क्या मंत्री जी इस कॉलोनी को भिवानी के बाहर जहां बहुत सी जमीन खाली पड़ी हुई है वहां भिवानी के लोगों की बहुत बड़ी तकलीफ है। अगर यह कॉलोनी भिवानी से बाहर बन जाए तो इससे वहां के लोगों की तकलीफ दूर हो जाएगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो पृथक प्रश्न पूछे हैं। इनका पहला प्रश्न बाल्मिकी बस्ती को लेकर है। यह प्रश्न इनका सीधा मेन प्रश्न से जुड़ हुआ नहीं है इसलिए माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर भिजवा दें। मगर मैं इनको आश्वासित करना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार की नीति इस बारे में बड़ी स्पष्ट है कि हमारे गरीब भाईयों की जो बस्तियां हैं उनका रास्ता कोई रोक न पाए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी बस्तियों का वाजिब रास्ता जरूर रहे। हम यह बिल्कुल नहीं होने देंगे कि ऐसी कोई बस्ती भी हरियाणा में हो जिसके लिए कोई रास्ता न हो। यह असंभव है। यह हम पहले

सुनिश्चित कर लेंगे कि हम कितने फुट रास्ता छोड़ सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह मामला महकमा ऐग्जामिन कर लेगा और जो रीजलेबल चौड़ाई का रास्ता होगा वह हम छोड़ेंगे। जहां तक इनका दूसरा प्रश्न है इन्होंने यह पुछा है कि क्या इसकी लोकेशन चेंज करने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 11.44 एकड़ यानी तकरीबन साढ़े ग्यारह एकड़ जमीन हाऊसिंग बोर्ड ने हरियाणा हैंडलूम एंड हैन्डीक्राफ्ट कोरपोरेटन से दिसम्बर 2006 में ली थी। इसमें 144 लो-इन्कम ग्रुप, 200 मीडियम इन्कम ग्रुप, और 140 हाई इन्कम ग्रुप डबल स्टोरी हाउसिंग को बनाने के लिए हमने यह स्कीम प्लोट की थी। यह स्कीम 2 जुलाई, 2007 से लेकर 31 जुलाई, 2007 तक थी। हमें इसका ओवरवेलमिंग रिसर्पोस भी मिला था। हमने इसका ड्रा जनवरी, 2008 में निकाल भी दिया है। यह स्कीम पूरी है। इस स्कीम के तहत 1910 लाख रुपये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग पर खर्चा आएगा। और 553 लाख 76 हजार रुपये का खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पर आएगा। Everything stands sanctioned. Sir, We have also proposed to complete this Scheme by May, 2009. So, location cannot be changed at this juncture.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की एक नीति है कि बड़े-बड़े भाहरों में जहां आवकता है वहां चाहे-इन्कम ग्रुप्स हों, चाहे मीडियम इन्कम ग्रुप्स हों या चाहे लो-इन्कम ग्रुप्स हों, उनके लिए आवास बोर्ड या अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से आवास की व्यवस्था की जाएगी। यह हमारी

सरकार की नीति है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आवासीय बोर्ड और प्राईवेट को-ओपरेटिव सैक्टर भी जिन जिन भाहरों में बहुत ज्यादा आबादी बढ़ी है विशेषकर फरीदाबाद में वहां पर आवकता की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं लेकिन फरीदाबाद की स्थिति के बारे में मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात लानी होगी कि वहां पर तकरीबन तीस हजार से भी ज्यादा झुग्गी झोंपड़ी डिवैल्प हो गयी है। यह उनके लिए तो तकनीक है ही साथ ही बाकी भाहर के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए आवासीय बोर्ड या दूसरी एजेंसीज के माध्यम से एकमुक्त तौर पर लो इन्कम ग्रुप्स के लिए अलग कॉलोनीज की व्यवस्था सरकार करेगी ताकि समस्या का समाधान हो सके ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आगियाना किसी भी व्यक्ति को देना खास तौर से इस प्रान्त में देना इस सरकार की प्राथमिकता का केन्द्र बिन्दु है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में भी हाऊसिंग बोर्ड की तरफ से 809 डुपलैक्स टाईप हाउस और 27 हाउस चार स्टोरीज के लिए प्लोट करने जा रहे हैं ओर प्लोट की प्रक्रिया भी इस समय प्रोग्रेस में है अध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा में इस समय भिन्न भिन्न भाहरों में 4384 मकान बनाए जा रहे हैं। और इन पर 457 करोड़ 2 लाख रूपये खर्चा होगा। जहां तक झुग्गी झोंपड़ियों के लिए आवासीय योजना बनाने का

प्र न है, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इनका यह एक पृथक प्र न है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम या दूसरे अन्य प्रोग्राम्ज जैसे जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मि ान के तहत 100 करोड़ रूपयों की राशि भारत सरकार से फरीदाबाद के लिए मंजूर हो चुकी है। इसके अलावा इस प्रकार की अन्य हरियाणा सरकार की स्कीम्ज और भारत सरकार की भी जो स्कीम्ज हैं, उनमें भी हम इन सारी अनपेक्षित सदस्य अपना सुझाव इस बारे में लिखकर भिजवा दें, हम उस पर गंभीरता से विचार कर लेंगे।

श्री नरे ा यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीयस मंत्री जीह से जानना चाहता हूँ कि यह जो हाउसिंग बोर्ड का कार्यक्रम बना है यहद तो बहुत अच्छी स्कीम बनी है इससे प्रन्येंक गरीब आदमी को भी मकान मिल जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जमीन ऐक्वायर करने में प्रौब्लम आएगी और उसमें 1-2 साल लग जाएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि जहा पर आर जोन में जमीन नहीं है वहा ंपर प्राइवेट लोगों से जमीन लेकर गरब लोगों के लिए मकान बनाने का प्रावधान करेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड अपने सीमित साधनों के अंदर फ्लैट बनाता है जैसा हमने भिवानी में किया है। वहां हैंडलूम कॉर्पोरे ान से हमने जमीन 10 लाख रूपये प्रति एकड़ के भाव से ले ली है। इसी प्रकार से जहां जमीन ऐक्वायर करने की जरूरत पड़ेगी, वहां फ्लोर रेट नीति बड़ी

स्पष्ट है। परन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस सरकार के गठन के बाद इस समय जो स्कीम हमारे अंडर कंसीड्रेड हैं वह पंचकुला में 170 मकान की, कुरुक्षेत्र में 300 मकान ट्रिपल स्टोरी और करनाल में 195 ट्रिपल स्टोरी, सोनीपत में 112 ट्रिपल स्टोरी और 544 डबल स्टोरी, मतलौडा में 82 सिंगल स्टोरी, बहादुरगढ़ में 354 ट्रिपल स्टोरी और 89 सिंगल स्टोरी, भिवानी में 490 दो मंजिल, गुड़गांव में 259 नाइन मंजिल और 404 ट्रिपल स्टोरी, धारूहेड़ा में 552 डबल मंजिल, फरीदाबाद में 809 डुप्लैक्स और 27 मकान फोर स्टोरी बना रहे हैं। इसके अलावा हुडा के साधन सीमित हैं क्योंकि हुडा कर्वआउट करके जमीन देता है फिर भी उन्होंने बहादुरगढ़ में 6.7 एकड़, हिसार में 18 एकड़ जमीन कालोनी बनाने के लिए दी, जींद में 10 एकड़, कैथल में 7.5 एकड़ जमीन, सिरसा में 22.7 एकड़ जमीन और एच.एस.आई.डी.सी. बावल में 5 एकड़, गढी में 10 एकड़ जमीन दी है और इसमें हम हाउसिंग कालोनीज विकसित करेंगे और अध्यक्ष महोदय, जहां जरूरत पड़ी, वहां ऐक्वायर भी करेंगे।

श्री बचन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 11 जून, 2006 को सफीदों में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और हुडा सैक्टर की घोषणा करके आए थे और उस पर अमल भी हुआ। वहां पर 7,8 और 9 सैक्टर की घोषणा कर दी गई और सैक्टर 1-4 के तहत नोटिस भी लगा दिया गया। उसके बावजूद

भी वहां एस.डी.एम और अन्य उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई और उन्होंने रिपोर्ट दी कि सैक्टर-7 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बननी चाहिए। क्या मंत्री जी इस बारे में जानकारी देंगे कि डेढ़ साल से ज्यादा समय बीत गया है लेकिन हाउसिंग बोर्ड कालोनी जो कि वहां के लोगों की मांग है, नहीं बनी है।

Mr.Speaker : It is very difficult to reply.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि अगर वहां पर मांग है, सफ़ीदों क्योंकि ग्रोइंग भाहर है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुडा वहां जैसे ही अधिग्रहण समाप्त कर लेगा, वहां हुडा से जमीन अलॉट करवा के उसी लॉट में प्रयास करेंगे कि वहा भी हाउसिंग बोर्ड कालोंनी बनाई जाए। इस बारे में यदि मुख्यमंत्री जी ने घोशणा कर दी है तो अब तो यह हमारे लिए कानून कीतरह है और उसे हम जरूर लागू करेंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि तीन चार साल पहले करनाल में हाउसिंग बोर्ड का एक एस्टेट मैनेजर कोई गौतम था जिसने कि बहुत बड़ा स्कैंडल किया था। उसने वहां हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट बुक किए और लोगों से फुल एंड फाइनल पेमेन्ट ले ली। उसने एक जाली रसीद बुक भी छपवा रखी थी, उससे रसीद भी काटकर देता गया। मैं मंत्री जी सेयह नही जानना चाहूंगी कि उस

कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, किन्तु यह अब य जानना चाहूंगी कि जिस भोलीभाली जनता ने यह समझकर कि सरकारी अफसर है, पैसे जमा करा दिए, फुल एंड फाइनल पेमेन्ट जमा करा दी क्या उनको सरकार द्वारा प्लॉट दिये जाएंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक पृथक प्र न है इसलिए इस समय मेरे पास इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्या को यह जरूर कहना चाहूंगा कि आप इस बारे में हमें लिखकर भिजवा दें। पूरी जानकारी सहित मैं उतर भेज दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कोई प्राईवेट आदमी सरकार के नाम पैसा लेकर ठगी करता है तो सरकार उस पैसे को रिफण्ड कैसे करें। भायद यह संभव नहीं है। भायद माननीय सदस्या भी इस बात से सहमत होगी।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह गवर्नमेंट एम्पलाई था।

Sh.Randeep Singh Surjewala : Sir, this is a preliminary reply. I do not know the facts and it dose not relate to the questioon in hand.She should write to me and I will give her a full reply.

श्री हरि राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि झज्जर और बहादुरगढ़ भाहरों में पिछले 20-25 सालों से गरीब गाढ़े लुहार रह रहे हैं, क्या सरकार उनको भी प्लॉट या मकान बनाकर देगी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता तो वाजिब है। बागड़ी गाढ़े लुहार हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और उनको भी रहने का एक समान अधिकार है। जहां तक हाउसिंग बोर्ड की स्कीम का प्रश्न है, यह एक ओपन एडिड स्कीम है इसके लिए कोई भी व्यक्ति दरखास्त दे सकता है। इसमें लोअर इन्कम ग्रुप, मिडिल इन्कम ग्रुप और हायर इन्कम ग्रुप के मकान होते हैं। इसी प्रकार हुडा में इकोनोमिकली वीकर सैव इन के लिए मकान बनाये जाते हैं। उनके लिए ये भाई अपनी दरखास्त दे सकते हैं। दरखास्त देने के बाद जो बाकी की कैअेगरीज को मकान दिए जाते हैं उनके साथ इनकी दरखास्त को भी कंसीडर किया जायेगा।

construction of Bus Stands

***917. Dr. Sushil Indora :** Will the Transport Minister be pleased to state the number of bus-stand-constructed or being constructed during the last three year together with number of those Bus Stand which have not started functioning even after the completion of construction work ?

शिक्षा मन्त्री(श्री मांगे राम गुप्ता) : पिछले तीन वर्षों के दौरान 6 बस अड्डे निर्मित किये गये तथा इस समय 7 बस अड्डों पर निर्माण का कार्य चल रहा है। पिछले तीन वर्षों में ऐसा कोई भी बस अड्डा नहीं है जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हो तथा प्रयोग न हो रहा हों।

डॉ.सु गील इन्दौरा : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने छोटे से भाबदों में अपना जवाब दे दिया। बस अड्डे इस लिए बनाये जाते है कि जनता को सुविधा मिले और उस सुविधा के साथ उनका प्रयोग हो। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा आया है कि कुछ उस अड्डे ऐसे हैं जिनका उद्घाटन हो गया और वे बनकर भी कम्पलीट हो गये उसके बावजूद भी अब तक वे बस अड्डे जनता के लिए प्रयोग नहीं हुए हैं जैसे जुलाना, बवानी खेड़ा, उचाना, इसराना, रानियां, राजौंद आदि ऐसे कई बस अड्डे है जो पिछले कई सालों से प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं। इनका प्रयोग में न आना सरकार के वित्तीय प्रबन्धन पर बड़ी भारी चोट है क्योंकि पैसा तो जनता का ही है। मैं माननीय मंत्री जीसे यह पूछना चाहता हूं कि इन बस अड्डों को कब तक जनता के प्रयोग में लाया जायेगा ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्र न में तीन साल पीछे के टाईम में बस अड्डों के बारे में पूछा था कि पिछले तीन सालों में कौन से बस अड्डे प्रयोग में नहीं लाये गये हैं। इसके बारे में मैंने अपने जवाब में पूरा विवरण दे दिया है। जुलाना, उचाना के बस अड्डे पिछले तीन सालों से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से ऐसे ही पड़े हैं। कुछ बस अड्डे वर्ष 1982 में , 1985 में और कुछ पिछली सरकार के समय मे बनाये गये थे। कम से कम 15 ऐसे बस स्टैण्ड हैं जो बाहरों के साथ न होने के कारण पब्लिक के प्रयोग में लाया जाये या किसी दूसरे

विभाग को दिया जाये ताकि पब्लिक का आना जाना भुरु हो जाये। 15 ऐसे बस अड्डे हैं जो तीन ससाल से पहले पूरी तरह से प्रयोग में नहीं आ पा रहे हैं।

डॉ.सु गील इन्दौरा : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछले कई सालों से बस अड्डे प्रयोग में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि भाहर से उनकी दूरी है। क्या वे उदाहरण द्वारा बता सकते हैं ? क्योंकि रानियां का बस अड्डा तो बिल्कुल भाहर के अन्दर है क्या वे इस बारे में सर्वे करवायेंगे ताकि सर्वे के आधार पर यह पता चल सके कि वे किन कारणों से प्रयोग में नहीं आ पा रहे हैं और इन बस अड्डों का सुचारु रूप से प्रयोग किस प्रकार किया जा सकें ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने रानियां बस स्टैण्ड का जिक्र किया है कि इस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं है। इस बस स्टैण्ड का इस्तेमाल हो रहा है और अगर कोई ऐसी बात माननीय सदस्य के नोटिस में हैं तो वे लिखकर भिजवा दें। इस मामले में जरूर तहकीकात की जाएगी। 15 बस स्टैण्ड जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है उनकी लिस्ट अलग है इनमें रानियां का नाम नहीं है।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा करनाल बस स्टैण्ड के बारे में हर सै ान में सवाल लगता है। मैं अब यह नहीं

पूछूंगी कि यह बस स्टैण्ड कब तक बनेगा ? हम जब भी इस बस स्टैण्ड के बारे में पूछते हैं तो हमें कहा जाता है कि इस पर कंसल्टेंट्स के टैण्डर्ज हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि कंसल्टेंट्स के टैण्डर्ज अभी तक हुए हैं या नहीं ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि उनका करनाल बस स्टैण्ड का प्र न कई बार हाऊस में लगा है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि करनाल में बस स्टैण्ड आज भी बना हुआ है लेकिन सरकार ने महसूस किया है कि यह बस स्टैण्ड भाहर के बीच में पड़ता है जिसकी वजह से लोगों को काफी प्रोब्लम रहती है। सरकार का इस बस स्टैण्ड को भाहर से बाहर ि टाफ्ट करने का प्रपोजल है। इसके लिए हुड्डा के सैक्टर में जमीन का पोजै ान ले लिया गया है। पहले एक ऐसा विचार हुआ था कि जो पुराने बस स्टैण्ड बनते जा रहे थे उनसे हटकर एक नये बस स्टैण्ड का सैम्पल लाया जाए। जैसा कि हरियाणा ओर बातो में पूरे दे ा में अग्रणी हैं उसी प्रकार एक नए मॉडल का बस स्टैण्ड करनाल में बनाने का सरकार का विचार है इसके लिए कंसल्टेंट्स बुक किए गए हैं और उनको काम भी दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि थोड़ा इंतजार करें, करनाल में बस स्टैण्ड अव य बनेगा और वह बस स्टैण्ड हरियाणा का अद्वितीय बस स्टैण्ड होगा।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या कंसल्टेंट्स के टैण्डर्ज हो गए हैं ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि कंसल्टेंट्स के टैण्डर्ज हो गए हैं ।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, तावड़ में बस स्टैण्ड के लिए 1996 में पत्थर रखा गया था लेकिन वह आज तक नहीं बन पाया और वहां के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहां प्राइवेट बसिज खड़ी रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि तावड़ में बस-स्टैण्ड बनाने बारे सरकार का कोई विचार है या नहीं ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि तावड़ के अंदर न कोई बस स्टैण्ड है ओर नहीं कोई बस स्टैण्ड बनाने बारे सरकार का विचार है ।

श्री नरे । मलिक : अध्यक्ष महोदय, 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी सांपला में गए थे और वहां बस स्टैण्ड बनाने की घोशणा करके आए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस स्थिति में हैं कि मुख्यमंत्री की घोशणा के अनुसार सांपला में बस स्टैण्ड बनाएंगे ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि सांपला में बस स्टैण्ड बनाने की घोशणा मुख्यमंत्री महोदय ने की होगी, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे पास मुख्यमंत्री महोदय की ऐसी कोई घोशणा नहीं आई है और जैसे ही यह घोशणा हमारे पास आएगी तभी उस पर विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सांपला बस स्टैण्ड के लिए जमीन ऐक्वीजिशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं।

श्री नरेण यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सत्र में मंत्री जी ने आवासन दिया था कि नांगल चौधरी में जमीन ऐक्वायर करके बस स्टैण्ड बनाया जाएगा तो मैं अब माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नांगल चौधरी में बस स्टैण्ड बनाया जाएगा या नहीं ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से माफी चाहूंगा कि नांगल चौधरी में बस स्टैण्ड बनाने का कोई प्रपोजल सरकार का नहीं है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में परिवहन व्यवस्था और तंत्र पूरी तरह से सुदृढ़ है। फरीदाबाद जिला आबादी की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है, यहां पर सैक्टर

12 में सामान्य बस अड्डा बनाया जाना है जिसकी भायद मार्च में नींव भी रखी गई थी। पिछले विधान सभा में सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने माना था कि फरीदाबाद में बस अड्डा बनाया जायेगा और मंत्री जी किसी कार्यक्रम में फरीदाबाद आये भी थे उस समय भी वहां बस अड्डा बनाने की घोशणा करके आये थे कि जल्दी ही बस अड्डा बनानेका काम भुरू करवा देंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहा पर बस अड्डा बनाने का प्रोविजन भी है और मंत्री जी ने कमिटमेंट भी किया हुआ है इसलिए क्या वहांपर मंत्री जी बस अड्डा बनाने की कृपा करेंगे और बनायेगें तो कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा। पहले मैं पहले वाले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि सांपला के अंदर बस अड्डा बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। दूसरा मेरे साथी महेन्द्र प्रताप जी ने फरीदाबाद के अंदर नया बस अड्डा बनाने की मांग की है। फरीदाबाद भाहर दिल्ली के नजदीक बहुत अच्छा भाहर है। इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हम फरीदाबाद में करनाल की तरह बहुत आधुनिक बस अड्डा बनाया चाह रहे हैं जिसको हम जल्दी ही फाईनल करने जा रहे हैं।

बिजली मंत्री(श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो फरीदाबाद में नया बस अड्डा बनाने की मांग की है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में

बस अड्डे के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रही थी। यह बहुत पुराना विवाद जमीन उपलब्ध न होने की वजह से चला आ रहा था। यदि मुझे सही याद पड़ता है तो 8-9 महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद में बस अड्डा बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए स्वयं मीटिंग ली थी तथा फरीदाबाद में सचिवालय के पास बस अड्डा बनाने के लिए जमीन कर्व आऊट करवा कर ट्रांसपोर्ट विभाग को दिलवाई है। यह जमीन बे आकीमती जमीन है और यहां पर बी.ओ.टी. बेसिज पर बहुत अच्छा बस अड्डा बनाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 साल से गुड़गांव और फरीदाबाद में बस अड्डे के लिए जमीन का विवाद चला आ रहा था। इन दोनों भाहरों में बस अड्डे बनानेके लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इंटरवीन करके कई सौ करोड़ रुपये की जमीन अधिग्रहण करके इन दोनों जगहों पर बस अड्डे बनवाने के लिए दिलवाई है और असंभव काम को संभव किया है।

श्री गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुख्यमंत्री जी के आ पीर्वाद से कलायत हल्का आज विकास की राह पर अग्रसर है लेकिन यह बस अड्डे से जुड़ा हुआ प्र न है इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कलायत के अंदर बस अड्डा बनाने के लिए 26 अक्टूबर, 2006 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ि आलान्यास किया था। वहां पर बस अड्डा बनाने के लिए जमीन नै आनल हाई वे नं० 65 पर है जो कि बस अड्डा बनाने के लिए

बहुत अच्छी साईट है। वहां पर बस अड्डे के लिए जो जमीन थी उसमें मिट्टी भी डल चुकी है और मीटिंगज भी हो चुकी हैं लेकिन बस अड्डे का निर्माण कार्य अभी तक भुरू नहीं हुआ है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वहां पर कब तक बस अड्डे का काम भुरू होगा ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा और माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि कलायत में पहले बस अड्डे के लिए जो नींव रखी गई और जो साईट बस अड्डे के लिए सिलैक्ट की गई थी वह गलती से दूसरे प्लॉट की सिलैक्ट हो गई लेकिन जब वहां नींव रखने के बाद कार्य भुरू करने लगे तब आब्जैक्टिव आ गया कि वह साईट हमारे विभाग की नहीं है। लेकिन उस मसले को अब हमने बड़ी मुश्किल से सुलझाया है और हमने उस जगह का पोज़ेक्टिव ले लिया है। जमीन की फिलिंग भी कर दी गई है और जल्दी ही वहां पर बस अड्डा बनाना भुरू कर देंगे।

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उस अड्डे भाहर से दूर बनाये गये हैं उनका प्रयोग नहीं हो रहा है जैसे कि इसराना का बस अड्डा भाहर से दूर बना दिया गया जिसके कारण उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। सरकार गोहाना में भी भाहर से दूर नया बस अड्डा बनाने जा रही है इसलिए मैं मंत्री जी से जानना

चाहता हूँ कि कहीं गोहाना के बस अड्डे का भी वही हाल न हो जो इसराना के बस अड्डे का हो रहा है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि इसराना के बारे में तो ये कह सकते हैं कि वहाँ पर बस स्टैण्ड भाहर से दूर पड़ता है इसलिए वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मगर जहाँ तक गोहाना की बात है तो इसकी चिंता वे न करे क्योंकि गोहाना में हम बस स्टैण्ड ऐसी साईट पर ही बनायेंगे जहाँ पर उसका ठीक इस्तेमाल हो सके।

construction of Transport Training Institute at Garhi Padla

***843. Sh. Shamsheer Singh Surjewala :** Will the Transport Minister be pleased to state:-

(a) whether Haryana Government and Ashoka Layland have jointly decided to construct a Transport Training Institute at Garhi Padla, District Kaithal;

(b) whether Gram Panchayat Garhi Padla had donated 14 acres of agriculture land for the construction of this project; and

(c) the time by which project is likely to be started/completed, together with the total amount to be spent on this project ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) :

(क) जी हां, श्रीमान जी ।

(ख) जी हां, श्रीमान्जी । ग्राम पंचायत, गढ़ी पाडला ने 10 एकड़ भामलात भूमि उपहार के रूप में दी हैं । चार एकड़ अतिरिक्त भूमि तबदील करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) परियोजना प्रारम्भ कर दी गई हैं तथा यह अगले वित्त वर्ष 2008-09 में पूर्ण होने की संभावना है । इस परियोजना पर 16.95 करोड़ रुपये का खर्चा संभावित है ।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस प्रोजैक्ट में कम्पोनैट्स क्या-क्या बनाये जायेंगे । जो ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट बनेगा उसमें किस-किस प्रकार की ट्रेनिंग का प्रावधान होगा ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि परिवहन विभाग में जो हैवी लाईट व्हीकल ड्राईवर्ज हैं वे कम्पलीटली ट्रेड ड्राईवर नहीं हैं जिस कारण बहुत से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसके कारण बहुत सी जान-माल का नुकसान हो रहा है । इन सब कारणों को देखते हुए सरकार ने महसूस किया कि हरियाणा प्रदे 1 में कम से कम तीन ड्राईवर ट्रेनिंग सैन्टर्ज खोले जायें जो कि क्रम 1: बहादूरगढ, रोहतक और कैथल में खोले जायेंगे । जो भी भविश्य में ड्राईवर सैन्टर्ज में से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी । जो व्यक्ति इन ट्रेनिंग सैन्टर्ज से

ट्रेनिंग लेगा उसे ही लाईसैंस मिलेगा और उसको ही गाड़ी चलाने का अधिकार होगा। इसके साथ-साथ हमने टेस्टिंग सैन्टर बनाने का भी फैसला किया है। कई केसिज में हमने यह देखा कि कई बार एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती से नहीं होता बल्कि गाड़ी में कमी भी कभी-कभी एक्सीडेंट का कारण बन जाती है। इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि गाड़ी की, स्पेयर पार्ट्स और दूसरे जो पार्ट्स हैं उनकी भी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। इसके लिए हमने टेस्टिंग सैन्टर बनाने की भी योजना बनाई जिसमें हरेक गाड़ी को एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रॉपरली चेक करके उसको दुरुस्त किया जायेगा और अगर उसके किसी पार्ट को बदलना जरूरी होगा तो उसको भी बदल दिया जायेगा।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इन ट्रेनिंग सैन्टरज में ड्राइवर्ज के अलावा क्या कण्डक्टर्स और परिवहन विभाग की वर्क गप के दूसरे कर्मचारियों के लिए भी ट्रेनिंग की क्लासिज और होस्टल का भी प्रबन्ध किया जायेगा ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि इन ट्रेनिंग सैन्टरज में सिर्फ ड्राइवर्ज के लिए ही ट्रेनिंग दी जायेगी और जहां तक कण्डक्टर्स का सम्बन्ध है तो कण्डक्टर्स और दूसरे कर्मचारियों के लिए किसी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त होस्टल बनाने की योजना भी सरकार के विचाराधीन है

और जल्दी ही होस्टल की व्यवस्था भी कर दी जायेगी। अगर उसमें कुछ कैंडीडेट्स ऐसे होंगे जो दूर से आकर दाखिला लेंगे तो उनके रहने की व्यवस्था भी कर दी जायेगी।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस गांव ने इस परियोजना के लिए 14 एकड़ जमीन दी है उस गांव को इससे क्या लाभ होगा ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह एक पृथक प्र न है। इस प्रकार की बात मेरे नोटिस में नहीं है। इसके बारे में वे लिखकर भिजवा दें। इस बारे में इनको उचित जवाब भिजवा दिया जायेगा।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमने फाईल पर यह निर्णय लिया हुआ है कि ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल के लिए जिस गांव द्वारा भूमि दी जायेगी वहां के बच्चों को बगैर कोई पैसा चार्ज किए उस ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल में सरकार द्वारा नि मुक्त ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ड्राइवर्ज ट्रेनिंग स्कूल के अन्दर क्लास 3 ओर 4 के जो लोग उनमें भी सरकार द्वारा उस गांव के बच्चों को नौकरी के मामलों में प्राथमिकता दी जायेगी।

construction of Road

***965. Shri Naresh Yadav :** Will the P.W.D (B&R) Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads;-

1. Mohlara to Ramchanderpura via Rattaklan;
2. Rattaklan to Kaslwari;
3. Gokalpur to Bihali via Begpur Ateli;
4. Bhilwara to Nawdi Ashram(upto Narnaul to Rewari Road);
5. Mahasar to Ragunathpura(upto Girdharpur Mor);
6. Karia to Bochria; and
7. Sariato Shahpur Doyam;

(b) if so, the time by which the construction Work of the above said roads is likely to be started ?

Power Minister(Sh.Randeep Singh Surjewala) :

(a) only road listed at sr. No.7 is being considered for construction.

(b) Time cannot be specified as the construction of road involves the clearance of a manned railway crossing from the Minister of Railway, Government of India. Road work can be taken up only after such clearance.

श्री नरे । यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मैंने जिन 7 रोड्स का जिक्र किया है उनको प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जाये क्योंकि ये सभी सड़कें अटेली और महेन्द्रगढ़ को राजस्थान से जोड़ती हैं। इनकी लम्बाई भी बहुत ज्यादा नहीं है कोई एक किलोमीटर की है कोई डेढ़ किलोमीटर लम्बी है और कोई दो किलोमीटर लम्बी है।

श्री अध्यक्ष : नरे । यादव जी, इन रोड्स के बारे में मंत्री जी जवाब दे चुके हैं। अब आपका स्पैसिफिक प्र न क्या है ?

श्री नरे । यादव : अध्यक्ष महोदय, अब मेरा स्पैसिफिक प्र न यह है कि इन रोड्स को जरूर बनाया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र को लेकर सरकार पहले ही चिंतित है क्योंकि यह क्षेत्र हमारा दक्षिण हरियाणा का वह क्षेत्र है जिसको पिछली सरकार ने विकास से महरूम रखा। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए सरकार द्वारा 1888 लाख 38 हजार रूपये 54.87 किलोमीटर लम्बी विभिन्न सड़कें बनाने के लिए प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत दिये गये हैं। इन सड़कों में सरकार ने मुख्यतः अटेली खेड़ी रोड से राजस्थान बॉर्डर तक, नारनौल से मंढाना राजस्थान बॉर्डर तक, महेन्द्रगढ़ से चामदेड़ा, भालखी, दोंगड़ा, सिलापुर, अटेली रोड और अटेली से कनीना रोड, रेवाड़ी

से नारनौल जो कि स्टेट हाईवे नम्बर 20 है और यहाँ से खोड़, सिलापुर, सीमहा, दड़ौली अहीर से लेकर स्टेट हाईवे नं० 17 तक की सड़कें बनाने के लिए मंजूर की है। इसके अलावा 2 सड़कें और हमने अटेली विधानसभा क्षेत्र की मंजूर की है। एक सड़क है अकोली से खुराना राजस्थान बॉर्डर तक जो कि 2.20 किलोमीटर लम्बी है जिस पर 17 लाख 31 हजार रुपये का खर्चा आयेगा और दूसरी सड़क भाोभापुर से राजस्थान बार्डर तक की है जोकि आधा किलोमीटर लम्बी है जिस पर 5 लाख 55 हजार रुपये खर्चा आयेगा और जो सड़क हमने कहा है कि अंडर कंसीड्रे टन है इस पर भी 266 लाख रुपये अकेली पर खर्चा आयेगा। जो बाकी सड़कों की श्री नरे । यादव जी ने चर्चा की है उन सबकी पहले से ही कनैक्टिविटी है और जो मेरे माननीय साथी इन सड़कों की ड्यूअल कनैक्टिविटी चाहते हैं वह इस समय सम्भव नहीं है।

श्री अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यमुनानगर में जो बी.के.डी. रोड है जो की 100-150 गाँवों को जोड़ती है और जिस पर स्ऑन क्र ार जोन भी पड़ता है, क्या मंत्री जी इसको बनवाने का कोई प्रावधान करेंगे ? इस पर ट्रक बहुत ज्यादा चलते हैं और बाहर की गाड़ियों भी बहुत आती हैं। यह रोड बिल्कुल टूटा पड़ा है। इस पर 40 किलोमीटर यू.पी. का एरिया भी आता है। अध्यक्ष महोदय, इस पर दूसरी स्टेट्स से ट्रक आते हैं और दूर-दूर तक बदनामी होती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस सड़क को बनाया जायें।

श्री अध्यक्ष : यह प्र न तो आप पहले भी पूछ चुके है ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बी.के.डी. रोड का नाम लिया है पहले भी इसका जिक्र हुआ था और माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल ठीक है कि इस रोड पर बहुत ट्रेफिक चलता है । मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि इसको बी.ओ.टी. स्कीम के तहत बनाया जायेगा ।

श्री अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह कब तक बनकर तैयार हो जायेगी, क्या मंत्री जी इस बारे में कोई आ वासन देंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, बी.ओ.टी. का अपना सिस्टम है, उनकी अपनी प्रणाली है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि इसको जल्दी ही बनाया जायेगा ।

construction of Road

***943. De. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road between village Puranpura and Dhana Ladanpur in Bhiwani constituency ?

Power Minister(Sh.Randeep Singh Surjewala) : No, sir.

डॉ० वि० भांकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, हमारे खजाने लबालब भरे पड़े हैं, फिर क्या कारण है कि हमारी ये छोटी-छोटी सड़कें नहीं बन पा रही हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनके विधान सभा क्षेत्र के अन्दर काफी पैसा सड़कें बनाने के लिए सरकार ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा के अन्दर तकरीबन समान तौर पर पैसे का वितरण हुआ है।

Mr. Speaker : Now the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Providing Employment through Foreign Employment Bureau

***821. Dr. Sushil Indora** : Will the Labour & Employment Minister be pleased to state:-

(a) the name of the place where the Foreign Employment Bureau are located in Haryana;

(b) the number of persons to whom the employment has been provided by the above said Bureau sssso far; and

(c) the number of the employment seeking persons registered with the Bureau so far ?

भाहरी विकास मन्त्री (श्री ए०सी०चौधरी) :

(क) विदे 1 रोजगार ब्यूरो का कार्यालय पुचकूला में स्थित है।

(ख) ब्यूरो द्वारा अब तक 11 प्रार्थियों को दुबई नौकरी के लिए भेजा गया।

(ग) बाहर जाने के लिए अब तक 7064 प्रार्थियों ने ब्यूरो के पास पंजीकरण करवाया है।

Fuctioning of Haryana Rural Development athority

***967. Sh. Radhey Shyam Sharma Amar :** Will the Labour & Employment Minister be pleased to state tthe time by which the Haryana Rural Development Athority will start its functioning ?

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की स्ीपना एवं गठन अधिसूचना दिनांक 29-10-2007 के द्वारा किया गया है ओर इस प्राधिकरण ने हरियाणा पंचायत भवन, सैक्टर 28, चण्डीगढ़ में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

Recurring loss of Revenue

***811. Dr. Sita Ram :** Will the Industries Minister be pleased to state:-

(a) whether the land for setting up SEZ has been acquired in the State, So far; and

(b) if so, the recurring loss to be incurred to Government in the form of land revenue ?

उद्योग मन्त्री,(श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा) :

(क) हां श्रीमान् ।

(ख) सरकार को भूमि राजस्व के रूप में कोई हानि नहीं हुई है ।

वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

Mr.Speaker : Hon'ble Members, now, discussion on the Budget Estimates for the year 2008-09 will resume Yesterday. Shri Ram Kumar Gautam was on his legs. Now, he may continue his speech on Budget Estimates for the year 2008-09.

श्री राम कुमार गौतम (नारनौद) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी सी इम्पोर्टैंट बात हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। मैं बजट पर ही भुरु कर लेता हूँ। जो बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने पे । किया है उसके बारे में जो बातें मेरी समझ में हैं वह मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। मैं कोई अर्थ- गारंटी तो नहीं हूँ लेकिन जितना बजट मेरी समझ में आया है मैं अपनी बात यहां रखने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे काबिल वित्त मंत्री चौधरी बिरेन्द्र सिंह जी ने पे । किया है उसको पढ़ कर पता चलता है कि डेफिनेटली वे

बहुत ही काबिल आदमी हैं। भगवान की दया है कि वे पॉलिटिक्स में सही मौके पर आ गए लेकिन हम बूढ़े हो कर इस पालिटिक्स में लेट आए हैं। हमने साथ ही साथ पढ़ना शुरू किया था। लेकिन 58-59 साल की उम्र में जाकर मेरा इसमें संतर बैठा जबकि भाई बिरेन्द्र सिंह जी ने 30 साल की उम्र में ही कच्चे काट लिए। (विधन) नैचुनली वे पॉलिटिक्स में ज्यादा मेच्योर हैं।

एक आवाज : गौतम साहब, आज इनका जन्म दिन भी है इसलिए इनको जन्मदिन की बधाई भी दे दीजिए।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको जन्मदिन की बधाई भी दे देता हूँ।(विधन)

एक आवाज : इनका जन्मदिन तो कल है आज तो चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला जी का जन्मदिन है।

श्री राम कुमार गौतम : मैं इनको कल भी जन्मदिन की बधाई दे दूंगा और आज तो मैंने इनको बधाई दे ही दी है। मैं चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला जी को भी जन्मदिन की बधाई देता हूँ। स्पीकर सर, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले समय मेरे कुछ भाईयों ने मेरे खिलाफ ऐसी बातें कही और बजट वाले दिन ऐसे-ऐसे इल्जाम लगाए कि गौतम तो कांग्रेस पार्टी में जाने वाला है, कांग्रेस के पे पार्टी मेरी पार्टी है। हिन्दुस्तान में दो ही पार्टीज है एक कांग्रेस में जाने वाला हैं, कांग्रेस के पे रोल पर हैं, मुझे कांग्रेस पार्टी का ऐजेंट कहा।

अध्यक्ष महोदय, बी०जे०पी० मेरी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है। हिन्दुस्तान में दो ही पार्टीज हैं एक कांग्रेस पार्टी और एक बी०जे०पी० पार्टी और बाकी की जो पार्टीज है वे लूट-खसोट के गिरोह हैं। लोग जानते है कि इनमें किसी का खेल कुछ भी नहीं है। वे सदस्य जो यहां पर बैठे हैं सारे मेरे भाई हैं, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा वे सभी मेरे भाई हैं और मैं उन सबका दिल से रिगार्ड करता हूं। जो संविधान बनाने वाले हमारे बुजुर्ग थे और जो संविधान बना था उसकी कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डा० भीम राव अम्बेडकर थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता श्री को भी यह सौभाग्य प्राप्त है कि वे उस संविधान सभा के मैम्बर हुआ करते थे (विधन) मैं उनका दिल से भुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हकारे भई जिनको आज दलित समाज कहा जाता है सो ल स्ट्रक्चर में उनको अधिकार दिये गये और वे आज एम०एल०ए०, एम०पी०, आई०ए०एस०, डॉक्टर, आई०पी०एस०, एच०सी०एस० आदि बड़ी-बड़ी सर्विसिज मे आते हैं। ये किसी से कम नही थे। ये मा ल बिरादरी के हमारे भाई थे। अध्यक्ष महोदय, जब मोहम्मद गजनवी ने हमारे दे ा पर हमला किया था तो इस मा ल बिरादरी ने उसके एक बार नही कई बार दांत खट्टे कर दिये थे। इतिहास गवाह है जब कोई हार जाता है तो उसको पता नहीं क्या-क्या कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि रावण सारी सृष्टि में सबसे विद्वान था, सबसे काबिल था लेकिन लोग उसको आज राक्षस कहते हैं क्योंकि वह हार गया था। यह

काम इनके साथ भी हुआ। They were actually defeated और वे कमजोर पड़ गए और रिजर्व्स और रिजर्व्स ट्राईब्स में आ गए। अब यह बात ये बेचारे भाई समझते ही नहीं हैं। महज एम०एल०ए० और एम०पी० बनाने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां पर इनके बीज का नाश कर दिया गया है। इनका नेता जो है वह अपने समय में इन भाईयों का 10,000 का बैकलॉग छोड़ कर चला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार का बजट स्टडी कर रहा था तो उसमें मैंने देखा की एस०सी० और बी०सी० के लिए 21 प्रतिशत बजट रखा है। जब इनके नेता का राज था उस समय में यह बजट था नहीं, वह इनको लोगों में गिनता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर असेम्बली में और एम०पी० के लिए इनका रिजर्व्स नहीं होता तो वह इनकी भावना को देखना ही पसन्द नहीं करता। He hates them. फिर भी पता नहीं इन भाईयों की क्या मजबूरी है जो ऐसी पार्टी में बैठे हुए हैं। मैं तो इनको कहना हूँ कि ये मेरी तरह अच्छे काम करें तो जनता इनको जरूर मेरी तरह चुनकर भेजेगी, चाहे बुढ़ापे में मौका देगी पर मौका जरूर देगी क्योंकि जनता आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखती है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मुझे एक भाव बहुत अखरा कि मेरे किसी भाई ने कह दिया कि राम कुमार गौतम एजेंट है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि मैंने आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया है। मैं उस आदमी को जो घर की इज्जत लूटवाता है और जो पैसा लेकर काम करता है या करवाना है, एक ही मानता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी

ईमानदारी से इन बेचारे भाईयों को कहना हूँ कि भाईयों में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी भी मायावती और कां गी राम जी को भी बुरा नहीं कहा है जो कि यह कहा करते थे कि "तिलक, तराजू ओर तलवार, इनको मारो जूते चार।" तिलक में तो हम आ जाते हैं। (विधन) अब जाटों के बारे में पता नहीं क्यों कह दिया वे तो बेचारे वैसे ही पिछड़ी जाति में आते हैं। (हंसी)

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मायावती पहले तो यह कहती थी कि " तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार।" लेकिन जब सता में आना था तो उस समय उसने यह नारा दिया था, "तिलक, तराजू और तलवार, इनकी बोलों जय जयकार। "

श्री राम कुमार गौतम : मैंने अपने जीवन काल में कभी कां गिराम और मायावती की बुराई नहीं की। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि गौतम तू फंलाने के खिलाफ भी बोला लेकिन तू कां गिराम या मायावती जो रोजाना गाली देते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता। मैंने उनको कहा कि जिन लोगों की लड़ाई वे लड़ रहे हैं मैं भी उन्ही की लड़ाई लड़ रहा हूँ, हम भी गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं लेकिन तरीका अलग-अलग है। हमारे पास बैठे हुए भाईयों ने भी बहुत सी बातें कही हैं लेकिन मैं तो इन भाईयों का भी बुरा नहीं मानता हूँ मैं इनसे प्यार करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने दैनिक जागरण नाम से एक अखबार की वैबसाइट

पढ़ी थी। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस आजादी को पाने के लिए हमारे बजुर्गों ने लड़ाई लड़ी और जो आजादी हमें मिली है उसको कायम रखने के लिए हमारे जैसे चन्द लोग ही लगे हुए हैं लेकिन इनसे भी बहुत बड़ा रोल प्रैस का है उनका छोटा रोल नहीं है। लेकिन प्रैस का कोई आदमी अगर मनचाही बात लिख दे तो ठीक नहीं है क्योंकि उसको न तो समझ है और न ही उसको हरियाणा की राजनीतिक का ज्ञान है। मैं इन भाईयों को इतना डराना करना चाहता हूँ कि प्रैस का रोल बहुत बड़ा रोल है। प्रैस ने ही आगे आने वाला राज बनाना होता है। प्रैस ही यह बताती है कि अगर 36 बिरादरियों का राज होगा तो वह कैसा होगा। अध्यक्ष महोदय, यह सब प्रैस पर बड़ा भारी डिपेंड करता है। अगर प्रैस वाले यह निर्णय कर लें कि करप्शन खत्म हो जाएगा। कोई ताकत रोक नहीं सकती। कैसे रोक देगी ? सबकी आंखें हैं सबको पता है कि कौन कैसे और कितने पैसे खा रहा है और हरियाणा में कितने ओफिसर्स भ्रष्टाचारी हैं, जात पात का ढोंग रचाते हैं और मनचाही जगह पर वे पहुंच जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात हर आदमी जानता है। लेकिन मैं प्रैस वाले भाईयों को ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मैं जो उनके बारे में कहना चाहता हूँ उसको उनको समझ जाना चाहिए। मेरे बारे में यह कहना कि गौतम तो भोंपू है। और कभी यह कहना कि यह तो चौटाला की बुराई करता है, कभी चौधरी भजनलाल की बुराई करता है और कभी कभार यह हुडा साहब की बढाई कर देता है और कभी कभार एक आध बार यह सरकार की बुराई भी कर देता है। अध्यक्ष महोदय,

मेरा तो कंस्ट्रक्टिव रोल है मैं जिस दिन असैम्बली में चुनकर आया था उसी दिन मैंने ऐलान किया था कि मेरे लिए पहले दे । है फिर प्रदे । और फिर बी०जी०पी० है ।

श्री अध्यक्ष : फिर नारनोंद हल्का है ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, जब मैं पहली बार चुनकर आया था उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था और उस दिन मैंने मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दी थी। मैंने उनसे यह कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप यह न समझना कि आप कांग्रेस पार्टी से हो इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैंने कहा था कि मैं तेरे खून की इज्जत करता हूँ, तेरे से प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि तेरे में दे िभक्तों का खून है, तेरे दादा, तेरे पिता फ्रीडम फाईटर रहे हैं इसलिए तू अच्छा काम करियों और 36 बिरादरियों का भला करियों। अगर 36 बिरादरियों का भला करेगा, सबके लिए अच्छा करेगा तो हम तेरा साथ देंगे, इसमें पार्टी बीच में नहीं आएगी लेकिन अगर बदमा ि करेगा तो तेरे सबसे बड़े दु मन हम हैं। मुख्यमंत्री जी को याद होगा मैंने पहले ही दिन मुख्यमंत्री जी को यह कहा था। अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग मेरी मुखालफत करते है। मेरी पार्टी वाले भी कह देते हैं लेकिन मैं तो जो अच्छी बात समझ में आती है उसको कह देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक भाई अगर दुनिया को बेवकूफ बना रहा है और अगर मैं लोगों को यह न बताऊं कि ये आदमी डाकू है, भौतान है, बेवकूफ बना रहा है तो लोग कैसे समझेंगे। अध्यक्ष महोदय, फर्ज करो

लोग आपकी इस सरकार से नाराज हो जाएं तो वे ऐसे ऐसे डाकू भौतान को फिर से चुन लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे लोगों को अगाह करना, उनको बताना जरूरी है कि ये जो लोग चीफ मिनिस्टरी की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग किसी के भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी भिवानी में एक प्रैस कांफ्रेंस की थी और जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा मैं भुरू रखूंगा क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि कई लोग गलत ट्रैक पर चले जाएं। अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह बात कहने की घड़ी नहीं है क्योंकि भजनलाल जी के पोते का देहान्त हो गया है लेकिन मेरे मन में कई ऐसी बातें हैं जिनको कहने से मैं रोक नहीं सकता। कल चौधरी भजनलाल जी का ब्यान आया था जो उन्होंने हिसार से दिया था। वे कहते हैं कि अब तो लोकदल की सरकार चल रही है इस बारे में मुझे कोई गम नहीं है क्योंकि हम तो लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, और जन हित के कार्य करेंगे। उनका कहना था कि मेरा बेटा भी जन हित में लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कौन किसका भला करेंगे और कौन मौका देगा भला करने का ? जितनी लूटपाट करनी थी वह हो चुकी। अब तो वही बात है कि खेल खत्म और पैसा हजम क्योंकि खेल ही कुछ नहीं है। जिन बैकवर्ड क्लास के भाईयों ने उनको अपना खून पिलाया और 32 हजार अपनी वोट दी, उनको कहता था कि मैं नॉन-जाट का चैम्पियन हूँ। 27 परसेंट जो रिजर्वे इन लागू हुई वह रिपोर्ट सारे दे आ में तो 1991 में लागू हुई लेकिन उसने हमारे प्रदेश में नहीं लागू होने दी। उस नॉन-जाट का नारा लगाने वाले ने उनका

बीज मार दिया। 1995 में जाकर बड़ी मुक्ति कल से 27% रिजर्वे में लागू की। छोटी नौकरियों में और बड़ी नौकरियों में, व अफसरों की नौकरियों में तो सारा छोड़ दिया। मुख्यमंत्री महोदय, आप इससे इनके रहते लिस्ट निकलवाओ और देखों की उस दौरान कितने बी.सी.ए. के भाई अफसर बने, पता लग जाएगा। यह पता लग जाएगा तो कोई उसको छुएगा भी नहीं। नॉन-जाट का कैसा चैम्पियन था, यह उनको पता लग जाएगा। क्या पंजाबी भाई भूल जाएंगे उनका तीन सीटों पर कब्जा खत्म कर दिया कालका, फतेहाबाद और टोहाना में कब्जा खत्म कर दिया। मात्र 100 में से 5 नौकरियां दी, वे कैसे भूल सकते हैं। भूलेंगे तो मैं याद दिलाऊंगा। जब तक सांस है तब तक याद दिलाऊंगा इसी तरह से क्या ब्रह्मण भाई भूल जाएंगे ? उनका भी बीज मार दिया। 12 साल तक जब तक चीफ मिनिस्टर रहा उनको तीन या चार से फालतू टिकट नहीं लेने दिए। किसी को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। अगर कोई ब्राह्मण असल का बीज होगा तो नजदीक भी नहीं जाएगा। जाएगा तो मैं याद दिलाऊंगा। हमारे राम जी लाल जी साथ घुमते रहते हैं। वे देखते रहते हैं कि कौन सबसे बड़ा हाऊ है। उनको यह नहीं पता की सबसे बड़ा हाऊ तो तुम्हारे पास ही बैठा है। बैकवर्ड क्लास का नास करने वाला वही है। इसी तरह से उसने अग्रवाल दो, तीन या चार से ज्यादा कभी नहीं बनाए। कहता है नॉन-जाट का चैम्पियन हूं। मेरे ताड़े का कोई नेता नहीं। क्या नॉन-जाटनी के सारे बीज मर गए थे, जामने छोड़ दिए थे। सब जाम रखे थे। बड़े नेता तो बहुत थे पर वह आगे आने

का मौका ही नहीं देता था। वह इतना खतरनाक बहुरूपियां था कि हमारे जाट भाईयों को बहकाने उनके पास पहुंच गया। बनते ही जाट भाईयो को बहकाने लगा। मैं जाट हूं हम जाट से बिगड़ाने बने थे। है भी सच्ची बात। देसी खांड की जिसने बान है तो वो अग्रेजी क्यू खाव। जाट का बीस और नोई। हमारे जाट कालेज में गया वहां कहने लगा कि मैं थारा भाई हूं। रिबैन्डू रिबैन्डू निकलवा कर देख लो, मैं थारा भाई हूं। आपकी जितनी भी मांगे है बताओ, उनकी सारी मांगे मान भी ली और यू सोची की ये भाई भी नेता मान लेंगे। यह जो जाट कॉलेज के सामने एस.पी. का दफतर चल रहा है, यह धर्म माला के लिए दे दो। उन्होंने रिजैक्ट कर दिया और प्रवाना बाचने से इन्कार कर दिया। फिर जा कर पंजाबीयों को बहकाने लगा, कहने लगा कि मैं बहावल पूर का हूं। तुम भी रिफयुजी, मैं भी रिफयुजी। उनको भी बहका दिया और कुछ नहीं दिया उनका भी बीज मार दिया उसके बाद मुस्लमान भाईयों के पास चला गया। उनको फरीदाबाद में बुला दिया वहां एम.पी. बनने के लिए कहने लगा कि मेरा और तूम्हारा धर्म एक है। फर्क सिर्फ नाम का है। तुम भी मुर्दा गाढते हो, हम भी गाढते हैं। हम भी दफनाते है तुम भी दफनाते हो। इस तरह से उनको भी बेवाकूफ बनाया। ब्रहाम्णों को टिकट मिल जाता था और उनका भी बीज मार दिया। करनाल की सीट से जितने नेताओं का आर्िवाद चीफ मिनिस्टर बना, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चान्द राम, डॉ. मंगलसैन और पंडित भगतवत दयाल भार्मा और लाला बलवन्त राय तायल जैसे उसने मार दिए। ये लोग कभी

भुलेंगे नहीं, भूल भी जाएंगे तो मैं भूलण कोनी दूँ। भहरूपीए पन की भी हद है। कुम्हार धर्म ाला में गया और कहने लगा कि भाईयों मुझे खु ि है कि मैं अपनी कोम में आ गया हूँ। वहां कुम्हारों को कहने लगा कि मैं भी तुम्हारा भाई हूँ तो कुम्हार कहने लगे कि ते क्यों गलत कहें हों, तें तो बि ानोई हो। तब कहने लगा कि भाई जात कभी जन्म से नहीं होती वह तो कर्म से होती है। (विधुन)अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट के बारे में चर्चा करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : गौतम, साहब, आप औरकितना समय बोलने के लिए लोगे क्योंकि उस दिन आप 34 मिनट बोल चुके हो।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा समय और लूंगा। मैं सरकार का ध्यान बजट की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरी समझ में जो मोटी बात आई है वह य है कि जो फोरैस्ट का बजट है वह 110 करोड़ रूपयें का है। मैं यह समझता हूँ कि यह बिल्कुल नाजायज बजट है। इसमें कहा गया है कि पांच करोड़ पौधे हर साल लगाये जाते हैं। कितने साल बीत गये। लगभग 10 साल से चल रहा है। आप वहां मौके पर जाकर देखिये सारे आंकड़े फ्रॉड हैं, फोरजरी है। जहां तक फूड सप्लाई विभाग की बात है इस विभाग को तो बन्द ही कर देना चाहिए क्योंकि गाँवों में रा ान तो किसी को मिलता नहीं हैं या फिर वहां पहरेदार बिठाने चाहिए ताकि अगर कोई रा ान नहीं दे तो उसकी

मरम्मत कर सकें। अध्यक्ष महोदय, कोआप्रे इन का बजट है यह 19 करोड़ रूपयें का बजट है। इस बजट को और बढ़ाना चाहिए और गरीब लोगों के लिए ज्यादा लोनिंग का प्रावधान करना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी को जो लोन मिलता है वह या तो वक्त पर मिलता नहीं अगर मिलता है। तो उसके लिए भी कमी इन देनी पड़ती है। गरीब आदमी तो चक्कर लगा-लगा कर मर जाता है। जहां तक पावर की बात है पावर के लिए बजट 862 करोड़ 13 लाख रूपयें मिला है यह बजट बहुत थोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, आज गांवों में पुरानी वायर बदलने के योग्य हो गई है। आज बिजली का सारा सिस्टम लड़खड़ा गया है। इसके कई कारण हैं क्योंकि बीच में ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार आई जिन्होंने लोगों को कहा कि बिजली के बिल न भरों मैं यो आया। जब लोग बिजली के बिल नहीं भरेगें तो नेचुरली पैसा कहां से आयेगा और उसके बाद बेवकूफ बनाकर सी०एम० बनकर जिन लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे उनको गोलियापें से भुनवाया। पावर के लिए यह बजट थोड़ा है। बिजली की ज्यादा से ज्यादा जनरे इन का इन्तजाम करना चाहिए और इन्फ्रास्ट्रैक्चर को बढ़िया से बढ़िया करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्कूलों के लिए बहुत थोड़ा बजट रखा गया है। स्कूलों की बिल्डिंग लगभग खराब पोजी इन में है। 10-10 एकड़ या 5-5 एकड़ में स्कूल बने हुए हैं। स्कूलों की बिल्डिंग इतनी खराब पोजी इन में हैं कि कोई भी मां-बाप अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते और वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पंसद करते हैं चाहे वे प्राइवेट

स्कूल एक कोठड़ी में ही क्यों न बने हों। अध्यक्ष महोदय, 10+2 स्कूल चाहे लड़कियों के लिए हो चाहे लड़कों के लिए हों, जितने होने चाहिए उससे बहुत कम हैं। प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि स्कूलों के लिए बजट बढ़ाना चाहिए। एलीमेंट्री एजूके इन में योगा कम्पलसरी करनी चाहिए क्योंकि एक बार योगा लागू हो गया तो बच्चे बीमार नहीं होंगे और प्रदेश से हेल्थ की प्रोब्लम खत्म हो जाएगी। हायर एजूके इन के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है जो कि बहुत थोड़ा है, हमने मुख्यमंत्री महोदय से कई बार कहा कि हमारे नारनौंद और आस पास के गांवों की लड़कियां जब बस्ता उठाकर बसों में धक्के खाती जाती हैं तो हमारे लिए भार्म से डूब के मरने वाली बात हो जाती है। सारे गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर पहली बार मुख्यमंत्री महोदय को खाना खिलाया और उनसे एक मेन मांग की कि हमारे यहां लड़कियों के लिए एक कॉलेज और आई०टी०आई० बननी चाहिए। (इस समय संभापतियों की सूची में एक सदस्य आई०जी० भोर सिंह चेयर पर पदासीन हुए।) हम जब भी मुख्यमंत्री जी से हमारे यहां कॉलेज खोलने के बारे में पूछते हैं तो वे कहते हैं कि क्या करूं गौतम जी बजट कम है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब पूरे हरियाणा प्रदेश में इतने कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो केवल हमारे इलाके के लिए ही बजट क्यों कम है? हमारे यहां लड़कियों और लड़कों के लिए एक कॉलेज खोल दिया जाए तो हम आपके आभारी होंगे। सभापति महोदय, स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत कम

बजट रखा गया है। स्पोर्ट्स के मामले में हम आज दूनिया में बहुत पीछे हैं, हालांकि सरकार ने बनने के बाद कुछ स्टेडियम्स बनाए हैं लेकिन अभी भी हरियाणा में स्टेडियम की कमी है। स्टेडियम ज्यादा बनने चाहिए। सभापति महोदय, एक तरफ अर्बन डिवैल्पमेंट डिपार्टमेंट हैं और दूसरी तरफ टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है। अर्बन इस्टेट सब जगह नहीं है इसलिए या तो सरकार कम्पलसरी कर दे कि जहां भी म्यूनिसिपल एरिया हैं चाहे क्लाय सी० हो, चाहे क्लास बी० हो, यानि जहां भी म्यूनिसिपल कमेटियां बनी हुई हैं वहां अर्बन इस्टेट जरूरी हो और जब तक अर्बन इस्टेट नहीं बनती तब तक टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले नोटिस देकर किसी का पीस आफ माइंड खराब न करें। जो भी अर्बन इस्टेट बन रहे हैं सरकार उसके लिए जमीन चाहे 20 लाख रूपये प्रति किला एक्वायर करें या 10 लाख रूपये प्रति किला एक्वायर करे लेकिन प्लॉट का भाव 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार या 10 हजार रूपये भी गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा हैं, इसलिए जो गरीब आदमी 1000 रूपये या 500 रूपये गज के हिसाब से प्लॉट ले लेते हैं उनके लिए या तो कोई ऐसा अर्बन इस्टेट बनाया जाए जिसमें उनको भी रियायत हो और या जो कॉलोनियां बन चुकी हैं उनको रैगुलैराईज कर दिया जाए जिसमें उनको राहत मिल सके। उन अनअथोराइजड कॉलोनियां बन चुकी हैं उनको रैगुलैराईज कर दिया जाए जिसमें उनको स्पै 1ल रियायत हो और या जो कॉलोनिया बन चुक ताकि उनको भी राहत मिल सके। लेबर एण्ड लेबर वैंल्फेर की बात है तो अभी

हमारे मंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि हिन्दुस्तान में हरियाणा ही ऐसी स्टेट है जहां 3510/- रुपये हम अपने लेबर भाई को देते हैं लेकिन यह कहीं भी लागू नहीं है। ठेकेदारी प्रथा में लेबर को 2000/- रुपये प्रतिमास ही दिये जाते हैं चाहे तो इस बारे में वित्त मंत्री जी पता कर लें। जो पब्लिक हेल्थ में भी सरकार ने आदमी लगा रखे हैं उनको केवल 3 हजार रुपये प्रतिमाह ही देते हैं फैक्ट्रियों में तो छोटे छोटे बच्चे लगा रखे हैं और 3500/- रुपये महीने की सैलरी किसी भी श्रमिक को किसी भी फैक्ट्री में नहीं मिल रही है। इसलिए इसकी तरफ सरकार विशेष ध्यान दे और इसे सख्ती से लागू करवाये। इसमें बजट भी बढ़ाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, अब मैं वैलफेयर ऑफ एस०सी० एंड अदर बैकवर्ड क्लासिज के बारे में बात करना चाहूंगा कि इसमें 130 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। 130 करोड़ रुपये इनके वैलफेयर के लिए बहुत थोड़ा है। हालांकि पहले वाली सरकार में तो इनके वैलफेयर के लिए न के बराबर बजट रखा जाता था। पिछली सरकार तो इन भाईयो के खिलाफ थी। उस समय एस०सी० भाईयो को गांवों में बसने नहीं दिया जाता था और तरह-तरह के जुल्म उन पर होते थे। यही कारण है कि पिछली सरकार के समय में एस०सी० भाई गांवों को छोड़कर चले जाते थे।

श्री सभापति : गौतम जी, आप क्या सुजैस्ट करते हैं ?

श्री राम कुमार गौतम : सभापति महोदय, मैं तो यही सुजैस्ट करता हूँ कि वेलफेयर ऑफ एस०सी० एंड अदर बैकवर्ड क्लासिज के लिए बजट थोड़ा है, बजट बढ़ाना चाहिए। सभापति महोदय, एक दफा मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि सरकार इन भाईयों को दो-दो एकड़ जमीन खरीदने के लिए लोन देगी। यह स्कीम लागू भी की गई लेकिन थोड़ा बहुत लोन दिया गया और कई जगहों पर पैसा दिया भी नहीं गया। मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरह से इस स्कीम को लागू किया जाये और कम से कम 5-5 एकड़ जमीन खरीदने के लिए इन भाईयों को लिब्रल लोन बिना ब्याज के दिया जाना चाहिए या 100 साल के पट्टे पर जमीन दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इनको जो लोन दिया जाये उस पर सब्सिडी भी दी जानी चाहिए ताकि गरीब भाई भी ऊपर उठ सकें। यदि सरकार ऐसा करेगी तो जो अपोजी इन में जिन साथियों ने गलत पार्टी पकड़ रखी है वे अच्छे लोगों का साथ देंगे और मुख्यधारा में आ जायेंगे। सभापति महोदय, अब मैं वाटर सप्लाई एंड सैनीटे इन के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि वाटर सप्लाई एंड सैनीटे इन के लिए 653 करोड़ रुपये का बजअ में प्रावधान किया गया है। यह पैसा ठीक है लेकिन इसमें कुछ बढ़ोतरी और करनी चाहिए। सभापति महोदय, मेरे हल्के में अनेक गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की बहुत समस्या है। मसूदपुर और डाटा गांवों में तो पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। मैं हर बार दे और वाटर सप्लाई एंड सैनीटे इन का बजट भी बढ़ाया जाये तभी जाकर सरकार हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कर पायेगी।

सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि हमारे वहां पर एक ऐसा नया रजबाहा जिस अधिकारी ने बनवाया है उसके खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिए और इसे सुधारा जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को पानी की समस्या न हो। सभापति महोदय, हैल्थ सर्विसिज के बारे में कहना चाहूंगा कि हैल्थ सर्विसिज में नाम मात्र का बजट रखा गया है। आज के दिन ज्यादातर गांवों में किसी भी हैल्थ सेंटर में डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। मेरे हल्के के बास गांव के हैल्थ सेंटर में डाक्टर नहीं है। इस बारे में मैंने हैल्थ मिनिस्टर महोदया को कई बार बताया है और न ही वहां पर बिल्डिंग का निर्माण है। सभापति महोदय, छोटे-छोटे झोलाछाप डाक्टर जिनको किसी बीमारी का ज्ञान नहीं है वे बहुत पैसा कमा रहे हैं। कई लड़के आर०एम०पी० की नई-नई ट्रेनिंग लेकर आते हैं और आते ही सूआ लगाने का काम शुरू कर देते हैं। इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए सभापति महोदय, वूमन एंड चाइल्ड डिवैल्पमेंट के लिए भी बजट में बहुत कम पैसा रखा गया है। आज के दिन हमारी बेटियां की दशा काफी खराब है। आज कौन सी सदी का जमाना है, सारी दुनियां कहां से कहां चली गई है लेकिन हमारी बहन-बेटियां वहीं की वहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की सहूलियत हमारी बहन-बेटियों को अवश्य दी जाये कि किसी भी परिवार की बेटि को पैसे की दिक्कत की वजह से अपनी हायर लैवल की पढ़ाई बीच में न छोड़नी पड़े। इसके अतिरिक्त जो हमारी अनपढ़ महिलाएं हैं उनके लिए भी सरकार ऐसा इंतजाम अवश्य करे कि वे कम से

कम चिह्नी ढढ सकें और अढने धर कल हलसलब—कलतलब रख सकें ।
इसललए बकड कल डल डढललल कलनल कलहलए ।

श्री सडलडतल : गलतड कल, अलड कृडडल वलईणुड अड करें ।

श्री रलड कुडलर गलतड : सडलडतल डहलदड, एक डलत डें
डह डतलनल कलहूंगल कल सरकर दवलरल कल वरुतडलन डकड डें रलडुक
और डुरलकलक के ललए कल 620 करलडु रूडडे कल डुरलवधलन कलडल
गडल है, डह डहुत ही थलडुडल है । डतल नहलं डह वलसुतव डें थलडुडल
लग रहल है । डलछले डकड सै डन के दलरलन वलतडंतुरल ने डुङुने कलहल
थल कल गलतड सलहड तुडुहलरल दल सडुकलं कल डनवलने कल कलडुडेदलरल
तल डें ले लेतल हूँ । सलरल सुटेक के कल छलटे छलटे रलड थे वे सडुडल
डन गडे लेकलन कलनुद से हलंसल कल कल सुटेक हलईवे थल वलह अडुडल
तक नहलं डनल । डलवकूद इसके कल इस सडुक कल डनवलने के डलरे
डें डलननलड डुखुडडंतुरल कल ने डुडल कलहल थल कल इस रलड कल डंकूरल
हल गई है इसललए डह डनेगल ही और डलननलड वलत डंतुरल डहलदड
के दवलरल दल सडुकलं कल डनलने कल कलडुडल लेने के डलद डुडल डगवलन
कलने हडलरल वल सडुक अडुडल तक कडुलं नहलं डनवलई गई । इसकल
डुडल टलल दलडल गडल । इसके अललवल हडलरल एक सडुक थल सुलसर से
वलडल डलटलल—डेटवलडु, डह हडलरल सडसे डडुडल डलंग है । इस सडुक
के डन कलने से अलड सडके ललए डुडल सहूललडत हल कलडुडल कडुलंकल
सुलधे सुवरकल से सुलसर डलटलल—डेटवलडु हलरक नलरनलँद और
नलरनलँद से उकलनल हलते हुए नरवलनल तक डह एक ऐसुडल डदुडल
सडुक है लेकलन डलर डुडल इसकल डनवलने कल तरड सरकर कल

ध्यान अब तक नहीं गया है। यह मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इसको बनवाने की जिम्मेदारी लेने के बाद भी यह नहीं बनी। दूसरी बात मैं ब्रिजिज के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे यहां जो खाण्डा का पुल है यह खाण्डा नहर पर नारनौंद से खाण्डा जाते वक्त आता है। नारनौंद से खाण्डा रोड पर नारनौंद की तरफ जो पहल पुल है वह बनवाना बहुत जरूरी है और एक बहुत बड़ी डिमाण्ड है दूसरे राजली पुल से खानपुर होकर डाटा और राजली पुल से डाटा की तरफ गुराना से खानपुर रोड तक दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट रोड हैं। मैं इनको बनवाने के बारे में कई बार कह चुका हूँ लेकिन ये भी अभी तक नहीं बने। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार का ध्यान इस और दिलाना चाहूंगा। इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलैक्शन होने के बाद की बात है जब डॉ० रघुबीर सिंह स्पीकर बने तो जो पास के गांव हैं उनमें स्पीकर साहब के गोती भाई रहते हैं तो वे कहने लगे कि अब तो हमारा भाई स्पीकर बन गया है अब तो हमारी सरकार है हमारा राज आ गया है। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा राज आ गया है यह बात तो ठीक है लेकिन तुम अपनी यह सड़क तो बनवा लो। लेकिन अब भगवान जाने कि वह सड़क कब बनेगी। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस और दिला रहा हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि कम से कम ये जो इतनी इम्पोर्टेंट सड़कें हैं इनको तो सरकार बनवाएगी ही। इसके साथ ही मैं सरकार का

धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो खाण्डा नहर पर पुल बना हुआ है उस पुल पर रिटेनिंग वॉल बनाने की जो मांग की गई थी वह इस पुल पर रिटेनिंग वॉल बनने से ही काम चलने वाला नहीं है रिटेनिंग वॉल बन जाने से ही पूरा फायदा लोगों को नहीं हुआ है क्योंकि यह पुल बहुत संकरा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से इस पुल को चौड़ा करने का भी अनुरोध करूंगा। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय के ध्यान में एक अति महत्वपूर्ण बात भी लाना चाहूंगा कि सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में संस्कृत विषय के लेक्चरर नहीं हैं। इस सरकार के आने से पहले पहली वाली सरकार के समय में जब भी स्कूलों को अपग्रेड किया जाता था तो संस्कृत के लेक्चरर की पोस्टें सभी स्कूलों में होती थी। इस बारे में शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संस्कृत प्राध्यापकों का शिष्ट मण्डल भी दो तीन बार मिल चुका है। उनको यही कहा जाता है कि जब किसी स्कूल में बच्चे संस्कृत विषय में दाखिला लेंगे तभी वहां पर संस्कृत के प्राध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। सभापति महोदय, जब स्कूल में प्राध्यापक ही नहीं होगा तो कोई बच्चा दाखिला कैसे लेगा। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि 10+2 के स्कूलों में बच्चों के दाखिलों से पहले ही संस्कृत विषय के प्राध्यापक होने चाहिए तभी बच्चे संस्कृत विषय में दाखिला लेंगे और तभी हमारी संस्कृत भाषा का विकास होगा। यही संस्कृत भाषा हमारे ऋशियों की भाषा है और यही हमारे हिन्दुस्तान की पहली भाषा का विकास होगा। जिससे

अनेक भारतीय भाशाएं डवलप हुई हैं। दूसरी बात, संस्कृत टीचर बनने के लिए बहुत से लोगों ने छोटे-छोटे बच्चे, 5-6 साल के बच्चे गुरुकुलों में दाखिला करवा दिये। कहीं किसी संस्कृत विद्यालयों में, कहीं रामरा के गुरुकुल में दाखिला करवा दिये। उनको इस बात का खतरा लगने लगा कि अगर ये बच्चे यहां पर रहे तो ये बेराजगार बन जायेंगे। उन्होंने सोचा था कि अगर ये बच्चे ओ०टी० और भास्त्री कर जायेंगे तो संस्कृत टीचर लग जायेंगे। इसलिए चेयरमैन सर, ओ०टी० और संस्कृत के टीचर जरूर लगाने चाहिए।

श्री सभापति : गौतम साहब, आप वाइंड अप करें।

श्री राम कुमार गौतम : सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जब मोहम्मद गौरी, भारत पर हमला करता था तो वह अक्सर हार जाता था। मोम्मद गौरी बहुत बार भारत से हारा है। उनको किसी ने यह बता दिया कि हिन्दूस्तान से जीतना तो बहुत आसान काम है। उसने पूछा कि कैसे आसान है ? उसको बताया गया कि यह दे । धर्म का दे । है। यहां लोग धर्म को बहुत मानते हैं और इस दे । में उनकी कई माताएं हैं, जैसे भारत माता, गऊ माता और उनकी माता। जब लड़ाई भुरू हो तो गऊओं का च्यौणा छोड़ दो और ये हिन्दू लोग गऊओं पर हथियार नहीं उठायेंगे और ये हार जायेंगे। सभापति महोदय, उन्होंने गऊओं का च्यौणा छोड़ दिया और जो हमारे राजपूत राजा थे या और जो दूसरे हिन्दू राजा थे जो गऊ को अपनी माता

समझते थे, उन्होंने हथियार नहीं उठाये। उसका नतीजा यह हुआ कि वे लड़ाई में हार गये। श्री ओम प्रकाश चौटाला को भी इसी प्रकार का फार्मूला मिल गया लगता है। वह भी कहीं पर तो आगे अरोड़ा, कहीं पर सुभाश गोयल और कहीं पर रामभगत भार्मा और कहीं पर इंदौरा जी, इस प्रकार से वह इन सबको गऊओं के च्यौणोकी तरह इस्तेमाल करके हरियाणा में सत्ता प्राप्त करना चाहता है लेकिन सभापति महोदय, उनका वक्त निकल चुका है अब उनका वक्त आने वाला नहीं है।

श्री सुभाश चौधरी (जगाधरी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी ने हरियाणा के बहुमुखी विकास के लिए, समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए जो बजट में सहूलियतें प्रदान की हैं वे अपने आप में सराहनीय हैं। सभापति महोदय, 3 साल पहले वह सरकार भी थी कि जिसने जाति के नाम पर, किसानों के नाम पर वोट लेकर उसील जाति के साथ धोखा दिया और उसका नतीजा यह रहा कि जनता ने उनको नकार दिया। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने केन्द्र सरकार से मिल कर किसानों को कर्ज से उबारने के लिए किसानों के लोन माफ करवा कर उनको राहत प्रदान की है। भारत सरकार से किसानों का जो कर्जा मुआफ हुआ है उससे किसानों के अन्दर उत्साह का संचार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से

समाज के हर वर्ग को राहत मिली है। हरियाणा के अन्दर एक नई आशा की किरण जगी है। हरियाणा प्रदेश की तरक्की और नई गरिमा स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तरक्की की ओर अग्रसर है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। इस सरकार के रजा में किसानों को बहुत राहत मिली है। किसानों का ब्याज मुआफ हुआ, कॉआपरेटिव के अन्दर भारत सरकार ने किसानों के कर्ज मुआफ कर दिये हैं, बिजली के बिल मुआफ हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को आनी फसलो का जो भाव मिला है वह पूरे देश के अन्दर अपने आप में एक मिसाल है। किसी भी प्रदेश के अन्दर किसी भी फसल का भाव हरियाणा से ज्यादा नहीं है चेयरमैन सर, मैं उस समय को भी याद करता हूँ जब तीन-चार साल पहले का समय था तब किसान की फसल मण्डी में पड़ी रहती थी और किसान उस पर बैठ कर रोया करता था। जीरी औने-पौने भाव में बिका करती थी। उस समय एक बात चारों ओर सुनाई पड़ती थी "चौटाला तेरे राज में जीरी गई ब्याज में।" उस समय के पीरियड के बाद एक समय आज का है जब हमारी सरकार ने और हुड्डा साहब ने भारत सरकार से, सैटर में बात करके हमें जीरी का जो रेट दिलाया है वह भी सारे हिन्दूस्तान में सबसे ज्यादा है और इसने भी एक नई मिसाल कायम की है और एक ऐसा माहौल आया है कि "हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में।" चेयरमैन सर, यह बात तो प्रदेश के हित में है और यह दर्शाती है कि सरकार की नीयत और नीति में क्या फर्क है। चेयरमैन सर, दो

महीने पहले ही हमने सरसो काटी हैं और उसमें 6 या 7 क्विंटल भी फसल नहीं हुई है। पाले की वजह से किसान को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। छः एकड़ गेहूं की सोईग है और फसल कटने वाली है। चेयरमैन साहब, आप इस बारे में जांच करवा सकते हैं कि उसमें एक भी दाना अनाज का नहीं है और उसमें से भूसा-भूसा ही बनेगा। चेयरमैन सर, इस पाले के कारण किसानों को जरूर दिया जाए। आज किसान इस स्थिति के अन्दर नहीं है कि फसल का घाटा बर्दा त कर सके। दूसरी फसल का घाटा बर्दा त करना किसान के लिए असम्भव होगा। पिछली सरकार के समय में हमें पॉपुलर का रेट नहीं मिला। हमारे यहां पर पॉपुलर की फसल होती है जिससे प्लाई की इंडस्ट्री चलती है। पॉपुलर का भाव देने में हमारी सरकार ने सारे रिकार्ड तोड़ दिये हैं। चौटाला साहब के राज में पॉपुलर का रेट 150/- रुपये मिलता था जब कि आज इसका भाव 600/- से 650/- रुपये मिल रहा है जो कि सरकार की नीयत को दर्शाता है। दोनों सरकारों में फर्क क्या है ? पिछली सरकार के समय में मुख्यमंत्री और मन्त्री उगाही करवाया करते थे और एम०एल०एज० से भी उगाही करवाते थे। (विधन) आज हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की यह सोच है जिसकी वजह से किसानों को उसका भाव मिला है।

श्री बलवन्त सिंह : चेयरमैन सर, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। चेयरमैन सर, मेरे सम्मानित सदस्य कह रहे हैं कि उस

समय के एम०एल०एज० से उगाही करवाई जाती थी। चेयरमैन सर, इनकी इस बात को सारे हरियाणा की जनता सुनने लग रही है। आज सदन में तमा गा सा बना रखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से यह कहना चाहता हूँ कि ये विद प्रूफ उस एम०एल०ए० का नाम बताएं कि वह उगाही करता था और कौन उससे करवाता था। इस बारे में जो कह रहे हैं उसकी इन्क्वायरी करवाई जाए।

श्री सुभाश चौधरी : चेयरमैन सर, माननीय सदस्य भी जानते हैं कि मेरे जिले में प्लाई इन्डस्ट्री का भाषाण हुआ था और वहां पर इनके समय में 20 लाख रूपए की मन्थली ली जाती थी। उस समय में वहां पर किसी एक उद्योगपति से एक करोड़ रूपए की डिमान्ड की गई थी लेकिन उसकी एवज में वह 70 लाख रूपए लेकर गया था लेकिन उसको एस०पी० अम्बाला द्वारा रास्ते में ही रोक लिया गया और उसको कहा गया कि या तो एक करोड़ रूपए लेकर आ जाए नहीं तो तुझे गलत प्रापर्टी रखने के इल्जाम में अन्दर कर दिया जाएगा। इस बारे में बलवन्त सिंह सढौरा जी भी जानते हैं।

श्री बलवन्त सिंह : चेयरमैन सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। माननीय साथी जी ने अभी जो बात कही है इस बारे में मेरा कहना है कि जिस तरह से हाउस की पहले कमेटी बनाई गई है उसी तरह से इनके द्वारा कही बातों की सच्चाई जानने के लिए भी हाउस की एक कमेटी बनाई जाए और जो इन्होंने बात कही है

उसके बारे में चैक किया जाए। इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री सुभाश चौधरी : चेयरमैन सर, पिछली सरकार ने 2003-04 में अपने वक्त में यमुनानगर भुगार मिल की मिलीभगत के साथ किसानों के 35 करोड़ की पेमेंट नहीं की थी। मैं इस बारे में सढ़ौराजी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात भी गलत है ? हमारी सरकार के आने के बाद ही मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने किसानों की वह पैमेंट दी है।

श्री बलवन्त सिंह : चेयरमैन सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। उस मसय किसान उस प्राईवेट मिल के खिलाफ कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट में जाने की वजह से ही उनकी पेमेंट का मामला लटका था न कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का उसमें हाथ था।

श्री सुभाश चौधरी : चेयरमैन सर, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान किसानों के उन ट्यूबवैल कनेक्शनों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनके ऊपर इण्डस्ट्रीयल रेट लगा हुआ है। चाहे वे ट्यूबवैल कनेक्शन, बागवानी, पंपुपालन या फिशर्री के लिए प्रयोग किए जाते हों। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन ट्यूबवैल कनेक्शनों को इण्डस्ट्रीयल रेट से निकाल कर एग्रीकल्चर स्लैब प्रणाली में शामिल किया जाए ताकि किसानों के ऊपर से आर्थिक बोझ कम हो सके। चेयरमैन सर, कोआपरेटिव सैक्टर के अन्दर किसानों का ब्याज माफ किया है।

इसी तरह से जो नॉन-एग्री के अन्दर गरीब लोगो को लोन मिलता हैं उसमें भी उन गरीबो को माफी मिलनी चाहिए। लेकिन उन गरीब लोगो को फायदा नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन लोगो का लोन भी माफ किया जाए जिससे उन गरीब लोगो को भी बहुत राहत मिलेगी। चेयरमैन सर, सरकार ने देहातों में 11 हजार सफाई कर्मचारी सफाई के लिए लगाए है। यह बात दर्शाती है कि हमारी सरकार की नीयत क्या है। चेयरमैन सर, एक वह भी समय था जब छोटे वर्गों की इतनी अनदेखी होती थी कि भायद कोई सोच भी नहीं सकता था। मुख्यमंत्री जी का यह फैसला कि देहांत के अंदर 100-100 गज के प्लाट्स गरीब आदमियों को दिए जाएंगे, बहुत ही सराहनीय है। लोगों में इसको लेकर खुशी की लहर है। मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं। चेयरमैन सर, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा के अंदर जो सरकार ने नीति बना रखी है उसकी भी बहुत ज्यादा प्रगति हो रही है। गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ सकें, उनको ज्यादा सहूलियतें मिल सकें, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है, मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है ताकि गरीब लोगो को लाभ पहुंचे सकें। मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। चेयरमैन सर, सिंचाई के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यमुना नदी हमारे जिले में से गुजरती है इसलिए इस बारे में भी ख्याल करने की जरूरत है क्योंकि यमुना नदी का जो बहाव है वह हरियाणा की ओर ज्यादा है तथा यू०पी० की ओर कम है। इस

बार पहाड़ी के अंदर पिछले बीस सालों के मुकाबले ज्यादा बर्फबारी हुई है इसलिए बरसात के दिनों में यमुना नदी में ज्यादा पानी आने की उम्मीद है। हमारे जिले में ऐसे हालात हैं कि हमारे यहां के कई गांव यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा पानी की आंका के दृष्टिगत यमुना नदी के किनारे पर हरियाणा की तरफ से स्टड्स यानी ठोकरे लगवायी जाए ताकि खेती की जमीन को बचाया जा सके और जो यहां पर गांव बसे हुए हैं उनमें ज्यादा नुकसान न हों, फसलें तबाह न हो। चेयरमैन सर, मुख्यमंत्री जी की अपार कृपा से पहली बार हमारे जिले में यमुना पारके किसानों के लिए हमने भी इसके लिए बहुत साथ दिया है ताकि लाईन वहा पर खड़ी की जा सके, बिजली के पोल खड़े किए जा सकें क्योंकि बरसात में पानी बहुत ज्यादा यमुना में आता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो वहां पर रीवर बैल्ट पर बिजली के पोल हैं उनके ऊपर पत्थर की ठोकरें लगायी जाएं ताकि फ्लड के टाइम परवे बह न जाएं। वैसे तो ये बीस फुट गहराई तक लगवाए गए हैं लेकिन फिर भी ज्यादा पानी की वजह से उनके बहने की आंका तो बनी ही रहती है क्योंकि यमुना नदी में ढाई लाख, तीन लाख या चार लाख क्यूसिक पानी आता है। उस दौरान वे लाइने वह न जाए ठोकरें लगाने का प्रबन्ध भी सरकार को करना चाहिए। ताकि बिजली की लाईन सेफ हो सकें। चेयरमैन सर, जहां तक इंडस्ट्रीज में सहूलियतें देने का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही उदारदिली दिखायी है। इंडस्ट्रीज को

प्रदे 1 में बढ़ावा मिले और प्रदे 1 तरक्की करे, इसके लिए सरकार ने बहुत काम किए हैं। चेयरमैन सर, कृषि तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सबको पता है जमीन तो उतनी की उतनी ही है रबड़ नहीं है जो बढ़ जाए जबकि परिवार बढ़ गए हैं और खेत छोटे रह गए हैं। इंडस्ट्रीज में अपने आप में एक मिसाल है और यह मिसाल ही रहेगी। अब बहुत भारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर आया है जबकि एक वह भी समय था जब हरियाणा से इंडस्ट्रीज उजड़कर राजस्थान, उत्तरांचल जिन्होंने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की सहूलियतें दी। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जगाधरी कांस्टीच्यूएंसी से चुनकर आया हूँ। जगाधरी एक बहुत पुराना इंडस्ट्रियल टाउन है। यह पीतल की इंडस्ट्री के नाम से मशहूर है लेकिन आज वहां पर पीतल की इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर खड़ी हुई है। चेयरमैन सर, उसका सबसे बड़ा कारण यही हैं, इन्होंने टैक्स और बिजली में अपने यहां के उद्योगपतियों को बहुत सहूलियत दी। हमारे यहां की पिछली सरकारें इतनी सहूलियत नहीं दे सकी जिसके कारण हमारी इंडस्ट्री पिछड़ गई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जगाधरी की मैटल इंडस्ट्री कम्पीट कर सकें। इस बात की गारण्टी मैं लेता हूँ कि रेवेन्यू हम जितना आज दे रहे हैं उससे कम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इससे हमारे यहां की इंडस्ट्री दूसरे प्रदेशों से मुकाबला कर सकेगी। सभापति महोदय, वैंट प्रणाली में कुछ खामियां हैं। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे एक आदमी 'ए' ने 'बी' से माल

खरीदा और उसको माल की पेमेन्ट कर दी और टैक्स की पेमेन्ट भी कर दी। 'बी' ने टैक्स ले लिया और अपनी दुकान बंद करके नयी दुकान खोल ली और वहां से चला गया। बड़ी अजीब सी यह स्थिति है कि जिस आदमी ने टैक्स भी दे दिया अर्थात् 'बी' को 'ए' ने टैक्स दे दिया ओर नोटिस 'ए' को ही आ रहा है, नोटिस 'बी' को नहीं आ रहा है। इस सिस्टम में बड़े सुधार की जरूरत है। जो आदमी पहले ही टैक्स दे चुका वह किस बात का टैक्स दे। उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जिसने टैक्स लेकर खा लिया और खजाने में जमा नहीं कराया। मैं वित्त मंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि इस खामी में सुधार के लिए ऐक्ट में भी चेज है वह बेमिसाल है। पिछले चालीस वर्ष का इतिहास इस बात का गवाह है कि बिजली के मामले में क्या क्या होता रहा। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यमुनानगर जिले में किसी सरकार के राज में आज तक कोई बिजली के उत्पादन की इकाई नहीं लगी थी, आज की सरकार के समय में इकाई लगी भी है ओर एक इकाई फव इन भी कर रही है और दूसरी इकाई चलने के लिए तैयार है। मेरा आपके माध्यम से सराकर से अनुरोध है कि यमुनानगर की बिजली के उत्पादन के लिए तीसरी इकाई भी लगनी है उस तीसरी इकाई का काम जितनी जल्दी हो सके, भुरु किया जाए।

श्री सभापति : अब आप वाइंड अप करें।

श्री सुभाश चौधरी : म्युनिसिपल सिटीज के अंदर डिवैलपमेंट ने हाउस टैक्स माफ किया, उसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूँ। मेरा भाहर भी 'ए' क्लास सिटी है। मेरे भाहर के अंदर भी एक म्युनिसिपल पार्क बनाया जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने जनरल हॉस्पिटल को 40 से 60 बैड का अस्पताल करने की बात कही थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरे यहां के अस्पताल को 40 से 60 बैड का भीघ्न करवाया जाए। पीने के पानी के बारे में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि गांवों में पीने के पानी के ट्यूबवैल 'स्वच्छ जल धारा' योजना के अन्तर्गत बने हुए हैं। इनका बिल पंचायतें देती हैं लेकिन आज हालात यह हैं कि लोग बिल देते नहीं हैं और बिजली बोर्ड उनके कनेक्शन काट देता है या बिजली ही नहीं रहती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि 'स्वच्छ जल धारा' योजना के तहत सरकार उनको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू चलवाये। सरकारी कर्मचारियों के बारे में वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके बारे में और ज्यादा फिखादिली से सोचें और उनको और ज्यादा सहूलियतें दे। They are also part and parcel of the Government. हरियाणा प्रदेश के 40-50 हजार कर्मचारी हैं इनकी सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए। बेरोजगारी भता नौजवानों का बढ़ाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने छछरौली के अन्दर सरकारी कॉलेज बनाने से जल्दी से जल्दी बनाया जाए। छछरौली में अब कोई रैस्ट हाउस नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से

अनुरोध है कि सरकार छछरौली में रैस्ट हाउस जल्दी बनवाये। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री साहिदा खान(तावड़) : चेयरमैन सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभापति महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में कानून-व्यवस्था पहली चीज है। आज मेवात में निर्दोश लोगों पर केस लाद दिया जाता है और वहाँ पर जो अधिकारी हैं वे चुप बैठे रहते हैं। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में आई हमेवात में यह लिखा हुआ नजर आता है, " नकली सोने की ईंटों से सावधान, हरियाणा पुलिस"। जब वहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और जो अधिकारी हैं वे भी पूरे तरीके से ध्यान नहीं देते तो फिर वहाँ पर गुण्डे आदमी और बढ़ जायेंगे जबकि सरकार भय मुक्त प्रशासन की बात कहती है। (विधन)

श्री नरेन्द्र कुमार प्रधान (बादली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो ये गुण्डाराज की बात कर रहे हैं तो गुण्डाराज तो इनकी सरकार की देन है। जब पिछली सरकार आई थी उस समय से गुण्डाराज चला आ रहा है। इनकी सरकार के समय जेलों के अन्दर रैस्ट हाउस जैसा माहौल बना दिया था। गुण्डों को सिक्क्योरिटी देकर मिमला तक घुमाकर लाया जाता था। आज कानून व्यवस्था की बात करते हुए इन्हे भार्म आनी चाहिए।

श्री साहिदा खान : चेयरमैन सर, माननीय सदस्य डायरेक्ट यह नहीं कह सकते कि भार्म आनी चाहिए। मेवात यहां से ज्यादा दूर नहीं है सिर्फ 325 किलोमीटर है। तीन साल पहले यह सरकार आई थी जब दोशियों को सरकार सजा न दे तो हमारी क्या गलती है। (इस समय माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि कृषि की बात हो रही है। आज किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो चुका है। बार-बार यह कहा जाता है कि गेंहूं का रेट एक हजार रुपये करदिया है। मानते हैं कि इससे किसान को फायदा होगा। किसान आज कर्जे के बोझ से इतना दब गया है कि डी०ए०पी० और यूरिया का खाद उसे समय पर नहीं मिलता लम्बी लाईन लगानी पड़ती है। फिर भी खाद पूरे तरीके से किसानों को नहीं मिल पाती है। बल्कि ब्लैक में मिलती है। इससे किसान ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। अगर कोई मजदूरी के लिए चला जाए तो उसको सवा सौ रुपये दिहाड़ी से ज्यादा नहीं मिलता, इस प्रकार वह लगातार महीना भर जाएगा तो 3200 रुपये उसके बनते हैं। महीने में से कम से कम 22 दिन काम करते हैं ओर बाकी के 8 दिन मिस्त्री की दिक्कत आने से, छुट्टी पड़ जाने से ओर ईट आदि मैटीरियल न होने की वजह से निकल जाते हैं। 3000 रुपये में गरीब आदमी अपना गुजर बसर नहीं कर सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बात कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपरी पूरा विचार करें। पानी के लिए यहां बार-बार बात होती है। मेवात के बारे में कहा गया है कि यह नहर तैयार हो जाएगी तब मेवात में पानी आएगा।

गुड़गांव कैनाल में जो आलरेडी पानी चल रहा है वह 200-250 क्यूरिक के आस पास है जबकि इस नहर की कैपेसिटी 3000 क्यूसिक की है। फरीदाबाद, गुड़गांव के सभी सम्मानित सदस्य बैठे हैं और इनको पता है कि इस नहर में 200-250 क्यूसिक से ज्यादा पानी नहीं है। पूरा फरीदाबाद, मेवात और गुड़गांव इस नहर से जुड़ा हुआ है और उसी के ऊपर निर्भर करता है। मैं समझता हूँ कि तालाबों में भी यह पानी जा सकता। पिछली सरकार में कम से कम यह तो था कि तालाब तो भरे होते थे चाहे वे किसी भी तरह से भरे होते थे। अध्यक्ष महोदय, हालात यह है कि वहां दिन प्रतिदिन सूखें का सामना करना पढ़ रहा है। गरीबों के लिए एक नई बात आ रही है कि 100-100 गज के प्लांट मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ और इस स्कीम का स्वागत करता हूँ। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि लोगों को प्लांट तो तभी मिलेंगे जब इनके नाम बी०पी०एल० में रहेंगे। बी०पी०एल० में जो धांधली हुई है वह सबके सामने है। सभी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं कि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। अभी कल परसों हमारे मेवात के डी०सी० ने एक पटवारी को सस्पेंड भी किया है। इस मामले में बहुत धांधलियां हो रही हैं, इस बात को सरकार ने और प्रशासन ने मान भी लिया है। गरीब लोगों को इस स्कीम का लाभ तभी मिलेगा जब उनका नाम बी०पी०एल० में होगा। जब बी०पी०एल० नाम की चीज नहीं होगी तो प्लांट क्या, कुछ भी नहीं मिल सकता। बी०पी०एल० स्कीम के तहत जो गुलाबी

कार्ड ओर पीले कार्ड बने हुए थे उससे गरीब आदमी को अनाज और चावल मिलते थे जिससे वे अपना गुजर बसर करते थे ओर अपाहिज पेट भर खाना खा सकते थे। (गोर एवं व्यवधान)मैं लोगों की समस्या यहां बता रहा हूं न कि कमान के लिए यह बात कह रहा हूं।

श्री नरे । कुमार प्रधान (बादली) : अध्यक्ष महोदय, सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि बी०पी०एल० से प्लाट का कोई सम्बन्ध नहीं है। (गोर एवं व्यवधान) सभी जातियों के लोगों को प्लांट मिलेंगे।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की बात है, हमारे तावड़ हल्के में नहर का पानी नहीं आता। तावड़ ब्लॉक और आस-पास के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे यहां न तालाब हैं और न ही जोहड़ हैं। इसी तरह मेवात में दो जगहें भयाना और सराज भी हैं जहां पानी नहीं है। हमारे तावड़ ब्लॉक में तो कम से कम ट्यूबवैल लग सकता है क्योंकि डेढ़ इंची के लगभग पानी लगता है और उसमें भी 10-10,15-15 बार ट्रिपिंग हो जाती है। लोग बार-बार फोन करते हैं और हमें रात भर सोने नहीं देते। बिजली के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि हम मानते हैं कि सरकार के पास पूरी बिजली नहीं है लेकिन सरकार जितनी भी बिजली दे उसमें ट्रिपिंग न हो। बिजली लगातार आ जाये और रात के समय लगातार चलती रहे तो अच्छा रहेगा क्योंकि दिन में हवां चलती है और गेहूं खराब हो जाती है।

बिजली के नाम की हरियाणा में चीज नहीं रह गई है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा। मेवात में पेयजल के लिए 'राजीव गांधी पेयजल संवृद्धि' परियोजना लागू हुई है। सरकार को मैं अपनी तरफ से सुझाव देना चाहूंगा कि कोटला झील का काफी बड़ा एरिया है वहां से यह प्रोजेक्ट पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए भुंरु हुआ था। कोटला झील में 10 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। यमुना में बरसात के दिनों में जो फालतू पानी आता है अगर उस फालतू पानी को इस झील में डाल दिया जाए तो हमारा वाटर लैवल कम से कम 20 फुट ऊपर उठ सकता है क्योंकि हम वहां से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। इससे मेवात में सिंचाई अच्छे तरीके से हो सकती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बरसात के समय में बरसात के पानी को इस नहर में डालने की व्यवस्था की जाये। इसके अतिरिक्त सरकार ने कहा था कि उस जमीन को एक्वायर किया जायेगा और किसानों को मुआवजा दिया जायेगा। इस तरफ भी सरकार ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से मेवात जिले में शिक्षा का ग्रॉथ गिरता जा रहा है। मेवात में जिला हैड क्वार्टर बने हुए तीन-चार साल हो गए लेकिन वहां पर एक भी सरकारी सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। वहां पर एक हिंदू हाई स्कूल है और एक मेव डीग्री कॉलेज है जो कि दोनों ही प्राइवेट है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की तरफ तभी ध्यान दिया जा सकता है जब स्कूल होंगे। आज के दिन प्रदेश में मास्टर्स की जो हालत बनी हुई है

उसके बारे में सभी को मालूम है। मास्टरो के ऊपर नंगी तलवार लटकी हुई है। जो गैस्ट टीचर है वे अपनी नौकरी के लिए हर रोज स्ट्राईक करते हैं जिसके बारे में सभी को जानकारी है। यदि इसी तरह की स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक जारी रही तो शिक्षा का स्तर पूरे प्रदेश में गिरता जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेवात में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। मेवात हमें 11 से पिछड़ा हुआ एरिया रहा है और अब भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आगे भी पिछड़ा ही रहेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने बजट अभिभाषण पर बोलते हुए सबसे पहले भय, आतंक और सुरक्षा की बात की है। सोहना, तावड़ और मेवात एक साथ लगता हुआ क्षेत्र है। इस बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इनकी सरकार साढ़े पांच साल तक प्रदेश में रही। उस समय कानून व्यवस्था की प्रदे 1 में क्या हालत थी यह सभी को मालूम है। उस समय दस-दस जिप्सियां एक साथ ले जानी पड़ती थी। अध्यक्ष महोदय, सोहना मेवात से जुड़ा हुआ एरिया है उस समय वहां पर एक-एक गांव से एक रात में दो-दो गाड़ियां चोरी हो जाती थी। यदि कोई बैंक के बाहर अपनी मोटर साइकिल खड़ी करके बैंक से

पैसे निकलवाने जाता था तो बाहर से उसकी मोटर साईकिल चोरी हो जाती थी। उस समय गऊ माता की हालत भी बहुत खराब थी जिस प्रकार से सीमेंट के कट्टे को हम उठाकर डालते हैं उस तरह से उस मसय गऊओं को उठाकर डाला जाता था।

बैठक का स्थगन

Mr.Speaker : Hon'ble Members, as the sound system in the House is not properly working, the House is adjourned for 15 mintues.

(The Sabha hten adjourned at 4.18 P.M. and re-assembled at 4.33 P.M.)

वर्ष 2008—2009 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

Mr.Speaker : At the time of the adjourment of the sitting, Shri Jaunapuna was on his legs. He may continue his speech.

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया(सोहना) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कानून और व्यवस्था के बारे मे बता रहा था कि इस मौजूदा सरकार के आने से पहले पिछले साढ़े पांच साल के दौरान कानून व्सवस्था का इतना बुरा हाल था और यह नौबत थी कि चाहे कहीं कितना भी बड़ा हादसा हो जाये और अगर कोई थाने मे कम्पलेट लिखवाने जाता था तो कोई एफ०आई०आर० नही लिखी जाती थी जब तक कि ऊपर के आदे ा न आ जायें। सबसे

बड़ी बात यह थी कि सोहना, तावड़ और मानेसर ये तीन पुलिस स्टेशन ऐसे थे कि इन तीनों थानों में भाम को 4 बजे तैयारियां की जाती थी और सुबह 10 बजे तक जितना भी पहाड़ों में जो ईललीगल काम था वह सारा उस समय के दौरान होता था और इससे जितना रात को पैसा इकट्ठा होता था वह सारे का सारा ऊपर भेजा जाता था। यह नौबल पूरे साढ़े पांच साल रही। आज इन तीन सालों के अन्दर हम बड़े गर्व और फर्क के साथ कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा जिसे कोई ईललीगल साबित कर दे। उस समय सबसे बड़ी बात यह थी कि रोड के ऊपर चलते-चलते जो 10 टायरों की गाड़ियां होती थी उन 10 टायरों वाली गाड़ियों के ड्राइवर और कण्डक्टर को बांध कर गाड़िया चोरी हो जाती थी और उसके बाद तक उनकी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं होती थी। यू०पी० में गुलावटी के पास एक गांव है उसमें एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा था। मेवात से उसकी सीधी रिश्तेदारी है। प्रशासन के साथ भी मेरी कई बार मीटिंग हुई और तब जाकर वह पूरा गिरोह पकड़ा गया। उनके पास से बहुत बड़ी मात्रा में मोटर साइकिल, बड़ी गाड़ियां, ट्रक इत्यादि पकड़े गये थे। प्रशासन ने थाने में लिस्ट लगा रखी थी कि अपनी-अपनी गाड़ियां की पहचान कर गाड़ी ले लें। अभी फिरोती की बात चल रही थी। गुड़गांव एक ऐसर भाहर है जिसमें पूरे प्रदेश के आदमी रहते हैं। उसके बावजूद भी साढ़े 5 साल जिस आंतक से वे जी रहे थे कोई आदमी अपने आपको

सुरक्षित नहीं मानता था लेकिन आज मैं पूरे फर्क से कह सकता हूँ कि आज किसी आदमी से कोई फिरोती नहीं मांगी जाती। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ कि 3 साल की अवधिके ही बहुत से मामले डीक किये हैं वरना यह मामला बहुत बिगड़ चुका था। सबसे बड़ी बात जो केन्द्र ने, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक ऐसा अनोखा काम किया है कि किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किये हैं। इसी सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले की भुरुआत भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही सबसे पहले की थी। चाहे पहले बिजली के 1600 करोड़ रुपये के बिलों की माफी का मामला हो, चाहे 830 करोड़ रुपये के आम गरीब आदमी के ब्याज का मामला हो। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए केन्द्र सरकार ने भी 60 हजार करोड़ रुपये के किसानों के कर्जे माफ किये हैं। उससे गरीब किसानों को राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव जिले में 17 गांव ऐसे हैं जिनकी तरफ हुड्डा का पैसा बकाया है। क्योंकि जमींदार की बात चल रही है, उनका केस हाई कोर्ट में चला गया था और उसमें हुड्डा जीत गया था और किसान हार गए थे। उस समय इन 17 गांव के लोगों से चौटाला जी ने पब्लिक के बीच में बैठ कर यह वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी और मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें कोई पैसा वापिस जमा नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब सरकार बन गई और उन लोगों ने झाडसा में इक्कठे हो कर

चौटाला जी से यह बात कही कि अब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं हमारा 17 गांवों का 400 करोड़ रुपया जो हमें हुड्डा में वापिस जमा करवाना है उससे निजात दिलवा दें तो चौटाला जी ने 90-90 साल के लोगों को घोड़ा पुलिस पीछे लगा कर सोहना तक दोड़ा-दोड़ा कर पिटवाया था। उनकी पगड़ियां तथा जूतियां तक लूट ली गईं जो कि सम्मान की निशानी होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का आश्वासन चाहूंगा कि जब प्रदेश के किसानों को इतनी राहत दी जा रही है और अगर उन गांवों के किसानों को भी राहत न दी गई तो हमारी तो आपस में रिश्तेदारी भी खराब हो जाएगी चूंकि जो जमीन मुआवजे के रूप में रखी हुई थी वह छुट नहीं सकती। अगर वे लोग अपना सब कुछ भी बेचें तो भी अपनी जमीन नहीं छुड़वा सकते। उनके रिश्तेदारों ने अपनी जमीन गिरवी रख कर यह जमीन छुड़वाई है। अगर मुख्यमंत्री जी की कृपा हो जाए तो उन बेचारे लोगों की जमीन फ्री हो सकती है और हमारी रिश्तेदारी टूटने से बच सकती है। यह बहुत बड़ी राशि भी नहीं है, केवल 400 करोड़ रुपए हुड्डा का बकाया है वह माफ कर दिया जाए और जिन्होंने जमा करवा दिया है उनको भी राहत दी जाए ताकि वे भी अपनी बेटियों को घर से अच्छी तरह से विदा कर ससुराल भेज सकें और उनके रिश्ते बचे रह सकें। यह वादा मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। स्पीकर सर, प्रदेश के सभी वर्गों को छूट मिलती जा रही है। स्पीकर सर, पिछली बार मैं गांव में गया था वहां पर जमींदार भाहरी ब्राह्मण धोलीधार है। उस समय वहां

पर एक ब्राह्मण सभा थी वहां पर उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आज कल सरकार सभी वर्गों के बारे में सोच रही है मगर पंडितों ने ऐसा क्या बुरा किया है जो हमारे प्रति कोई सोच नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि अगर आपकी बात ठीक है तो मैं आपकी बात को विधान सभा में उठाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, वे लोग कई-कई सालों से वहां पर बैठे हैं उन पंडितों को भी अधिकार दिया जाए कि वे अपनी जगह ले सकें। वे लोग वहां पर तीस साल से ज्यादा समय से बैठे हैं। स्पीकर सर, कोर्ट ने भी यह बात कही है कि जो मालिक है उसका कबजा है उसी का मालिकाना हक भी है इस लिए उनको उनका हक दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जीसे यह निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर भी गौर करें जो पंडित धोलीधार बैठे हैं। उनको भी उनका हक मिलना चाहिए ताकि वे भी अपनी जमीन खरीद सकें, जोत कर सकें क्योंकि उस पर उनका हक बनता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी और अहम बात यह है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुड़गांव और फरीदाबाद ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको सारे हरियाणा में माना जाता है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने मैट्रो रेल की भुरुआत वहां पर करवाई है और मैट्रो के लिए उन्होंने काफी पैसे का भी प्रावधान किया है। मैं इस बात को थोड़ा और आगे लेजाना चाहता हूँ कि गुड़गांव तक तो ठीक है लेकिन गुड़गांव के अंदर लाखों लोग हर रोज मानेसर, आई.एम.टी. तथा बावल तक जाती है। अगर मैट्रो रेल को मानेसर तक बढ़ा दिया जाए या बावल तक बढ़ा दिया जाए तो

इससे लोगों को बहुत ही फायदा होगा और लोग वक्त पर अपनी फ़ैक्टरियों में पहुँच सकेंगे तथा इससे ट्रैफिक भी कन्ट्रोल हो जाएगा। जो लाखों गाड़ियां डेली मानेसर तक जाती है वे बन्द हो जाएगी और उनसे भी बचत हो सकेगी। सड़क और परिवहन के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि गुड़गांव में जो पुराने सैक्टरज है वहां तक तो लोकल बस है लेकिन राजीव चौक से सैक्टर 50, 55 तथा सैक्टर 56 में जो लोग जाते हैं उनके लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं है। गरीब आदमी रिक्शा में वहां तक जा नहीं सकता और अपनी गाड़ी भी नहीं है जिसके कारण उनको काफी दिक्कत का सामना करता पड़ता है। सरकार ने काफी सरकारी बसें खरीदी है इसलिए अगर उन सैक्टरों के लिए बस का इन्तजाम हो जाए तो इससे उन लोगों को काफी फायदा मिल सकेगा। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ मैं एक बात होस्पिटल के बारे में भी बताना चाहता हूँ। गुड़गांव एक ऐसा क्षेत्र है जहा पर सारी चीजें बहुत जरूरी है। मैं यहा पर यह बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम ऐम्ज जैसा हास्पिटल बनाना बहुत जरूरी है। आज आबादी बढ़ती जा रही है और हर बात के लिए हमारे लोगों को ऐम्ज में जाना पड़ता है। मेरा यह निवेदन है कि वहा पर ऐम्ज जैसा हास्पिटल का होना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ 3510 रूपए जो मजदूरी लागू की गई है वह छोटी बात नहीं है। किन जगहों पर यह लागू हो गई है इस बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन बहुत जगहो पर यह लागू हो गई है इसकी भुर्रुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी

ने ही की थी इससे आम आदमी को काफी मदद तो नहीं मिल पाएगी लेकिन 1000/- जब वह अपने परिवार में ले कर जाएगा तो उससे उसके परिवार को बड़ी राहत मिलेगी। अगर वह किराए के मकान में रह रहा है तो 100-50 रूपए उसका किराया बढ़ने से उसके मकान मालिक को यानि जमीनदार को फायदा मिलेगा और उनके बीच का जो गैप है वह इससे खत्म हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, जहा तक बिजली की बात है, बिजली को ग्रहण लगा हुआ है प्रदेश में बिजली की बड़ी दिक्कत है। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी भांरुआत भी की है। मगर भांरुआत जो की गई है हम समझते है कि आने वाले अढ़ाई तीन साल से पहले पूरी बिजली लोगों को नहीं मिल सकेगी। जैसे कि पिछली बार भी फसलों के लिए बिजली पूरी नहीं मिली थी जिसके कारण फसलों को नुकसान हुआ था। पिछली बार की तरह इस बार भी एक बार भी बारिश नहीं हुई। पहले सर्दियों में बारिश हो जाती थी लेकिन इस बार वह भी नहीं हुई है। जिसके कारण बिजली की पूर्ति में कमी हो रही है। बिजली की आपूर्ति बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इतना जरूर हुआ है कि ट्रांसफार्मज, खम्भे और तार की कोई कमी नहीं है। पहले जब कोई ट्रांसफार्मज जल जाता था या कोई तार टूट जाती थी तो छः-छः महीने तक लोग रोते रहते थे और वह बदले नहीं जाते थे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज कोई अधिकारी यह नहीं कह सकता है कि ट्रांसफार्मज की कमी है या तार अथवा खम्भे नहीं है। आज इसकी सारी व्यवस्था ठीक है लेकिन बिजली

की सप्लाई की कमी है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली चाहे किसी भी रेट पर मिले वह खरीद कर प्रदेश के लोगों को दी जाए।

श्री अध्यक्ष : अब आप कन्कलूड करें क्योंकि और सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : स्पीकर सर, मैं पांच मिनट में कन्कलूड कर लूंगा। सिंचाई के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पिछले 4-5 दिनसे गुड़गांव में पानी की भारी किल्लत है। इस बारे में मैंने सिस्टम यह हो सकता है कि गुड़गांव कैनल के लिए दमदमा झील में पानी का स्टोरेज किया जा सकता है। हमने पानी के टैंकर गुड़गांव में से सभी जगहों से मंगवा लिए हैं लेकिन फिर भी वहां पर पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। अगर आगरा कैनल से दमदमालेक में पानी दे दिया जाए तो उससे गुड़गांव के पीने के पानी की दिक्कत खत्म हो सकती है। यह नहर एक या डेढ़ किलोमीटर लम्बी ही बननी है और उसके लिए जमीन एक्वायर की हुई है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। यह जो पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था है इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 40 सालों में एक गांव में एक ट्यूबवैल ही हुआ करता था और आज इस सरकार के आने के बाद एक गांव में चार-चार, पांच-पांच या छः-छः ट्यूबवैल हो गए हैं, लेकिन अगर वहां पर बिजली चली जाए तो लोगों को

पानी नहीं मिलता है। अगर बिजली होगी तो ही पानी की पूर्ति हो पाएगी इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बिजली की भी समुचित व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के सोहना भाहर में गर्म पानी निकलता है और लोग उसको या तो बर्फ से ठण्डा करते हैं या फिर फ्रिज में लगा कर पाने के लायक ठण्डा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पानी की प्रोब्लम को दूर करने के लिए एन०सी०आर० में 65 करोड़ रूपए सैंकान किए हुए है। आप इस पैसे को दिलवा दें तो वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़क और पुलों की बात करना चाहूंगा। यह ठीक बात है कि आज हरियाणा में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मेरे हल्के सोहना में सोहना रोड को अलवर तक डबल कर दिया जाए, जो कि मंजूर भी हो गया है। इसी तरह से अंधेरिया मोड से रोड बननी है जो कि बाया जौनपुर माण्डी होते हुए गंडगांव को जाएगी। दूसरी रोड बसन्त कुंज थाने से आयानगर बार्डर पर मिलेगी, उस बारे में अभी तक अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अगर अधिकारी इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो इस सड़क का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। अध्यक्ष महोदय, पलवल से रेवाड़ी 17(b) नैशनल हाईवे बना हुआ है और इस सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है जिसकी वजह से वह सड़क टूट गई है उसको भी रिपेयर करवाया जाए। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव से फरीदाबाद की जो सड़क है वहां पर भी ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से जाम लगा रहता है इसलिए इस सड़क को डबल किया जाए ताकि वहां पर ट्रैफिक

व्यवस्था ठीक हो सकके। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से राजीव चौक से खेड़की दौला तक टोल टैकस लगा हुआ है। वहां पर 10-12 गांव साथ में लगते हैं। अगर किसी का रि तेदार आ जाए और वह गलती से रास्ता भूल जाए तो उसको 16 किलोमीटर का चक्कर काटकर अपने घर जाना पड़ता है। अगर कोई सब्जी लेने के लिए जाए तो उसको 50 रूपए की सब्जी 500 रूपए में पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वे नै नल हाई-वे अथोरिटी से बात करें कि वहां पर अन्डर बाँय पास बनाया जाए ताकि वहां के गांवों के लोगो को सुविधा मिल सकें।

श्री अध्यक्ष : जौनपुरिया जी, आप बैठे। आपकी जो भी बाते हैं आप उनको लिखकर भेज दें। आनन्द सिंह डांगी जी, आप बोलें।

श्री आनन्द सिंह डांगी(मेहम) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, 18 मार्च, 2008-09 को वित्तमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने हरियाणा की जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए समाजिक एवं कल्याणकारी प्र ासन प्रदान किया है। पिछली सरकार के समय में जो भय, आतंक और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी गई थी, उस बारे में आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी और उनके साथी मंत्रियों के सहयोग से आज हरियाणा प्रदे ा में भांति और सामजस्य कायम

है, समाजिक सदभावना कायम है। किसी प्रदेश के राजा या मुख्यमंत्री का अपना जनता के प्रति सबसे पहला कर्तव्य होता है कि उसकी जनता में सदभावना हो, आपस में प्रेम हो, एकजुटता हो, एक भावना हो और हर प्रकार से भय मुक्त हों तथा एक दूसरे के प्रति हर तरह से लगाव बढ़े। अध्यक्ष महोदय, इसी का परिणाम आज यह है कि आज हरियाणा प्रदेश में हर व्यक्ति बढ़े सुख की नींद सोता है। पिछले भासन काल में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल था, गुण्डागर्दी का माहौल था, आतंकवाद का माहौल था उसको पिछले तीन सालों में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले खत्म करने का कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, यह होना भी चाहिए था। कानून व्यवस्था को ठीक करना भी एक बहुत बड़ा कार्य हमारी सरकार ने किया है। कानून व्यवस्था के बारे में आज हम बढ़े फर्क से कह सकते हैं कि आज हमारा प्रदेश उन्नति और तरक्की की तरफ अग्रसर है। अध्यक्ष महोदय, यह सारा काम किसी की नीति, नीयत और निश्ठा के बल पर होता है। नीति, नीयत और निश्ठा की सबसे पहले मुखिया को जरूरत होती है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने वह करके दिखायी है। अध्यक्ष महोदय, नीयत के साथ ही बरकत होती है और उसी का नतीजा आज है कि हरियाणा आजहर फील्ड में, हर लाईन में चहुंमुखी विकास की तरफ बढ़ते हुए गौरवमयी ढंग से बुलंदियों पर पहुंचने का कार्य कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह कार्य आपसी टीम के साथ मिलकर किया है जिसकी गूंज आज भारतीय संसद में गूंज रही है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश या देश

का विकास और तरक्की उसकी कानून व्यवस्था और उसकी अर्थ व्यवस्था पर निर्भर होती है। हमें आज इस बात के ऊपर बड़ा फर्क है कि ये दोनो हमारे प्रदेश में ठीक है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम आज का बजट और पिछले तीन सालों का बजट देखें तो वह यह दर्शाता है कि जहां तीन साल पहले इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ 2200 करोड़ रुपये का बजट हुआ करता था वह आज 6650 करोड़ रुपये का हो गया है। 6650 करोड़ रुपये का बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस हरियाणा प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक लगन के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। यह किसी के कहने की बात नहीं है। बल्कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज हरियाणा प्रदेश हिन्दुस्तान के मानचित्र पर एक अलग ही स्थान रखता है। चाहे विकास की वजह से हो या चाहे कानून की वजह से हो, हर तरह से पूरे प्रदेश में सदभावना और प्यार प्रेम है। हर तरह के भाई चारे के हिसाब से हमारा प्रदेश अलग है। यह सारे का सारा श्रेय हमारे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को जाता है। क्योंकि इनकी नीति, नीयत और निश्ठा बहुत अच्छी है और साथ ही उन्होंने टीम वर्क का सहयोग लेकर इस प्रदेश को हर तरह से आगे बढ़ने का काम किया है। हर तरह का सहयोग लेने की लगन उनमें है और वे इस बारे में प्रयत्नशील भी हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश

एक कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषक हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान अपनी मेहनत से हर किसी का पेट पालता है इसलिए यदि उस कृषक की मेहनत करके अपने प्रदेश और देश के लिए काम कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ जिसने कृषि के लिए और कृषक के लिए विशेष रूप से चाहे वह सबसिडी देने की बात हो, चाहे किसान को ऐग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटस के लिए उसकी और जिंस के अच्छे भाव देकर के किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने की बात हो, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि किसान की जिंस के लिए उन्होंने एक सही वक्त पर और सही समय व सही सीजन पर उसका सम्मानजनक मूल्य किसान को मिलता है आज किसान को गेहूँ का एक हजार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट मिला है यह भाव किसान ने सोचा भी नहीं था। इससे पहले जो सरकारें रहीं, किसी ने 10 रुपये भाव बढ़ा दिया किसी ने 5 रुपये बढ़ा दिया, या किसी ने 20 रुपये बढ़ा दिया। इस प्रकार के रेट बढ़ाकर उसको सम्मानित करने की बजाय बेइज्जत किया जाता था। आज की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी की रहनुमाई में, प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनसे किसान की जिंस के भाव के लिए आवाज उठाई और 1100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव की मांग रखी और उसका असर तीन दिन के अंदर सामने आया। तीसरे दिन ही यू.पी.ए. की सरकार ने एकदम से एक हजार रुपये प्रति क्विंटल के रेट की घोषणा की और एकदम से 350 रुपये प्रति

विंटल की रेट में बढ़ौतरी की। इस सरकार ने किसान को जो सम्मान दिया है, किसान को उसकी मेहनत का फल दिया है, यह काबिले तारीफ है। पंजाब खाद्यान्न उत्पादन में हमारे से आगे हुआ करता था लेकिन आज किसान की मेहनत की वजह से और पानी के ठीक ढंग से आज हरियाणा प्रदेश । कृषि क्षेत्र में पंजाब से आगे जाकर अच्छा नाम कमा रहा है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के और गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किए है वह पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल हैं। जिस तरह से उनको 100-100 गज के प्लॉट देने की बात कही है, यह बहुत बड़ी बात है। आज हरियाणा प्रदेश । की सरकार ने अनुसूचित जाति के गरीब भाईयों को अनुदान के रूप में, मदद के रूप में अपना जीवन ठीक ढंग से व्यतीत करने के लिए 100-100 गज के प्लॉट देने की बात कही है। यह गरीब आदमी को प्रोत्साहित करने वाली बात है। आज के दिन हम जमीन के भाव देखें तो वह आसमान छू रहे हैं। 100गज का प्लॉट आज के दिन चाहे कहीं भी ले लो उसकी कीमत एक लाख रूपये से कम नहीं है। यदि गरीब आदमी को इस तरह की राहत मिल जाए तो यह बहुत सराहनीय है। इसी प्रकार से किसान के लिए और हर गरीब आदमी के लिए भी ब्याज माफी की जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोशणाये कीं और उनको अमली जामा भी पहनाया तो यह भी गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। अध्यक्ष महोदय, आज किसान इतना अधिक दबा हुआ है उके खेत की जो उपज है उस उपज के हिसाब ससे वह अपने बच्चों का पालन पोशाण भी मुक्ति कल से कर

पाता है। खेती की अच्छी पैदावार लाने के लिए किसानों को कर्जा लेना आवेक हो जाता है लेकिन अगर उसकी अदायगी के वकत उसके ऊपर तरह-तरह के दवाब डाले जायें ओर जबरदस्ती वसूली की जाए तो किसान बेसहारा होकर अपने मन को मारकर बैठ जाता है। उसकी जो मेहनत होती है उस पर उसको पछतावा होता है लेकिन आज यू०पी०ए० की सरकार ने, श्रीमती सोनिया गान्धी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो 60,000 करोड़ रूपये की कर्जा माफी की घोशणा की है वह बहुत ही सराहनीय कदम है जिसकी पूरे किसान वर्ग में, हर समाज में जबरदस्त वाह-वाही हुई है। इससे किसानों को जबरदस्त राहत मिली है ओर एक हसैसला अफजाई हुई है। साहूकारों और आढ़तियों के ब्याज के लिए रोजाना सरकार की नीति और नीयत सुनने में आती है। साहूकारों और आढ़तियों से गरीब किसानों ने जो लोन ले रखे हैं या जो जरूरत के वकत अपनी जीन्स डालकर थोड़े से पैसे लेकर आता है उस पर ब्याज बढ़कर इतना कर्जा हो जाता है कि किसान और गरीब आदमी की बस की बात नहीं रहती कि वह उतार सके। आज मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को जो उनकी तरफ से यह बात आई है कि साहूकारों और आढ़तियों से जो कर्जा किसानों के ऊपर है उसको ठीक ढंग से निपटाने की जो बात आई है जिससे किसान भी बचेगा और साहूकार तथा आढ़ती जिनसे कर्जा ले रखा है उसके ऊपर भी आंच नहीं आयेगी। इतनी बड़ी सोच इतना बड़ा फैसला इतने अच्छे ढंग से इसका पिटारा करना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। इसके

लिए पूरी उम्मीद के साथ जल्दी कदम उठाकर हमारी सरकार ने गरीब भाईयों ओर गरीब किसानों को राहत दी है। मेरा निवेदन इस बारे में यह है कि जो गरीब तबके के लोग हैं जो छोटे-छोटे कामों के लिए लोन ले लेते हैं। जैसे भैंस के लिए या दूसरे कामों के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, बच्चों के पालन-पोषण के लिए लोन लेते हैं, मेहनत करके कमाता खाता है उसके लिए कर्जा लेकर अपना काम जोड़ रखा है, उनके ऊपर हमारी सैंटर की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट इस बारे में विचार करे ताकि उनको इसके लिए भी राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारी सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी के लिए बहुत बड़ा काम किया है।

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, आप कितना टाईम और बोलोगे ?

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर एड्रेंस पर भी नहीं बोला। आज मुझे बोलने का मौका मिला है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप तीन मिनट और बोलिए।

श्री आनन्द सिंह डांगी : तीन मिनट नहीं, तीस मिनट और दीजिए।

श्री अध्यक्ष : डांगी साहब, आप लिखकर दे दीजिए।

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आकड़ें तो बोल नहीं रहा, दूसरा लिखा हुआ हो तो ऐसी भी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आप पांच मिनट और बोल लें।
(विधन) डांगी साहब, आप बजट पर बोलें।

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सड़क-परिवहन के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत बढ़िया इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया है यह सब जनता के सामने है। विकास के बारे में अच्छी सड़कें देकर, परिवहन को अच्छे रास्ते देकर जो कार्य सरकार ने किया है वह बहुत ही सराहनीय है क्योंकि किसी भी प्रदेश के विकास और तरक्की अच्छी परिवहन व्यवस्था और अच्छी सड़कों से जुड़ी हुई है। यह बड़े फर्क की बात है कि आज हरियाणा प्रदेश में चाहे ओवर ब्रिज बनाने की बात हो, सड़कों की वाईडनिंग करने की बात हो, सड़कों की स्ट्रैथनिंग की बात हो, यह सब बड़े जबरदस्त ढंग से किया गया है। आज हरियाणा प्रदेश इस मामले में पूरे देश के अन्दर सबसे आगे है। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए न्यूनतम दिहाड़ी 3510/- रुपये मासिक करना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा इस मामले में सारे हिन्दुस्तान में सबसे अग्रणी है। यह श्रेय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है क्योंकि गरीब आदमी की मेहनत का अगर सही मूल्यांकन न हो और उसकी मेहनत का ठीक पैसा न मिले तो गरीब आदमी के आँसू ही निकलते हैं और वे आँसू ठीक नहीं

होते। जो गरीब आदमी के लिए मिनीमम मजदूरी 3510/- रुपये करने का काम किया गया है, वह एक सराहनीय कार्य है। समाज के कमजोर वर्गों व अनुसूचित जातियों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए और उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति शिक्षा प्रोत्साहन" नामक स्कीम के तहत एक क्रांतिकारी योजना शुरू की गई है। जो गरीब आदमी अपने बच्चों की फीस भरने की हिम्मत नहीं करता था आज हरियाणा की सरकार ने उनको अनूठा प्रोत्साहन दिया है जिससे मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा और ही व्यक्ति को पढ़ने का मौका मिलेगा। गरीब छात्रों को 100 रुपये से 300 रुपये प्रतिमास तथा छात्राओं को 150 रुपये से 400 रुपये प्रतिमास तक छात्रवृत्तियाँ देने का काम इस सरकार द्वारा किया गया है। यूनिफार्म, लेखन सामग्री तथा स्कूल बैग इत्यादि पर 740 रुपये से 1450 रुपये तक का जो खर्चा आता है, वह सारा खर्चा अनुसूचित जातियों के सभी विद्यार्थियों को देने का सराहनीय काम सरकार द्वारा किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बिजली की हमारे प्रदेश में बहुत कमी है, उन पिछली सरकार के लोगों की तरह से ये लोगों को बरगलाते नहीं क्योंकि ये लोग जहाँ कहीं भी जाते थे तो कहते थे कि 31 जनवरी के बाद हरियाणा की जनता को 24 घण्टे बिजली मिलेगी और फिर कहते थे कि 31 मार्च के बाद 24 घण्टे बिजली मिलेगी लेकिन 6 साल तक लोगों को बहकाकर इस प्रदेश में राज करके ये लोग चले गए लेकिन इन्होंने कभी कहीं एक यूनिट बिजली का

कारखाना लगाकर इस समस्या का समाधान करने के बारे में नहीं सोचा। मगर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस समस्या को हरियाणा प्रदेश से जड़मूल से खत्म करने के लिए झाड़ली में, खेदड़ में, झज्जर में और यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए जो कार्य किए हैं वह जबरदस्त सराहनीय कार्य हैं और यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जो नीयत से काम करता है और जिसकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जनता ने जिसका साथ दिया होता है और कुछ करने की बात जिसके दिमाग में होती है, अपने फर्ज को निभाने की जिसमें बात होती है। हरियाणा की जनता इसके लिए हर कदम पर सरकार को बधाई देती है और सरकार की सरापहना करती है। आने वाले वक़्त में हमें पूरी उम्मीद है कि इस समस्या का जड़मूल से समाधान हागौं ये काम वही करता है जो जनता के प्रति जवाबदेही रखता हो। जनता के साथ झूठे वायदे जो आज हमारे सामने बैठे इन लोगों का हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जहा तक सिंचाई की बात है तो सिंचाई के मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री की रहनूमाई में एक लम्बा संघर्ष हरियाणा की जनता ने किया है और उस संघर्ष का मतलब एक ही था कि हरियाणा प्रदेश के किसान को पानी के मामले में जहां उसका जितना हक बनता है वह हक मिले। नहरी पानी और पीने का पानी भी उसको उतना मिले जितना उसका हक बनता है। आज पूरा हरियाणा इस बात के लिए मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता है और पूरा हरियाणा एक स्वर में आज मुख्यमंत्री महोदय के साथ खड़ा है। जहां जिसका जितना पानी का हक बनता था उतना पानी

देने का कार्य इस सरकार द्वारा किया गया है। और इस काम को अमली जामा पहनाने के लिए दो-तीन नहरों की भूखूआत की गइ जैसे हांसी-बुटाना-लिक नहर और दादूपुर- गहबाद-नलवी और नीयत और लगन से काम किया गया है, वह बहुत ही सराहनीय कार्य है इससे किसानों को एक नई रो पानी मिलेगी ओर किसानों को पेट भरने के लिए नया रास्ता और ताकत मिलेगी। जो ये लोग दोगली बाते करते हैं, सदन में कुछ कहते है और सदन से बाहर कुछ कहते हैं, जैसे सदन में कहते हैं कि हम इसका विरोध नही करते और सदन से बाहर जाकर उसी वक्त प्रैस में कुछ और कहते है। एक बेटा कहता है कि खून की नदिया बह जाएगी लेकिन पानी नहीं आने देंगे। जब श्रीमान से बेटे के बारे में पूछा जाता है कि आपके बेटे ने यह बात कही है या नहीं तो वे उस बात से मुकर जाते हैं ओर ऐसा आभास होता है वे अपने बेटे के बारे में भी कुछ भाक सा जाहिर करते है। यह तो एक रीति है क्योंकि आदमी वह छूटनी आसान नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते है कि जिस समय चौधरी देवी लाल जी प्रदे ग कके मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उड़े सम्मान के साथ प्रदे ग की बागडोर सम्भाल रखी थी। उस समय ओम प्रका ग चौटाला ने बहुत बड़ा कलंक उन पर लगाया था जिसके कारण चौधरी देवी लानल जी को मजबूरन ऐसी बात कहनी पड़ी थी जो आज चौटाला जी अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं। आज भी प्रदे ग में वहीं हालत बने हुए है। ओम प्रका ग चौटाला अपने बेटे के बारे में स्पष्ट बात नहीं कर पाये। इस बारें में प्रदे ग के लोंगों के

लिए सोचने वाली बात है। इस तरह के लोग जनता को बार-बार झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। इस तरह के लोग जनता को बार-बार झूठ बोलते हैं और जनताको गुमराह करते हैं। इस तरह के लोग जनता से झूठ बोल कर वोट लेते हैं और अपना राजनैतिक तंत्र स्थापित करने की कोशिश करते हैं लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने प्रदेश में चारों तरफ विकास कार्य किए हैं जो अपने आप में मिसाल हैं। आज के दिन प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। आने वाले समय में दूसरे प्रदेशों के लोग हरियाणा प्रदेश की तरक्की को, यहां होने वाले विकास कार्यों को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने जनता को मुहैया करवाया है उसको देखने के लिए आएंगे। अगर किसी प्रदेश की सरकार की नियत ठीक होगी तो वे हमारा अनुसरण भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक हफ्ते से बजट पर अनेकों बातें कई माननीय सदस्यों ने रखे हैं लेकिन मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भाहरी तर्ज पर सरकार गांवों का विकास करने जा रही है वह अपने आप में एक मिसाल है। मौजूदा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का चहूमुखी विकास करने तथा भाहरी क्षेत्रों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 91 गांवों का चयन आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त गरीब आदमियों के घरों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने

एक अनूठी योजना चलाई है जिसके तहत गरीब आदमियों को मुफ्त में पानी के कनेक्टर्स के साथ टूटी और पानी की टंकी भी दी गई है ताकि गरीब आदमियों के घरों में भी पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके और उनकी सेहत भी ठीक रहे। जबकि पिछली सरकारों के समय में गरीब आदमियों के पूरे मौहल्ले में पानी की एक टूटी भी मुश्किल से मिलती थी। गरीब आदमियों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए पहले किसी ने नहीं सोचा। पहली बार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब आदमियों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की पहल की है और बहुत अच्छा प्रोत्साहन गरीब आदमियों को देकर उनकी काया-कल्प करने का काम किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के उत्थान के लिए 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति गांव उत्थान एवं मलिन बस्ती विकास योजना' नामक नई स्कीम शुरू की है। जिसके तहत वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या वाले सभी 391 गांवों में 50 लाख रुपये प्रति गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए खर्च किए जायेंगे जिससे प्रदेश के अंदर बहुत बढ़िया और स्वच्छ वातावरण पैदा होगा तथा प्रदेश के हर आदमी को अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त गांवों से गंदगी दूर करने के लिए और स्वच्छता लाने के लिए पूरे हिन्दुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अनूठा प्रोग्राम हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि प्रदेश में 11000 सफाई कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे जोकि गांवों में स्वच्छता की

स्थिति को सुधारने में लाभप्रद साबित होंगे। इस स्कीम के तहत 11000 गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे उनको रोजी-रोटी भी उपलब्ध होगी। अध्यक्ष महोदय, एक सफाई कर्मचारी को 3500 रुपये प्रति माह के हिसाब से सैलरी दी जायेगी। यदि किसी को अपने ही गांव में, अपने ही घर में 3500 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिल जायें तो मैं समझता हूँ कि वे 3500 रुपये 35000 रुपये के बराबर हैं। अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में हमें हर गांव में सफाई नजर आयेगी और प्रदेश के लोगों को स्वच्छ वातावरण रहने को मिलेगा जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा तथा लोगों को बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के तहत इच्छुक व्यक्तियों को गावों में या गांव के निकट एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए न्यूनतम दिहाड़ी पर रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। पहले यह स्कीम दो जिलों में चल रही थी अब पूरे प्रदेश में इस स्कीम को लागू किया जायेगा। इसी प्रकार से भाहरी विकास में भी किसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवा के लिए और दूसरे सभी महकमों के लिए सरकार ने वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, विकलांगों के लिए पैसे इन का प्रावधान किया है और यहां तक कि किन्नरों के लिए और बौनों के लिए भी मौजूदा सरकार द्वारा पैसे इन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ऐसे परिवारों के लिए जिनमें केवल लड़कियां हैं, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत इनको इतना जबरदस्त प्रोत्साहन दिया गया है कि आज गरीब आदमी अपने बच्चों को बोझ नहीं

मानता। इसी प्रकार से गीब परिवारों की लड़कियों की भादी के लिए 15 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। जबकि इससे पिछली सरकार द्वारा इसके अन्तर्गत केवल 5100 रुपये ही बड़ी मुकिल से दिये जाते थे। वह जो गरीब कन्याओं के लिए सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है इससे एक गरीब आदमी 15 हजार रुपये में अपनी बच्ची के हाथ पीले करके अगल घर भेज सकता है और सुख भांति से अपना गृहस्थ जीवन चला सकता है। यह एक बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कार्य है। इसी तरह से महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार द्वारा लाडली पैँान योजना भुरू की गई है उसी के तहत यह 15 हजार रुपये वाली बात भी आती है। इसी प्रकार से उद्योग धंधों में 33 हजार करोड़ रुपये का निवेँा आज हमारे प्रदेँा में होने लग रहा है और बाहर से यहां पर लोग उद्योग लगाने के लिए अग्रसर है जिससे 66 हजार करोड़ रुपये का निवेँा पाईपलाईन में हैं। जिनके भीघ्र ही स्थापित होने की सम्भावना है। इसका श्रेय भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है जिन्होंने चारों तरफ एक भांत वातावरण उद्योगों के लिए उपलब्ध कराया जिससे कि किसी भी इण्डस्ट्रीलिस्ट को जो हरियाणा में उद्योग लगाना चाहे उसको किसी प्रकार की असुविधा न हो। इन सब बातों के कारण ही हर कोई हमारे प्रदेँा में उद्योग लगाने के लिए अग्रसर है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। जहां तक एस०ई०जैड० का सम्बन्ध है तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेँा में जो एस०ई०जैड० की

स्थापना का प्रावधान किया गया है यह एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे कुछेक साथी हैं जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे प्रदेश में जो तरक्की और विकास के लिए अब तक किया गया है और भविष्य में जो किया जायेगा उसमें मन मार कर लोगों में जाकर के इस प्रकार की बात कहते हैं। कि एस०ई०जैड० जिसानों को उजाड़ने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि एस०ई०जैड० नहीं होंगे तो हमारा प्रदेश चहुंमुखी विकास नहीं कर सकेगा और न ही हमारे बच्चों को रोजगार मिल सकेगा। मैं इस सदन में इस बात की घोशणा करता हूँ कि मैं अपने महम हल्के की 10 हजार एकड़ जमीन एस०ई०जैड० और उद्योगों की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ऑफर करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वे हमारे महम हल्के में एस०ई०जैड० की स्थापना करें और उद्योगों की स्थापना करें। हमें इस बात की बड़ी खुशी होगी। एस०ई०जैड० और उद्योगों की स्थापना से हमारे बच्चों को रोजगार मिल सकेगा और बेराजगारी की समस्या से भी हमें निजात मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पिछले तीन सालों में तीन गुणा जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं तथा विभागों को दिया है उसका आबंटन दर्शाता है कि यह बजट जनहितकारी, जनकल्याणकारी और चहुंमुखी विकास के साथ-साथ सुख भांति के लिए हरियाणा प्रदेश को देश के परिदृश्य पर नम्बर एक की पोजीशन पर ले जाने वाला बजट है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं

आपके माध्यम से पूरे सदन से इस बजट को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करूंगा। इसके साथ ही मैं इस विकासपूरक बजट के लिए वित्त मंत्री महोदय, अधिकारीगण और जिन्होंने इस बजट को बनाने में सहयोग दिया और सबसे बढ़कर आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो इस प्रदेश को हर प्रकार से तरक्की और विकास के मामले में आगे बढ़ाने के लिए फैसले लिए हैं और काम किए हैं उनकी एक लम्बी सूची है उन सबके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ और इसी के साथ यह आशा करता हूँ कि जिस नीति और नीयत के साथ आज सरकार कार्य कर रही है अगर सरकार ऐसे ही कार्य करती रही तो आने वाले वक्त में हरियाणा प्रदेश इस देश का सिरमौर होगा। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।

डॉ० सीता राम (डबवाली, अनुसूचित जाति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री महोदय ने जो 2008-09 का वार्षिक बजट पेश किया है इस पर आपने मुझे चर्चा करने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय वित्तमंत्री जी बड़े सुलझे हुए डेमोक्रेटिक आदती हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जनता को अच्छा बजट देने का प्रयास किया है। लेकिन बजट पेश होने से पहले आम जनता को इस बजट से बहुत आशाएं

थी और बजट से लोगों को उम्मीद होती भी है। आम आदमी को उम्मीद होती है कि उसको इस महंगाई के दौर में खाने पीने की चीजें सस्ती उपलब्ध होंगी। उद्योगपतियों को भी आशा होती है कि किसी तरीके से वैट में या करों में राहत दी जायेगी लेकिन इस बजट को पढ़ने के बाद और इसका आंकलन करने के बाद यह लगता है कि यह बजट लोगों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। इस बजट में बजट एट ए ग्लॉस के अन्दर दिखाया गया है कि रिवैन्यू रिसीट्स के अन्दर बड़ा भारी इन्क्रीज हुआ है, जो 2005-06 में 29.6 परसेंट के करीब इन्क्रीज है अगर उसको हम 2008-09 में देखें तो यह घटकर तकरीबन 10 परसेंट के करीब हो गया है। इसी तरह से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हैं यह भी बढ़ा है। पावर सैक्टर में 2007-08 में जो प्लान एक्सपेंडीचर था वह 872.52 करोड़ रुपये था लेकिन इस साल 2008-09 में घटकर यह 866.88 करोड़ रुपये हो गया है। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो प्लान बजट था वह 90 करोड़ से ज्यादा था जो कि घट कर 68.17 करोड़ हो गया है। मैं सिर्फ उन बिन्दुओं पर प्रकाश डाल रहा हूँ जहाँ पर सरकार अपनी कमियों को दूर कर सकें और जिन डिपार्टमेंट का बजट घट गया है उनको बढ़ाया जा सके। अर्बन डिवैल्पमेंट डिपार्टमेंट का भी 2007-08 में प्लान बजट 314.16 करोड़ था उसको घटाकर 291 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह से कंसोलिडेटेड फंड्स पावर सैक्टर में जो बजट 2007-08 में 14.34 परसेंट था वह डिक्लीज हो कर 13.36 परसेंट हो गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी बजट जो 2007-08 में 3.

59 परसेंट था वह घट कर 3.22 परसेंट हो गया है सिंचाई विभाग का बजट भी पिछले साल 2007-08 के 6.25 परसेंट के मुकाबले घट कर 5.59 परसेंट हो गया है। इसी तरह से जो वॉटर सप्लाई और सैनितेान का 2007-08 का बजट था वह 5.10 परसेंट से घटकर 4.79 परसेंट हो गया है। इसी तरह से हैल्थ डिपार्टमेंट का बजट भी 2007-08 में 2.65 परसेंट था जो कि घट कर 2.59 परसेंट हो गया है इसी प्रकार से पुलिस विभाग का बजट 3.67 परसेंट से घट कर 3.39 परसेंट हो गया है। अध्यक्ष महोदय, जिस नरीके से इसके अन्दर जो इन्क्रीज 2005-06 में रेवेन्यू रिसीट्स में दर्शाई गई है वह 29.6 परसेंट है जबकि इस वर्ष 2008-09 में जो प्रपोज किया गया है वह 10% के करीब है। इससे ऐसा लगता है कि जो इन्क्रीज हुई है क्योंकि जो क्लैक्टर रेट बढ़ा है उसकी वजह से स्टॉम्प ड्यूटी भी बढ़ी है। महंगाई बढ़ने की वजह तथा वैट बढ़ने की वजह से यह इन्क्रीज हुई है लेकिन अब डाउन ट्रेंड चल रहा है और अगले साल जब वैट डाउन आएगा या महंगाई में कमी होगी तो अगले साल पता चलेगा कि हरियाणा के अन्दर आर्थिक स्थिति कैसी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो अन्य विषय हैं मैं उनको टच नहीं करूंगा जिन पर हमारे साथी बोल चुके हैं लेकिन मैं पावर सैक्टर पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। यहां पर यह बात बार-बार कही गई कि पिछली सरकार ने एक भी युनिट बिजली पैदा नहीं की लेकिन हमारी सरकार के समय में प्रदेश में बिजली की स्थिति बहुत अच्छी थी। स्पीकर सर, जैसे कि आज बिजली का कमी के कारण कट्स और जाम

लगते हैं वैसे कट्स और जाम हमारी सरकार के वक्त में नहीं लगते थे। हमारी सरकार ने पानीपत की दूसरी यूनिट चालू की और इसके साथ ही साथ हमें फरीदाबाद से भी बिजली मिली। स्पीकर सर, यह रिकार्ड की बात है और यह हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में दर्ज भी है। यह सरकार का छपा हुआ सर्वेक्षण है इसके अन्दर लिखा हुआ है कि 1565 मेगावाट बिजली हमारी सरकार के अन्दर प्रोड्यूस हुई थी। (विधन) स्पीकर सर, टोटल 4000 से कुछ अधिक बिजली उत्पादित की गई। आप यह फिगर देख सकते हैं अगर यह गलत है तो आप कह सकते हैं यह आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट छपी है जिसमें से मैंने यह फिगर कोट किया है यह इसके अन्दर मैं इन किया हुआ है। आप इसको उसमें से निकाल दीजिए। (विधन) मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है यह आपकी बुक में छपी हुई है। यह जा'साथी कहते हैं कि राज में खु'हाली है। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने जनता के मन में यह भय डाल दिया कि वैट लागू करके हमारी सरकार ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। हमने उस वैट को लागू नहीं करना था। अध्यक्ष महोदय, यहां पर विधान सभा में तो ये लोग कहते थे कि वैट से प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। इन लोगों ने व्यापारी, मजदूर और किसान तथा आम आदमी के मन में यह बात डाल दी थी कि पिछली सरकार ने वैट लागू करके प्रदेश को बर्बाद कर दिया। वैट को लेकर इन लोगों ने मजदूरी और किसानों को भड़काया लोगों को गुमराह करने का काम किया (विधन)इसके कारण हमारी पार्टी को राजनीतिक नुकसान हुआ। स्पीकर सर, दूसरी बात यह है

कि हमारे ये साथी इन्होंने यह घोशणा की थी कि गैस अथोरिटी ऑफ इण्डिया ने कहा हुआ है कि भारत वर्ष के अन्दर वर्ष 2009 तक गैस अवेलेबल नहीं हो सकती है। यहां पर विधान सभा में ये कहते हैं कि गैस की उपलब्धता हमारे हाथ में नहीं है। इस गैस बेस्ड प्लांट को बनाने की घोशणा इन्हें नहीं करनी चाहिए थी और इसकी नींव नहीं रखनी चाहिए थी। ऐसी बात इन्हें नहीं कहनी चाहिए थी जो पूरी नहीं हो सकती थी। यह जो न्यूक्लीयर पावर प्लांट की चर्चा की गई है, मैंने इस के बारे में अपना सवाल भी किया था। तीन साल हुए न्यूक्लीयर पावर प्लांट पर कोई कार्य नहीं हुआ है। किसी को यह नहीं पता कि यह पावर प्लांट कहां लगेगा, कब लगेगा, इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। इस पर कितनापैसा लगेगा और बिजली की बेहद कमी है और हर साल बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। हम मानते हैं कि अभी तक सरकार ने कोई ऐसे प्रयास नहीं किये हैं जिससे इस बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, लोग पहले ही भयभीत हैं, गर्मी का सीजन आने वाला है गर्मी में बिजली की सप्लाई के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है ? इसके बारे में आश्वासन दें कि आने वाले समय में लोगों को बिजली मिलेगी। बिजली की डिमाण्ड अगर पूरी नहीं की गई तो लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। पिछले साल भी लोगों को बिजली की कमी झेलनी पड़ी थी। स्पीकर सर, इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि सोलर ऐनर्जी को हम डिवैल्प कर सकते हैं। सौर ऊर्जा डिवैल्प कर सकते हैं उसके अन्दर आप इनवैस्ट कीजिए क्योंकि छोटे-छोटे

प्लांट लगाकर हम मांग पूरी नहीं कर सकते और सोलर ऐनर्जी सस्ती भी पड़ेगी। इसके अन्दर जो पूरा खर्चा है वह सरकार स्वयं वहन करे जिस प्रकार से जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के अन्दर सौर सिस्टम में डिवैल्पमेंट हुई है। हमारे यहां पर धूप की दिक्कत नहीं है इसलिए उस सिस्टम को डिवैल्प करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस सिस्टम से बिजली की कमी को दूर किया जा सकें। कृषि के बारे में सदन में चर्चा की गई है, इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कृषि के अन्दर विकास दर की राष्ट्रीय औसत है वह 2.6 दर्शाई गई है लेकिन हमारी हरियाणा की सरकार ने इसकी विकास दर के बारे में बताया है कि आने वाले समय में यह 4.5 प्रतिशत होगी, यह ठीक है कि हरियाणा का किसान मेहनती है। हमारी हरियाणा की सरकार उनको बिजली और पानी नहीं दे पाई है, फिर भी उस किसान ने फसल की प्रोडक्शन में बढ़ौतरी करी हैं यह बढ़ौतरी किसान ने कैसे करी है यह मैं सदन में बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, किसान ने अपने खेतों में डीजल फूंक फूंक कर इस प्रोडक्शन में बढ़ौतरी की है। आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर बड़ा सा ऐरिया ऐसा है जहां पर जमीनी पानी अच्छा नहीं है, उस पानी में भारा बहुत ज्यादा है। आज किसान उस पानी का प्रयोग अपनी फसलों को पकाने के लिए कर रहे हैं। इस पानी की वजह से आने वाले समय में उस जमीन की ऊपजाऊ भाक्ति कम हो जाएगी। इस बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सी०ए०जी० की रिपोर्ट के अन्दर यह दर्शाया गया है कि वहां पर शिक्षकों की कमी है।

उसके बाद रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बीज बनाने के लक्ष्य को भी नहीं पा सकी है जिससे पर-एकड़ की प्रोडक्शन बढ़ सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस यूनिवर्सिटी के फण्ड को ज्यादा करने के बारे में व्यवस्था करनी चाहिए। रिपोर्ट के अन्दर जो पर-एकड़ प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में जो बात कही गई है सरकार को इस बारे में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उसमें किसान की लागत कम आए और किसानों की प्रोडक्शन बढ़े। सरकार को किसानों के लिए अच्छे पानी का प्रबन्ध करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च ऐक्टिविटीज है वे भी बहुत कम हुई है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह सरकार किसान हितौशी होने की बात करती है। लेकिन जब प्रदेश में भयानक ठण्ड पड़ी और पाले की वजह से किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ तब इस बारे में सरकार ने यह कहा कि यह नुकसान नैचुरल कलैमिटी के अन्दर नहीं आता है। इसलिए हम उनको मुआवजा नहीं दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार कहती है। कि हरियाणा प्रदेश का बजट सरप्लस है फिर इस सरकार को उन किसानों को पैसा देने में क्या दिक्कत है। अगर यह सरकार किसानों की हितैशी है तो इनको उस सरप्लस पैसे को उन किसानों को देना चाहिए जिनका पाले की वजह से नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सदन में डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात की जाती है लेकिन हकीकत में डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं हो पा रही है। इसमें दिक्कत यह है कि किसानों को गेहूँ और जीरी के अच्छे

दाम मिलते हैं और सरकार उनको आयल पैदा करने वाली फसलों की पैदावार करने के लिए कहती है। अध्यक्ष महोदय, इसमें किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। उनको आर्थिक रूप से नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, आज तो डायवर्सिफिके इन ऑफ क्राप्स भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि देश में अन्न की बड़ी भारी कमी है। आज हमें महंगे दामों पर अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता है (विधन) यह सिर्फ कागजों के अन्दर ही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि किसानों को अपनी फसल बेचने का पूरा अधिकार होना चाहिए। वह जहां पर भी अपनी फसल बेचना चाहे, वहां पर बेच सके। चाहे वह उन किसानों को होना चाहिए। किसान अगर किसी प्राइवेट को भी बेचना चाहे तो उसको यह अधिकार मिलना चाहिए। इसी तरह से किसान को अपने गन्ने को कहीं पर भी ले जाकर बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा हुई कि हरियाणा के अंदर काफी नये उद्योग लगे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा से बहुत से उद्योग धंधे पलायन भी कर गए हैं। कौन से उद्योग पलायन कर गए हैं उनकी भी मेरे पास कटिंग्स हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो जो दवाई बनाने की यूनिट्स हैं वह करनाल, अम्बाला क्षेत्र से निकल कर हिमाचल प्रदेश के अंदर चली गयी है क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा इंसेंटिव्स सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। उनको इन्कम टैक्स के अंदर छूट है। इसके अलावा और भी बहुत सी छूट उनको वहां पर दी जा रही है। इसी तरह से

अम्बाला का जो मिक्सी उद्योग है, जो ग्राइंडर उद्योग है उसकी भी कई यूनिट्स अम्बाला से शिफ्ट होकर चल गयी है। मेन बात शिफ्ट होने की यह है कि एक तो हिमाचल के अंदर ज्यादा टैक्स में छूट है और दूसरे बिजली की कमी की वजह से, भी वे हरियाणा से शिफ्ट हो रही है। बिजली न मिलने की वजह से वे अपना माल पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकते हैं जिसके कारण उनको घाटा उठाना पड़ता है। हरियाणा से उद्योग धंधे पलायन न करें इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि जब से यह सरकार आयी है हम हरियाणा प्रदेश को नम्बर एक पर लाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारे समय में भी इन्कम के मामले में गोंवा के बाद हरियाणा दूसरे नम्बर पर था और आज भी हरियाणा की पोजीशन वही है। तीन साल बीत गए पहले नम्बर पर हरियाणा कब आएगा। हर बजट में इसकी चर्चा होती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि अगर इतनी धीमी गति से हम चलते रहे तो एक नम्बर पर हरियाणा को लाने का प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी कई अनियमितताएं हुई हैं। कैथल डिपो के अंदर, सिरसा डिपों के अंदर या और कई डिपो भी ऐसी होंगी जिनके अंदर 49 बसिज ऐसी थीं जिनके टायर्स न होने की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। इसी तरीके से जो बसिज यू०पी० में आपरेट करती हैं उनको भी ज्यादा टैक्स देने से नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, आज हर एक व्यक्ति ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है। आज आम आदमी रोड पर चल नहीं

सकता क्योंकि रोडज पर बहुत कंजै न हो गयी है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है। आम आदमी को बड़ी भारी दिक्कत है उसको चलने की जगह नहीं मिलती है। कहीं रोड पर फुटपाथ नहीं है। और कहीं ने नाल हाईवे पर ही ऊंट गांडी वाले या बैल गाड़ी वाले चलते हैं। भाम के समय नजर नहीं आता सामने से लाईट पड़ती है जिसके कारण रोडज पर बहुत ज्यादा ऐक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए सरकार को इस बारे में प्रयास करने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक तो यह करना चाहिए कि जो ड्राइविंग लाईसैंस बनते हैं उनके बारे में सिट्रक्ट नोर्म्ज फॉलों करने चाहिए दूसरे यह करना चाहिए कि अगर सड़क पर चलने वालों के लिए जगह नहीं तो पैदल चलने वालों के लिए या तो फुटपाथ बनाए जाने चाहिए या ने नाल हाई-वे की साईड में ही छोटे रास्ते बनाए जाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप बैटि

डॉ० सीता राम : सर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। जो न्यूनतम मजदूरी 3510 रूपये हैं उसके बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि यहां पर बहुत से साथियों ने जिक्र किया कि यह मजदूरी किसी को मिल नहीं पाती है। अगर कोई प्राईवेट मजदूरी करता है तो उसको 1500 रूपये दिए जाते हैं। इस तरह से न्यूनतम मजदूरी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। दूसरे सर, यह कहूंगा कि हरियाणा के अंदर जो अभी जूडी गियरी के अंदर आफिसर्ज की नियुक्ति हुई है उसके अंदर

अनुसूचित जाति के जो आफिसर्ज थे वे बहुत ही कम सख्या में आए हैं। उनके लिए जो रिजर्वे इन के तहत पास मार्क्स 45 परसैंट होने चाहिए। यह नियम थू आउट इंडिया में है लेकिन उनको जनरल कैडिडेट की तरह ही 50 परसैंट मार्क्स पास होने के लिए दिये गये थे।

श्री आनन्द सिंह डांगी : सीताराम जी, माइंड का रिजर्वे इन तो नहीं होना चाहिए।

डॉ० सीता राम : आप रिजर्वे इन की सुविधा दे ही रहे हैं तो नॉर्म्स के अनुसार फौलोअप होना चाहिए। जिनके 45 परसैंट मार्क्स होने चाहिए, उनके लिए दोबारा से इंटरव्यू लेकर के जो उनमें योग्य लोग हैं उनको नौकरियों में मौका दिया जाना चाहिए। इसके अलावा 85 वां संविधान संशोधन जो हुआ वे मूल रूप में भारू से लागू करना चाहिए था। जो कर्मचारी है उनको प्रमोशन इत्यादि का जो लाभ बनता था वह लाभ उनको मिलना चाहिए था। इन भाब्दों के साथ बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ।

Major Nirpender Singh Sangwan (Dadri) : Sir, thank you very much for granting time to speak on the Budget Estimates. I take this opportunity to thank and congratulate the Hon'ble Chief Minister for creating conducive condition to sustain economic growth in Haryana.

Today, the rule of law prevails in the State which has instilled the sense of confidence in the people of Haryana. A sound foundation for a sound fiscal management in all-around development of the State has been laid. The Gross State Domestic production (GSDP) has increased by 10.1% over the last year. The agricultural sector is expected to grow at 10% the services sector at 12%. The per capita income is expected to the State has achieved a revenue surplus. State's own tax revenues at Rs. 10928 crores have shown a growth of 20.37% over the last year. All these are the highlights of the Budget in the beginning. In the annual plan, the Planning Commission has approved a plan size of Rs. 6650/- crores for 2008-09, and this marks an increase of three-fold over the 2000 mark which the previous Government had achieved. The welfare schemes to benefit of our Scheduled Castes brethren and other below the poverty line, have looked into. 21.55% of the plan funds are to be spent on the welfare schemes for this poverty or below the poverty line brethren. Hundred square yards residential plots to eligible BPL SC families are in the annals. The new initiatives- There were cases of extreme rural indebtedness leading distress to harassed farmers going to the extent of committing suicide. I take this opportunity to convey our sincere gratitude to the UPA Chairperson, Smt. Sonia Gandhi for ensuring the small and marginal farmers' indebtedness is taken care of. For this a waiver of Rs. 60,000/- crores has been included in the present Budget at the Centre. Speaker Sir, Waiver Scheme of Bank Loans for small and marginal farmers is an unprecedented bold step. Speaker Sir, incentive to farmers who have paid their loan in time should also be looked into because this shall give incentive to farmers to pay bank loan in time. Intention to

lower the stamp duty by another one per cent also shows the good intention of the Government. This is a great step towards the farmers being self-reliant to save some money. The Metro Rail Link from Delhi to Gurgaon is in full swing and it should be completed by the year 2010. Speaker Sir, I am sure that the Metro Rail Link to Faridabad and Bahadurgarh will also come through. An establishment of the Health University at P.G.I., Rohtak and opening to medical College with postgraduate facilities at Faridabad is also a great step towards self-reliance in the health sector. Speaker Sir, Government has given incentive to employees by raising House Building Advance from Rs. 7.50 lakh to Rs. 12.50 lakh and for Repair and Extension of House from the existing amount of Rs. One lakh and Rs. 1.80 lakh to Rs. Two lakh and Rs. 2.50 lakh respectively. Speaker Sir, education is one of the most important areas today not only for our State but also for the whole country. A revolutionary initiative has been launched as 'Mukhyamantri Scheduled Castes Shiksha Protsahan Scheme'. This scheme takes care of Scheduled castes' Children who dropout after primary or high school and this scheme will go a long way. Speaker Sir, to make it sure, the Scheduled Castes boys and girls studying in Government schools will be given a monthly stipend ranging from Rs. 100 to Rs. 300 per month for boys and Rs. 150 to Rs. 400 per month for girls. Speaker Sir, our Government is opening another Sainik School in Rewari District, this is one step which is going to a long way for taking care of the children of Servicemen and Ex-servicemen. Speaker Sir, one more Sainik School is required in Bhiwani and Hisar to take care of the Children of serving and Ex-servicemen because the serving soldiers and Ex-servicemen, give the best part of their life to the nation for

looking after their frontiers and in this process they are not able to look after their children at the correct time. Speaker Sir, such schools will give them an opportunity to study and compete at the same level with other children, Speaker Sir, in power sector, one 1200 MW coal-based Rajiv Gandhi Thermal plant at Khedar, Hisar and another coal-based Thermal Power Plant 1500MW capacity at Jhadli, Jhajjar, highlights towards self reliance in power sector which the State is going step. Speaker Sir, repair of transmission lines and changing of old lines which are hanging low in most of the villages is a propriety because this leads to accidents and power failure at many times. Speaker Sir, iron lines in old towns, are very old and it also need to change. This sector needs to look into. In the irrigation sector, equitable distribution of water throughout the State is being achieved. We are eagerly waiting for completion of the BML-Hansi-Butana Branch in Dadri and looking forward to get more water. The Hon'ble Chief Minister and the Minister has agreed to increase the water from 2.4 to 3.05 MAF I would suggest that escape reservoirs should be made at all the pump-houses so that these can recharge the water table in the area.

Under the Indira Gandhi Drinking Water Scheme, household connection are being given free of cost to the Scheduled Castes houses, but it needs strict vision for its implementation, Sanitation in town needs to be looked in to so that new sewerage lines which are being laid, should cater up to at least 2025.

Unprecedented growth of industries in the industrial hubs of the State are the hallmark of our

Government. I request that an industrial hub be created for under-privileged areas like Dadri. Talking about Dadri, I would say infrastructure available at Dadri is unprecedented. Land is available at reasonable prices there. Train and man power is available with the IT which is coming up in Dadri itself. It has a rail head. Moreover, it is only few kilometres away from Jhadli where power plant is coming up. Dadri has the best road network with the rest of India. Speaker Sir, therefore, I would request through you that an industrial hub may be created at this place shortly.

The Government has given best priority to the road network in the State. I am proud to say that the Rajiv Gandhi Bridges and Roads Infrastructure Development Programme involving Rs. 3000 crore was started from Dadri by Hon'ble Smt. Sonia Gandhi herself. I thank the Hon'ble Chief Minister for having chosen Dadri for the avenue. The rural roads under construction need to be checked for quality. This is on benchmark that we have to look into.

The agriculture department needs to do more. Agriculture Department needs to tie up at the lower level and at the ground level with the farmers. The department needs to do more demonstrations in the villages. The representatives of Agriculture Department can go and demonstrate the new seeds, pesticides & insecticides in the villages. They can demonstrate how the new crops are grown and it should be shown to the farmers. This department has to show how it is sown. Speaker Sir, the Animal Husbandry Department needs new veterinary clinics, more staff, more hospital for this, Speaker Sir, in the Education Sector also more funds are

required. I would suggest a new sports University for Haryana because Haryana has the potential to produce all kinds of sportsman in the field of sports. So, therefore, We need to pump it more money and enthusiasm in this field.

Sir, I am sorry to say that the Health Department needs a lot of overhauling. There is a paucity of staff and the staff which is available, is not willing to work in the rural areas. Sir. मुझे आपको एक बात बतानी पड़ेगी। आज की तारीख में जितने डाक्टर दादरी में पोस्टिड हुए हैं वे सारे के सारे अपनी बदली करवाकर जाते रहे, 10 डाक्टर में से केवल 3 ही पोस्टिड है। आज किसी भी PHC में डाक्टर नहीं है। वहां पर कोई डॉक्टर काम करने के लिए राजी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय डॉक्टर की नियुक्ति की जाये उस समय उनको बताया जाये कि उनको रूरल टाऊन्ज में पोस्टिंग दी जायेगी, जैसे दादरी है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वाईउ-अप करता हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी(नौलथा) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा में वर्ष 2008-09 का जो कर रहित बजट माननीय वित्तमंत्री जी ने पेश किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह बजट सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का एक दर्पण है। इसमें सभी योजनागत खर्चा का विस्तार से वर्णन किया हुआ है और समाज के सभी वर्गों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, सही मायने में यह बजट विकास

पूरक बजट है। वित्तमंत्री जी का यह चौथा प्रयास है और इन्होंने पिछले वर्षों की तरह से इस बार भी सभी विभागों के बजट में बढ़ौतरी की है। इस बजट की मुख्य विशेषता यह है कि सामाजिक आधार पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 84 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी रिकार्ड की बात है कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से 21.35 प्रतिशत बजट का हिस्सा रखा गया है जबकि प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.33 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, आज से तीन साल पहले जिस समय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली थी उस समय प्रदेश में अराजकता, आतंक और भय का वातावरण था जिसको ठीक करने की चुनौती हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार की थी। आज हम इस बात की खुशी हैं कि जिन बदमाश लोगों को पहले सरकार का समर्थन मिलता था आज वे या तो प्रदेश छोड़कर चल गए हैं या प्रदेश की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष : बहल जी, आप रैपीटें जान न करें। यदि आपको कोई नई बात कहनी है तो आप कहें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या के लिए आपको अपनी तरफ से अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्या इस सदन की सबसे पुरानी सदस्या

हैं इसलिए इनको अपनी बात कहने का पूरा-पूरा मौका दिया जाये।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अब मैं इस सदन का ध्यान कृषि क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहती हूँ। आज से तीन साल पहले जब माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने सत्ता सम्भाली थी तो उस समय प्रदेश का सारे का सारा हिसाब किताब बिगड़ा हुआ था। तरह-तरह के कर्जा का भार किसानों के ऊपर था। चौधरी देवी लाल जी ने लौंगों को यह कहा था कि बिजली के बिल कोई न भरे जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो एक कलम से सारे कर्जे माफ कर दूंगा। सत्ता हथियाने के लिए तत्कालीन राजनेताओं के द्वारा किए गए इस प्रकार के वायदों से किसानों का बिजली का बिल साल दर साल बढ़ता गया लेकिन किसी भी भूतपूर्व सरकार द्वारा किसानों का यह बिजली का बिल माफ नहीं किया गया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों के इस दर्द को समझकर 1600 करोड़ रुपये के किसानों के बिजली के बिल माफ करने का अभूतपूर्व कार्य किया और इसके साथ ही मैं माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और भारत सरकार को भी बधाई देती हूँ। जिसने इस देश के किसानों का 60 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ करके एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। हमारे देश का किसान कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दबा हुआ था और अनेक जगहों से उसके द्वारा आत्महत्यायें करने के समाचार

प्राप्त हो रहे थे। किसान को भी पूरी मेहनत करने के बावजूद अपना पूरा हक नहीं मिलता था। यह भी एक बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है इसके साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी ने जो एक बात का वर्णन किया है जो साहूकारों का कर्जा है उसके बारे में भी कोई न कोई निर्णय जल्दी ही लिया जायेगा। कोई न कोई रास्ता जरूर निकाला जायेगा। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा को-आपरेटिव बैंकस के कर्जों के ऊपर जो 830 करोड़ रुपये के ब्याज को भी माफ किया गया है, वह भी एक सराहनीय कार्य है। लेकिन मैं एक बात सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों को भी फायदा हो और छोटे किसानों को भी लाभ हो लेकिन इनके अलावा जो भूमिहीन लोग हैं जिन्होंने छोटे-छोटे लोन ले रखे हैं किसी ने बुगी के लिए, किसी ने छोटी मीन के लिए तो किसी ने चक्की के लिए लोन ले रखा है उनकी भी अगर इसी प्रकार से मदद की जाये तो साने पर सुहागा हो जायेगा। मैं यह समझती हूँ कि सरकार को इस बारे में भी कुछ कारगर कदम उठाने चाहिए जिससे इस प्रकार के भूमिहीन लोगों को भी कुछ राहत मिल सके।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम ससे माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो यह भूमिहीनों के कर्जों के बारे में चर्चा की है इस बारे में हरियाणा सरकार की यह नीति थी कि जिन्होंने कॉआपरेटिव सैक्टर में नर्रन

एग्रीकल्चर लोन ल रखा था उनका हम पहले ही सारे का सारा ब्याज माफ कर चुके हैं। इस स्कीम से 1 लाख 6 हजार 17 लोगों ने लाभ उठाया है।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहती हूँ कि जैसे किसानों को पूरा कर्जा एक बार में ही माफ कर दिया गया है इसी प्रकार से अगर इनके लिए भी कुछ किया जायेगा तो इससे इनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और यह भी एक बहुत अच्छा और सराहनीय कदम होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यह भी सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो भूमिहीन लोग हैं जो अपने काम धंधों के लिए छोटे-छोटे लोन लेते हैं उनको 10 हजार रुपये से ज्यादा लोन नहीं मिलता। अगर इस लोन सीमा को भी बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया जाये तो इससे उनको ज्यादा सहूलियत होगी क्योंकि 10 हजार में तो अब कुछ नहीं आता। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे उनको अपना काम करने में भी बहुत अच्छी सहूलियत मिलेगी। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में सारे काम बड़ी सूझ-बूझ के साथ कर रहे हैं और किसी भी वर्ग को कोई दिक्कत नहीं होती। बैंकों द्वारा उदारवादी दृष्टिकोण के तहत लोन देने और अन्य कल्याणकारी नीतियों के कारण किसी को भी पैसे की कमी कहीं भी नजर नहीं आती और कोई भी काम अधूरा नहीं रहता है। शिक्षा की दृष्टि से हमने बहुत तरक्की की है। भारी तादाद में स्कूलों को अपग्रेड

किया है और कई ऐसे फैसले भी लिये हैं जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। कुण्डली में राजीव गाँधी ऐजूके एन सिटी का जो निर्माण किया जा रहा है जिसमें वि व प्रसिद्ध संस्थाएं आयेंगी उसमें 25 परसेंट सीटें हमारे अपने प्रदेश के बच्चों के लिए होगी जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी प्रकार से मुरथल में मुरथल इंजीनियरिंग कॉलेज को दीन बंधु सर छोटू राम साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी युनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, यह एक सराहनीय कदम है। पूरे उत्तर भारत में पहला महिला वि विद्यालय खानपुर में बना और उसमें कुलपति से लेकर सभी कर्मचारी भी महिलाएं ही होगी। इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि खानपुर में ऐसी दयनीय हालत होती थी कि केवल तीन कमरे थे और उनके आगे घास-फूस का छप्पर होता था। बरसात के दिनों में वह भी सारा टपकता रहता था। किसी ने उसके हाई स्कूल तक अपग्रेड होने की बात भी नहीं सोची थी लेकिन आज वह एक युनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है। यह पूरे उत्तर भारत में एक मिसाल है और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को बधाई देती हूँ कि यह महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बहुत सारे स्कूल अपग्रेड हुए हैं लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए स्कूल भी ज्यादा तादाद में अपग्रेड जाएं आज के हालात के मुताबिक हर जिले में कम से कम एक कॉलेज लड़कियों के लिए, जहां भी बनाया जा सकता हो, जरूर बनाना

चाहिए उससे आजकल का जो माहौल है उसको थोड़ा सा सुधारने में राहत मिलेगी। इसी प्रकार से सिंचाई के लिए बहुत अच्छे कदम उठाये हैं। पहले जितना पानी आता था चौटाला जी उस पूरे पानी को सिरसा में ही पूरा कर लिया करते थे और 42 दिन तक नहर में पानी नहीं आता था लेकिन जब से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आइ है उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले पानी के समान बंटवारे के लिए एक सिस्टम बनाया। मैं जहां तक समझती हूं कि अब किसी को भी 2 सप्ताह से ज्यादा पानी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। हरेक को उसके हिस्से के मुताबिक पानी मिलता है। बी०एम०एल० हांसी बुटाना ब्रांच के बनने के बाद इस में और भी ज्यादा सहूलियत हो जायेगी। उसका 90 परसेंट काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी बाकी का काम भी पूरा हो जायेगा। इसी प्रकार से दादूपुर-नलवी नहर का निर्माण जो पिछले 20 साल से ठण्डे बस्ते में पड़ा हुआ था वह भुरू हो चुका है। इस नहर के निर्माण के बाद भाहबाद और अम्बाला का जो एरिया है उसको भी पानी मिल सकेगा। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को बधाई देती हूं। इसी प्रकार से सड़कों का काम बहुत तेजी से हो रहा है और सब जगह हो रहा है। जो सड़कें 12 फुट चौड़ी थी उनको 18 फुट चौड़ा किया गया है। मुझे 6 बार इस सदन में आने का मौका मिला है। जहां सयुक्त पंजाब में एक एम०एल०ए० 5 साल तक अगर 5 किलोमीटर की सड़क बनवा लेता था तो अपने आप को खुा किस्मत समझता था लेकिन आज मुझे खुा ही हैं कि सड़कों की कमी नहीं है। कहीं पर

प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें बन रही हैं और कहीं पर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सड़कें बनाई जा रही हैं। किसी को कमी महसूस नहीं होती कि उनके यहां सड़कों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा जिन सड़कों की मरम्मत की जाती है। उसमें थोड़ी देरी हो जाती है उन पर भी अगर थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाये तो और भी अच्छा होगा। जी०टी० रोड पर मेरे हल्के का एक गांव है सिवाह, उसमें मार्केटिंग बोर्ड की एक सड़क बनी हुई है। यह जो सड़क है वह बाईपास के साथ मिलती है। यह सड़क तो बनी हुई है। लेकिन इस सड़क की हालत खराब हो गई है और इसकी रिपेयर नहीं हुई है। मैं इसके बारे में एक साल से लिख रही हूँ तथा दो साल से मैं इसके बारे में सवाल उठा रही हूँ। अगर इसकी रिपेयर हो जाए तो इससे यहां के लोगों को काफी फायदा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था। महिलाओं के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है और इसके साथ ही साथ अध्यापकों के पदों में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किये हैं जो कि इस सरकार का सराहनीय कार्य है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए इस सरकार ने 100-100 गज के प्लॉट्स दिए हैं। पहले ये प्लॉट्स श्रीमती इन्दिरा गांधी के भासनकाल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गरीबों को दिए गये थे लेकिन इस बात को काफी समय हो गया है और उन परिवारों की दो-दो या

तीन-तीन पीढ़ियां हो गई है। उन लोगों के पास अब बैठने तक को जगह नहीं है। 100 गज जमीन उनको बहुत लेकिन गरीब परिवारों के लिए यह बहुत बड़ी चीज है जिससे उनको बहुत सहारा मिल रहा है। ये प्लॉट्स मिलने पर वे परिवार ठीक प्रकार से गुजारा कर लेंगे। सरकार का यह कदम बहुत ही मैं स्वास्थ्य के मामले में कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है। कि पी०जी०आई०, रोहतक को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा, यह बहुत ही अच्छी बात है। सी०एच०सी०, पी०एच०सीज० और सब-सैंटरज बनाए गए हैं। लेकिन मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो 10-10 या 20-20 हजार की आबादी के गांव हैं वहां पर सब-सैंटरज होते हैं। बड़े-बड़े गांव जो कुछ ब्लॉक में भी आते हैं इनमें पी०एच०सी० या सी०एच०सीज० बनाने के बारे में सरकार विचार करे कि उनके लिए क्या स्कीम बनाई जा सकती है ? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से खाद्य पदार्थों की सप्लाई की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगी। वैसे तो खाद्य पदार्थों और दूसरी चीजों की प्रदे 1 में कोई कमी नहीं है लेकिन वे महंगे रेट्स पर मिलती हैं। इनमें कोई दो राय नहीं है कि अनाज महंगा होने से किसानों को लाभ हुआ है और उसको उसकी मेहनत की कीमत मिलनी भुरु हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी है कि वह गरीब आदमी जिसने अनाज खरीद कर खाना होता है उसको इस महंगाई के कारण काफी दिक्कत होती है। 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम अनाज कार्ड के साथ प्रत्येक गरीब परिवार को दिया जाता है। मैं यह समझती हूँ कि यह अनाज उसके परिवार के लिए

थोड़ा है और उसको कम से कम 50 किलोग्राम कर दिया जाए तो उसको इससे ज्यादा सहूलियत मिल सकेगी और खाने पीने की उसकी दिक्कत कम होगी। वह महंगा अनाज खरीद कर अपने परिवार को नहीं खिला सकता है। इसी प्रकार से मिट्टी का तेल है उसकी सप्लाई के लिए ठीक इन्तजाम किया जाए। पहले मिट्टी का तेल एक परिवार को पांच लीटर मिलता था लेकिन अब इसको तीन लीटर कर दिया गया है और अब पांच लीटर की बजाए उनको तीन लीटर मिट्टी का तेल मिल रहा है। स्पीकर सर, कार्ड का सिस्टम ऐसा करना चाहिए कि वे किसी दूसरे कार्ड कमे भरोसे न रहें बल्कि जो रातान कार्ड है उसी पर सारी चीज मिल जाए। उसी रातान कार्ड पर अनाज भी मिल जाए और मिट्टी का तेल भी मिल जाएगा तो इससे गरीब आदमी को बहुत सुविधा हो जाएगी। (विधन) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तथा माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करती हूँ। यह बजट प्रदेश में तरक्की लाएगा क्योंकि इस बजट में हर मद के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे की व्यवस्था की गई है जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है।

विधान कार्य—

1. दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली(अलाउंसिज एंड पैरान ऑफ मैम्बर्ज) अमेंडमेंट बिल, 2008

Mr.Speaker : Hon'ble Members now,the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assenbly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister(Sh.Randeep Singh Surjewala) : Sir. I beg to introduce the Haryana Legislative Assenbly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2008.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Legislative Assenbly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr.Speaker : Motion moved-

That the Haryana Legislative Assenbly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr.Speaker : Question is-

That the Haryana Legislative Assenbly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr.Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in clause 2. He may move amendment.

Power Minister(Sh.Randeep Singh Surjewala) :
Sir. I beg to move-

“ That in clause 2 of the Haryana Legislative Assenbly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2008 for the proposed sub- section (1) of Section 7A of the Haryana Legislative Assembly(Allowances and Pension of Members) Act, 1975, the following sub- section shall be substituted, namely:-

(1) Every person shall be paid a pension of five thousand rupees oer mensem if he has served as a member for a period not exceding five years and an additional pension of one thousand rupees per mensem for every additional year of part thereof exceeding a period of five years and if the period of the first membership falls less than the term of five years of the Assembly, it will be treated as full period of five years for he purpose of pension:

provided that family pension shall be admissible, as may be prescribed, to surviving spouse and after his or her death to children (upto the age of eighteen years) of members who had been drawing pension under this Act,”

Mr. Speaker : Motion moved-

“ That in clause 2 of the Haryana Legislative Assenbly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2008 for the proposed sub- section (1) of Section 7A of

the Haryana Legislative Assembly(Allowances and Pension of Members) Act, 1975, the following sub- section shall be substituted, namely:-

(1) Every person shall be paid a pension of five thousand rupees per mensem if he has served as a member for a period not exceeding five years and an additional pension of one thousand rupees per mensem for every additional year of part thereof exceeding a period of five years and if the period of the first membership falls less than the term of five years of the Assembly, it will be treated as full period of five years for the purpose of pension:

provided that family pension shall be admissible, as may be prescribed, to surviving spouse and after his or her death to children (upto the age of eighteen years) of members who had been drawing pension under this Act,”

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो यह बिल का प्रस्ताव हमारी सरकार ले कर आई है इस बारे में हमारे बहुत से माननीय साथी मुख्यमंत्री जी से मिले थे ओर उनसे दो अनुरोध किये थे। इसमें पहला अनुरोध यह था कि 5000 रूपए प्रति माह जो पैं उन हमारे साथियों को मिलती है उसमें या प्रोवीजन था कि अगर पहली टैन्थोर उसकी पांच साल से कम की होती थी और अगर वह दूसरी बार जीत कर आता है तो उसके उस टैन्थोर के समय को उसकी पांच साल की टैन्थोर को पूरा करने के लिए काऊंट कर लिया जाता था। इस बारे में कई साथियों की विनियोग थी कि कई बार विधान सभा अपना

कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है तो इस वजह से कई सदस्यों को पेंशन का नुकसान होता था। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस बिल के माध्यम से एक अमेंडमेंट लेकर आई है कि अगर एक मੈम्बर एक बार इलैक्ट हो जाता है तो पूरे पांच हजार रूपए पेंशन मिलेगी, irrespective of whether he has completed the tenure of 5 years or not. उसके बाद जो उसकी सैंकेंड टैन्थौर है उसमें हर साल 1000/- रूपए उसको पेंशन मिलेगी। पहले 90 दिन का प्रावधान था कि उसको मिनिमम सर्व 90 दिन करना है तो हमारी सरकार ने उसको भी डिलीट कर दिया है। If fraction of even on day in a year is completed, he will be entitled to Rs. 1000/- as pension. So, these are the two beneficial provisions, which we have brought for the members who retire.

Mr. Speaker : Question is-

“ That in clause 2 of the Haryana Legislative Assenbly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2008 for the proposed sub- section (1) of Section 7A of the Haryana Legislative Assembly(Allowances and Pension of Members) Act, 1975, the following sub- section shall be substituted, namely:-

(1) Every person shall be paid a pension of five thousand rupees per mensem if he has served as a member for a period not exceding five years and an additional pension of one thousand rupees per mensem for every additional year of part thereof exceeding a period of five years and if the period of the first membership falls less than the term of five years of

the Assembly, it will be treated as full period of five years for he purpose of pension:

provided that family pension shall be admissible, as may be prescribed, to surviving spouse and after his or her death to children (upto the age of eighteen years) of members who had been drawing pension under this Act,”

The motion was carried.

Mr.Speaker : Question is-

That Clause2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

That Clause1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr.Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of Bill.

The motion was carried.

Title

Mr.Speaker : Question is-

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr.Speaker : Now, the Parllimentary Affairs Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Power Minister(Sh.Randeep Singh Surjewala) :
Sir. I beg to move-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr.Speaker : Question is-

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

2. दि हरियाणा स्पै ल इकोनोमिक जोन(अमैडमेंट) बिल, 2008

Mr.Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister(Sh.Randeep Singh Surjewala) :
Sir. I beg to introduce the Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move-

That Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

डॉ० सु गील इंदौरा(ऐलानाबाद, अनुसूचित जाति) :
अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार स्पै ल इकोनोमिक जोन (अमैंडमेंट) बिल लेकर आयी है। कोई भी बिल जब लाया जाता है तो वह उसकी सरलीकरण के लिए, उसकी मजबूती के लिए लाया जाता है। स्पै ल इकोनोमिक जोन क्योंकि व्यापारी से भी, उपभोक्ता से भी और हरियाणा प्रदे 1 के आम नागरिक से भी जुड़ा हुआ है इसलिए सरलीकरण के साथ-साथ इसको मजबूती से भी लागू करना होता है और इसके लिए यह जरूरी है कि सं गोधन किए जाएं और ऐसे सं गोधन किए जाएं कि कहीं भी पावर्ज को एक हाथ में न लिया जाए that should be decentralized. इनको डिसेंट्रलाईज भी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस सं गोधन के बारे में मेरा एक सुझाव है कि जो परियोजना अनुमोदन समिति का गठन किया गया है उसके जितने भी मैम्बर्ज हैं वे सारे के सारे सरकारी अधिकारी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे दे 1 में और प्रदे 1 में ऐसे अनुभवी लोगों की कमी नहीं है और वे स्पै ल इकोनोमिक जोन के बारे में अच्छी जानकारी दे सकते हैं, अच्छी राय दे सकते हैं, अच्छा म ाविरा दे सकते हैं। इसलिए इस समिति में दो चार ऐसे लोग भी होने

चाहिए थे जिनको अनुभव हो, जो स्पै गलाइज्ड हों, जो व्यापारियों से जुड़े हुए लोग हों, जो मीनरी से जुड़े हुए लोग हों या कोई और ऐसे लोग हों जो इससे जुड़े हुए हों। इस तरह के दो चार लोग इस समिति में जरूर होने चाहिए थे। जिस तरह से समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुमोदन करके सरकार को भेजे, ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करके एक पड़ाव डाल दिया गया है अध्यक्ष महोदय, होना यह चाहिए था कि एक समयबद्ध एस०ई०जैड० का प्रोग्राम होना चाहिए था। नहीं बना तो किसान की वह जमीन खाली ही रहेगी। वह एस०ई०जैड० का यदि पांच-पांच साल तक उस पर एस०ई०जैड० नहीं बना तो किसान की वह जमीन खाली ही रहेगी। वह जमीन न तो किसान के काम आएगी और न व्यापारी के काम आएगी। जिस तरह से हुडा द्वारा मकानों को बनाने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया जाता है उसी तरह से अगर इस बारे में समय सीमा फिक्स करते तो अच्छा रहता। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का भी संतोष लाने की जरूरत थी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और जरूरी अहम बात कहना चाहूंगा। जैसे कल को मान लो कि प्रोजैक्ट फेल हो गया, इसके कई आर्थिक कारण हो सकते हैं और अगर इस पर कोई कार्यवाही न हो तो ठीक नहीं है क्योंकि जो सरकार द्वारा अधिग्रहित की गयी जमीन की कीमत है या व्यापारी ने जो सस्ते दाम पर जमीन खरीदी है, उस जमीन की कीमत बढ़ेगी। सरकार ने जो जमीन अधिग्रहण की है वह जमीन व्यापारी बेचकर अपना घाटा पूरा करेगा लेकिन जिस तरह से किसान को वह जमीन मिली थी उससे

उसका तो नुकसान होगा। इसमें यह भी सं गोधन किया जाना चाहिए जैसे कल को कोई प्रोजैक्ट फेल हो जाता है तो या तो वह जमीन सरकार अपने पास रखे या फिर वह जमीन जिस किसान से ऐक्वायर की गई थी, उसी किसान को वापस कर दी जाए और जिस रेट पर उससे ली गई थी उसी रेट पर वापस कर दी जाए, ऐसा सं गोधन इसमें और किया जाए, यह मेरा सुझाव है। इस बारे में एक कमेटी और बनाई जाए जो कि इसे विस्तार से देखे कि जहां व्यापारी की जिम्मेदारी डालना चाहते हैं वहां व्यापारी की जिम्मेदारी डाली जाए लेकिन जहां सरकार की जिम्मेदारी बनती है वहां सरकार की जिम्मेदारी भी डाली जाए। यह मेरा सुझाव है। सरकार अगर बिजली नहीं दे पाती तो सरकार उसमें जिम्मेदार होनी चाहिए, अगर पानी समय पर नहीं दे पाती है तो सरकार भी जिम्मेदार होनी चाहिए और इसमें यह भी करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में सरकार उसकी भरपाई कैसे करेगी, यह भी बताना चाहिए। कल को यदि व्यापारी छोटा सा प्रोजैक्ट एस०ई०जैड० में लगा लेता है और बड़ा प्रोजैक्ट बाहर लगा लेता है और बाहर किए हुए प्रोजैक्ट्स को यहां दिखा देता है तो इससे सरकार को आर्थिक नुकसान होगा और रेवैन्यू कलैक्टर्स नहीं हो पाएगा। अतः इस बारे में मेरे द्वारा दिये हुए सं गोधन को भामिल करने में सरकार का फायदा है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर इंदौरा जी ने इस बिल पर अपने सुझाव दिये में दो बातें

आपकी अनुमति से सदन और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो यह अमेंडमेंट है वह एसैंि यली फौर्मल अमेंडमेंट है और जो एस०ई०जैड० ऐक्ट है, इसे इसी सदन में सर्वसम्मति से पारित करवाया था। उसके अंदर ही चीज की सीमित सीमा लिखी गई है कि इतनी अवधि के अंदर अमुक परमी न देनी है। मैंने उस दिन भी इस बारे में प्वायंटआउट किया था। पहली बार टाइम पीरियड में इसको कानूनी अमली जामा पहनाया है। जब जो मैंने बिल पढ़ा है यह सारे अगर उस पीरियड में आने होते तो automatically, it will be a deemed approval. उसमें लिखा है कि इस अमेंडमेंड ऐक्ट के दो लक्ष्य हैं। एक तो दो अलग-अलग कमेटी थी। अब इसमें एक प्रोजैक्ट इवैल्यूए न कमेटी बना दी है। इसके साथ ही एक और चिन्ता माननीय सदस्य ने जाहिर की है कि इसके अंदर केवल अधिकारीगण हैं और इसमें नैसैसरी टैक्नीकल ऐक्सपर्टीज या पौलिटिकल इन्पुट इसके अंदर होने चाहिए, नहीं तो यह कमेटी निर्णय नहीं ले पाएगी, इस बारे में मैं माननीय सदस्य की भांका का निवारण करने के लिए बताना चाहूंगा कि इसको आगे पढ़ें, Speaker Sir, this is only a Project Evaluation Committee.Finally, this will go to the Government and the Government will apply its own mind and it has right to reject, it has a right to amend and it has a other rights also. It can lay down condition one, two,three,four and further.Speaker Sir, so, this Project Evalulation Committee's report is not sacrosanct, as if can never be changed by he Government.The Government has discretion to change it.Thirdly,SpeakerSir, by amending this legislation, I want to draw Hon'ble learned

Member's attention to clause 7 of this Bill, where we have said that we have proposed to amend Clause(i) of Sub-section (1) of Section 11. इसमें पहले तो डिवैल्पर भी वैट और दूसरी चीजों का यूनिट के साथ साथ बेनीफिट ले सकता था लेकिन अब हमने उसे रूलआउट कर दिया है। अब जो यूनिट लगाएगा वह वैट का लाभ उठा सकेगा। पर डिवैल्पर नहीं उठा सकता इसलिए इसमें हम क्लॉज 7 में क्लॉज (1) ऑफ सब-सैक्शन 11 को अमैंड करके लेकर आए हैं। बाकी सभी फॉर्मल है इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह जो अमैंडिंग बिल है इसको पारित किया जाए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय दस मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। हाउस का समय दस मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

दि हरियाणा स्पैशियल इकोनोमिक जोन(अमैंडमेंट) बिल,
2008(पुनरारम्भ)

Mr.Speaker : Question is-

That Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr.Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr.Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr.Speaker : Question is-

That Clause stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr.Speaker : Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr.Speaker : Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr.Speaker : Question is-

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr.Speaker : Question is-

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Mr.Speaker : Question is-

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr.Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr.Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of Bill.

The motion was carried.

Title

Mr.Speaker : Question is-

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr.Speaker : Now, the Parllimentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister(Sh.Randeep Singh Surjewala) :
Sir. I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr.Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

**3. दि हरियाणा स्टेट लेजिस्लेचर (प्रिवें न ऑफ
डिसक्वालिफिके न)अमेंडमेंट बिल, 2008**

Mr.Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana State Legislature

(Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister(Sh.Randeep Singh Surjewala) :

Sir. I beg to introduce the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2008.

Sir, I also beg to move-

That Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

वाक-आउट

डॉ० सु गील इंदौरा(ऐलानाबाद, अनुसूचित जाति) :

अध्यक्ष महोदय, यह जो दि हरियाणा स्टेट लेजीस्लेचर (प्रिवें न ऑफ डिसक्वालिफिके न) अमैंडमैंट बिल, 2008 सदन में लाया गया है। यह व्यक्ति वि ेश को लाभ देने के लिए लाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं। मुझ उम्मीद नहीं थी क्योंकि जिस तरह से ये पारदर्िता की बात करते हैं। जिस पार्टी से ये संबंधित हैं। उसकी अध्यक्षता और यू०पी०ए० की चेयरपर्सन ने लाभ के पद पर रहते हुए रिजाईन देकर दोबारा से चुनाव लड़ा था। उस पार्टी से संबंधित होते हुए हमारे सदन के नेता आज

सदन में बिल लेकर आये हैं जिस माननीय सदस्य को हरियाणा स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमीशन का चेयरमैन बनाया है उनको लाभ देने के लिए यह बिल लाये हैं अच्छा तो यह होता कि पहले उन माननीय सदस्य से रिजार्डन करवाते और फिर उनको इस कमीशन का चेयरमैन बनाते और फिर बिल में संशोधन लाते । क्या जरूरत पड़ी थी इस अमेंडमेंट को लाने की? इस संशोधन में यह नहीं बताया गया कि क्या समय सीमा निर्धारित की गई है और जब यह खत्म हो जायेगा तो उसकी क्या जरूरत पड़ेगी ? अगर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए आपने कुछ करना है तो बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, बोर्ड बने हैं, कमीशन बने हैं, इन सबको भी इसमें ले आइये, बार-बार संशोधन लाने की क्या जरूरत है ? बहुत से चेयरमैन आपने कवर किए हुये हैं जैसे एम०आई०टी०सी० के चेयरमैन को पहले ही कवर किया हुआ है । अध्यक्ष महोदय, यह गलत हो रहा है क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए यह बिल लाया गया है ।इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं और एजेंडे प्रोटैस्ट सदन से वॉक आउट करते हैं ।

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वॉक-आउट कर गये)

दि हरियाणा स्टेट लेजिस्लेचर(प्रिवी कौंसिल ऑफ डिस्कवालिफिकेशन) अमेंडमेंट बिल, 2008(पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब ने जो बात कही है कम से कम उनको अपनी बात का जवाब तो सुनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आपने जो बात कही है उसका जवाब तो आपको सुनना चाहिए। It is your moral duty.सदन की कुछ गरिमा है। वाक आउट करने से पहले आपको जवाब तो सुनना चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी ने इल्जाम लगा दिया कि व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए सरकार ये अमेंडिंग बिल लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, वे भूल गए कि जब वे पहली बार बजट पर बोले तो यह उनकी मांग थी कि हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्मस कमीशन बनाया जाए। एक तरफ तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्मस कमीशन बनाने की मांग करते हैं और दूसरी तरफ आप उसका विरोध करते हैं। आप हैं किस तरफ। इसलिए मैंने उनसे सादर अनुरोध किया था कि कम से कम आप जवाब तो सुनते जाएं। उनकी लगातार यह मांग थी कि हरियाणा में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्मस बनाया जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी यह बात मान ली है। आज अगर ओफिस आफ प्रोफिट से उसको निकाल रहे हैं तो इसमें कोई अति योक्ति या अनहोनी बात नहीं है। इन्दौरा जी, आप भूल गए कि आपके समय में ऐसी बहुत सी अमेंडमेंट्स आई हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जिनकी बात आप कह रहे हैं, they are all included

here. आप सैक 1न 3(1) (ए) से क्लोज (के)तक पढ़कर आए होते तो आपको पता चल जाता कि इसमें बहुत सी श्रेणियां हैं जो इसके अंदर इन्क्लूड हैं। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जिसने लगातार लोकदल के साथियों के कच्चे चिट्ठे खोलने का काम किया है उस व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए यह किया गया है। पीड़ा एक व्यक्ति से है तो अलग बात है पर इसमें कोई सवैधानिक या कानूनी दिक्कत नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि संविधान के इस अमेंडिंग एक्ट को पारित कर दिया जाए।

Mr.Speaker : Question is-

That Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr.Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr.Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in clause 2. He may move amendment.

Power Minister(Sh.Randeep Singh Surjewala) :
Sir. I beg to move-

“ That in clause 2 of the Bill, after clause (I), the clause(m) may be added as follows:--

“(m) Deputy Chairman 20-Point Economic Programme.”

Mr. Speaker : Motion moved-

“ That in clause 2 of the Bill, after clause (I), the clause(m) may be added as follows:--

“(m) Deputy Chairman 20-Point Economic Programme.”

Mr.Speaker : Question is-

“ That in clause 2 of the Bill, after clause (I), the clause(m) may be added as follows:--

“(m) Deputy Chairman 20-Point Economic Programme.”

The motion was carried.

Mr.Speaker : Question is-

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr.Speaker : Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr.Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr.Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
Bill.

The motion was carried.

Title

Mr.Speaker : Question is-

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr.Speaker : Now, the Parllimentary Affairs
Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Power Minister(Sh.Randeep Singh Surjewala) :
Sir. I beg to move-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr.Speaker : Question is-

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

Mr.Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 25th March,2008.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 25th March, 2008.)